चिंतन

युद्ध नहीं शांति के मार्ग से होगा वैश्विक कल्याण

इस वक्त जब दुनिया मानवता पर संकट पैदा करने वाले युद्ध, क्षेत्रीय संघर्ष, आतंकवाद, कट्टरपंथी हिंसा, सीमा पर विवाद, हथियारों की होड़ और विनाशकारी विकास जैसे तत्वों से गुजर रही है, उसमें भारत इकलौता देश है जो शांति के मार्ग पर चलने का आह्वान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय अभिघ्नम दिवस कार्यक्रम के दौरान अपने संदेश में दुनिया से भगवान बुद्ध से सीखने, युद्ध से दूर रहने और शांति का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। यह पहली बार नहीं है, जब किसी अपने वैश्विक संबोधन में युद्ध छोड़कर शांति की राह पर चलने की अपील की है। विश्व में एक विचारधारा रही है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन और दूसरे पर आधिपत्य के लिए युद्ध की पैरवी होती रही है, लेकिन भारत अपने आदिकाल से अपनी वैचारिकता में युद्ध छोड़ शांति को अपनाने का पक्षधर रहा है। तीन वर्ष से रूस व यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, कोई भी हल नहीं निकला है, युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब भी मिले या बात की, जंग छोड़ कर वार्ता करने व शांति स्थापित करने की अपील की, ठीक वैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता में भी युद्ध त्यागने की अपील की। ऐसे ही भारत ने इजराइल से भी युद्ध छोड़ शांति कायम करने की बात कही। अभी इजराइल एकसाथ तीन मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। इजराइल हमास, हिज्बुल्ला और हूती जैसे आतंकी गुटों से जंग लड़ रहा है। आतंकवाद वैश्विक खतरा है, यह जानते हुए भी पाकिस्तान, ईरान समेत कई देश आतंकवाद को छद्म युद्ध के लिए बेजा इस्तेमाल करते रहे हैं। आतंकवाद को खाद-पानी देने में कई शक्तिशाली देश शामिल रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की पहल के बावजूद विश्व से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो पा रहा है। विश्व में जहां गरीबी, भुखमरी, बीमारी के खिलाफ सामूहिक प्रयास होना चाहिए, वहां अनेक देश आतंकवाद, हिंसा व डर के ट्रेड में शामिल हैं। भारत ने विश्व को आतंकवाद के खतरे के प्रति हमेशा आगाह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई क्षेत्रों में जारी युद्ध के बीच भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपरिहार्य बताया और दुनिया से युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनसे सीख लेने को कहा। खास बात है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले चीन जैसे कई देश सीमा पर तनाव, विस्तारवाद, वैश्विक नियमों का उल्लंघन जैसे कृत्य में शामिल हैं। भारत में विकसित बौद्ध धर्म का विश्व को महान संदेश शांति, अहिंसा और मानवता की सेवा है। आज युद्धग्रस्त, उन्मादग्रस्त, आतंकवादग्रस्त व हिंसाग्रस्त दुनिया को भगवान बुद्ध की शांति व अहिंसा की सीख की अधिक जरूरत है। भारत ने हमेशा सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना की वकालत की है, लेकिन चीन व पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों ने लगातार परेशान किया है। भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान आज अलग-थलग है, सीमा पर तनाव पैदा करने वाले चीन की विश्वसनीयता संकटग्रस्त है। 21वीं सदी में विश्व की भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते दुनिया कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरी हुई है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अमेरिका, चीन जैसे देश विश्व में शांति व मानवता की अगुवाई करें, संयुक्त राष्ट्र समेत बड़े वैश्विक मंच विश्व को युद्धमुक्त, हिंसामुक्त, डरमुक्त और आतंकवादमुक्त बनाने की दिशा में काम करें। इस प्रयास में भारत अपनी वैश्विक भूमिका के लिए सदैव तैयार है। किसी भी रूप में वैचारिक व धार्मिक कट्टरता मानवता के शत्रु हैं। मानव का विकास व कल्याण समस्याओं के हल में है।

रक्षा सौदा
डॉ. एल. एस. यादव

प्रीडेटर ड्रोन से सैन्य बल होंगे ताकतवर

> अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी 'जनरल एटामिक्स' से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस खरीद की लागत लगभग 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य चीन के साथ विवादित सीमाओं पर भारतीय सेनाओं की यौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है। प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से भारत के शत्रु देश भारत को आंखें दिखाने से डरेंगे। इन ड्रोन की शक्ति से भारत दुश्मनों के नापाक इरादों को तहस-नहस करने में आसानी से सफल होगा क्योंकि ये समुद्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और जमीनी सीमा के उस पार लक्ष्य साधने सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है।

भारत ने 15 अक्टूबर को अमेरिका के साथ ड्रोन खरीद के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजधानी दिल्ली में भारत के शीर्ष रक्षा और रणनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। इसके तहत विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग से अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी 'जनरल एटामिक्स' से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस खरीद की लागत लगभग 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य चीन के साथ विवादित सीमाओं पर भारतीय सेनाओं की यौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की केन्द्रीय समिति (सीसीएस) ने एमक्यू-9बी हंटर किलर ड्रोन की खरीद को मंजूरी प्रदान की थी। प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से भारत के शत्रु देश भारत को आंखें दिखाने से डरेंगे। इन ड्रोन की शक्ति से भारत दुश्मनों के नापाक इरादों को तहस-नहस करने में आसानी से सफल होगा क्योंकि ये समुद्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और जमीनी सीमा के उस पार लक्ष्य साधने सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत विषेश रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर मुख्य रुप से सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है। ये ड्रोन हवा से जमीन पर सटीक मार करने में अत्यन्त सक्षम हैं।

समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे तथा भारतीय वायु सेना व थल सेना को आठ-आठ स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले ये ड्रोन 35 घण्टे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं। ये चार हेलफायर मिसाइलें व 450 किलोग्राम बम ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस ड्रोन सौदे की घोषणा जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से जिस मानवरहित प्रीडेटर ड्रोन एमक्यू-9 बी का समझौता हुआ वह संसार का सबसे उन्नत श्रेणी का ड्रोन है। इस मानवरहित प्रीडेटर ड्रोन एमक्यू-9 बी के दो वर्जन हैं। पहला स्काई गार्डियन और दूसरा सी गार्डियन। एमक्यू-9 बी, सी गार्डियन ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं। ये ड्रोन कई तरह की यौद्धिक भूमिकाएं निभा सकते हैं। इस मानवरहित प्रीडेटर ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान दो फरवरी 2001 को भरी थी। यह ड्रोन थर्मोग्राफिक कैमरे और सेंसर से लैस है। इस ड्रोन में मौजूद एक कैमरा तीन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद किसी भी वाहन की नम्बर प्लेट तक को पढ़ सकता है। ऑपरेटर के आपात स्थिति में आक्रमण करने के लिए कमान्ड पर यह 1.2 सेकेन्ड में तीन किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह घातक मिसाइलों और बमों से शत्रु के ठिकानों पर आसानी से सक्षम है। मानवरहित एमक्यू-9 बी प्रीडेटर ड्रोन की लम्बाई 26 फुट यानि कि लगभग 11 मीटर है। यह 4763 किलोग्राम अधिकतम वजन के साथ उड़ान भर सकता है।

इस ड्रोन में 1769 किलोग्राम ईंधन एक बार में भरा जा सकता है। यह 1746 किलोग्राम भार का पेलोड लेकर उड़ सकता है। यह 500 फीसदी ज्यादा विस्फोटक सामग्री के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। यह चार

हेलफायर मिसाइलें, दो लेजर गाइडेड बम व 226 किलोग्राम बारूद ले जा सकता है। यह ड्रोन राडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। यह तय समय में हवा तथा पानी में गतिशील लक्ष्य को भी भेदने में अचूक है। इसके पंखों की लम्बाई तकरीबन 66 फुट है। यौद्धिक संक्रिया के समय यह पर्वतीय तथा दुर्गम हालातों में 50000 फुट की ऊंचाई तक सुरक्षित उड़ान भरकर शत्रु को नेस्तनाबूद कर सकता है। अमेरिका की वायु सेना ने वर्ष 2008 में अफगानिस्तान युद्ध के समय 230 किलोग्राम भार वाले बम से दुश्मन के 16 ठिकानों को एक ही उड़ान में ध्वस्त कर दिया था।

इसी तरह 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर एमक्यू-9 बी प्रीडेटर ड्रोन की मदद से अमेरिका ने मिसाइल हमले में ईरानी कुर्द फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी पापुलर मैक्लिइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मंहदी अल-मुहाजिस को मार गिराया था। एमक्यू-9 बी ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। यह चार मिसाइलों को एक साथ दागने में सक्षम है। इसकी खासियत यह भी है कि यह एक बार उड़ान भरने के बाद आसानी के साथ 1900 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है। चीन के साथ-साथ हिन्द महासागर क्षेत्र में सीमा की निगरानी के लिए भारत को ऐसे ही ताकतवर ड्रोनों की महती आवश्यकता है। दरअसल चीन ने हिन्द महासागर के अलावा कई समुद्री इलाकों में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। चीन अपने जासूसी जहाजों के साथ-साथ उपग्रहों, रॉकेटों और बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत को इन ड्रोन की विशेष जरूरत थी। अब इनके मिलने से भारत की ताकत पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगी और समय रहते बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकेगा। यह ड्रोन एमक्यू-9 रीपर का दूसरा वर्जन है। इसका इस्तेमाल काबुल में हेलफायर मिसाइल के एक मोडिफाइड वर्जन को दागने के लिए किया गया था। इसमें अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई थी।

प्रीडेटर ड्रोन एमक्यू-9 बी सी गार्डियन का इस्तेमाल क्वाड समूह के सदस्य चारों देश करते हैं। वर्तमान में भारत एक खुफिया एक्जीकरण अभियान के हिस्से के रूप में एमक्यू-9 बी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि इसे मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज तथा बचाव एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी उपयोग में लाया जा सकता है। एमक्यू-9 बी सी गार्डियन ड्रोन में एक इन-बिल्ट वाइड-एरिया समुद्री राडार, एक स्वचालित पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय और एक स्व-निहित एंटी सबमरीन वारफेयर ; एएसडब्लू किट लगी है। दुश्मन क्षेत्र के ठिकानों पर एकदम सटीक निशाना लगाने वाला यह ड्रोन इंटर-किलर यूएवी के नाम से प्रसिद्ध है। पानी की सतह के उपर और अन्दर दोनों ही प्रकार की जगहों की निगरानी व छानबीन के लिए इसमें 80 से ज्यादा जी-साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वह डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के माध्यम से पानी के भीतर हो रही आवाजों की पहचान करता है। इनकी मदद से प्रीडेटर ड्रोन गहरे पानी में छिपी हुई शत्रु की पनडुब्बियों को आसानी से खोज लेता है और उसके बाद मिसाइलों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देता है। इन खूबियों वाले ड्रोन से भारतीय सेनाएं काफी ताकतवर हो जाएंगी। गौरतलब है कि इस डील से भारत केवल अपने सैन्य तंत्र को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि यह अमेरिका के साथ उसके सामरिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। अमेरिका से यह रक्षा सहयोग भारत को वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में उभरने में मदद करेगा। वहीं भारत को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच मिलेगी, जो दीर्घकालिक रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

(लेखक जैन विद्यापीठ के छात्रावास रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विमर्श

डॉ. ज्योत्सना शर्मा

शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक कदम

पिछले दिनों 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी है। इससे पूर्व तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िसा भाषा को यह दर्जा प्राप्त है। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था जिसमें सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसी के साथ ही किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारित किए गए जो निम्नलिखित हैं:-(क) इसके आरंभिक में अभिलेखित इतिहास की 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में उच्च पुरातनता। (ख)प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक संघ है जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। (ग) साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो। (घ) शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक दौर से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है।

इसी क्रम में साहित्य अकादमी के अधीन भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने उपरोक्त मानदंडों को संशोधित किया जो इस प्रकार है कि इसकी उच्च पुरातनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में आरंभिक ग्रंथ/अभिलेखित इतिहास की है। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। ज्ञान से संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ। शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं। भारत की भाषायी विविधता को विशिष्ट पहचान देने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं तथा शास्त्रीय भाषाओं को विशेष रूप से बढ़ावा देने की दिशा में अत्यंत सार्थक कदम उठाए हैं। संसद अधिनियम के माध्यम से तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना इनमें से प्रमुख है। साथ ही शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़,तेलुगू ,मलयालम और ओड़िया भाषाओं के लिए मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तत्वावधान में उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित किए गए थे। प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक की मदद से प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण, संग्रह, प्रकाशन आदि पर भी लगातार काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि आज के बदलते परिवेश में यदि हम अपनी प्राचीन विरासत को शिक्षा के माध्यम से समझाएंगे तो उसके लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। हर विश्वविद्यालय में अनुवाद संबंधी केंद्र खोले जाने चाहिए जिनमें इन सभी भाषाओं में लिखे साहित्य का निरंतर अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो। इस प्रकार सभी भारतवासी सामाजिक संस्कृति से परिचित होंगे। सभी विद्यालयों में भी संबंधित राज्यों में बोले जाने वाली प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्रों में अपनी भाषा के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो सके। वह अपने साहित्य को जान सके और इस परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु अपनी भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर सके। ऐसे सभी सार्थक प्रयासों से हम अपनी भाषाओं को लुप्त होने से बचा सकेंगे। यदि हम अपनी भाषाओं में संशोधन करेंगे तो वह संप्रेषण अति स्पष्ट होगा, नए-नए विचार हमारे समक्ष आएंगे जिन्हें क्रियान्वित करना सरल होगा। नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा संवाद से विभिन्न दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का विकास होगा। जब संवाद स्पष्ट होंगे तो निर्णय भी सही लिए जाने की संभावना बढ़ जाती है और किसी भी समस्या के निपटान के लिए हल प्राप्त किया जा सकेंगे। अपनी भाषा बोलने वाला हर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और अच्छे से यह जानता और समझता है कि वह स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इसका सबसे अधिक असर हमारे भारत के सभी गांवों में देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, जहां बड़े अधिकारी जब गांव के लोगों से संवाद करेंगे तो भली-भांति उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे और उनकी समस्याओं का निदान ठीक प्रकार से करेंगे। जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा में सही प्रयास करने की, जिससे हम अपने छात्रों को भाषा के ध्वजवाहक के रूप में अग्रसर कर सकें।

(लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

भावनाएं आपकी दोस्त भी और दुश्मन भी

संकलित
दर्शन

जब आपकी भावनाएं सकारात्मक होती हैं, तो आप सत्य के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं लेकिन वही भावनाएं, जब वे उग्र होती हैं, तो आपके मन और शरीर को बर्बाद कर देती हैं। भावनाएं आपकी दुश्मन हैं और साथ ही आपकी दोस्त भी हैं। जो भावना आपको अंदर से इतना कोमल बनाती है, वह आपकी दोस्त है और जो आपको उग्र बनाती है, वह आपकी दुश्मन है...। हालांकि हम शारीरिक रूप से बड़े हो गए हैं, लेकिन हम भावनात्मक रूप से बड़े नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी भावनाओं के शिकार हैं। ओह! मुझे ऐसा लगता है! मुझे वैसा लगता है! क्या करूं? लेकिन आपकी भावनाओं के बारे में बड़ी बात क्या है? वे कल भी वहां थे और फिर से आपके स्थान पर आ गए तो क्या हुआ कभी-कभी आप आसमान में काले बादल देखते हैं, लेकिन स्थान उनका मालिक नहीं होता। वह बस उन्हें आने और जाने देता है। इसी तरह ये भावनाएं आती हैं, कभी सुखद, कभी अप्रिय। आपको उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यह पहला कदम है उन्हें आने और जाने दें। सभी भावनाएं लोगों, वस्तुओं और घटनाओं से जुड़ी होती हैं। वस्तुओं, लोगों या रिश्तों को पकड़ना स्वतंत्रता, मुक्ति में बाधा डालता है। बस जांच करें कि आपका मनोबल क्यों गिरता है? ज्यादातर मामलों में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी ने आपसे कुछ बुरा कहा। क्योंकि उनके पास कुछ कचरा था और उन्हें उसे फेंकना था और आप वहां थे, उसे पकड़ने के लिए तैयार। और एक बार जब आपने उसे पकड़ लिया, तो आप उसे बहुत जोश से पकड़े रहे! जागो!

मनुष्य का व्यवहार अप्रत्याशित व अनिश्चित

संकलित
प्रेरणा

मनुष्य एक अकेली प्रजाति है, जिसका आहार अनिश्चित है अन्य सभी जानवरों का आहार निश्चित है। उनकी बुनियादी शारीरिक जरूरतें और उनका स्वभाव फैसला करता है कि वे क्या खाते हैं और क्या नहीं, कब खाते हैं और कब उन्हें नहीं खाना होता है किंतु मनुष्य का व्यवहार बिलकुल अप्रत्याशित है, वह बिलकुल अनिश्चितता में जीता है। न ही तो उसकी प्रकृति उसे बताती है कि उसे कब खाना चाहिए, न उसकी जागरूकता बताती है कि कितना खाना चाहिए और न ही उसकी समझ फैसला कर पाती है कि उसे कब खाना बंद करना है। अब जब इनमें से कोई भी गुण निश्चित नहीं है तो मनुष्य का जीवन बड़ी अनिश्चित दिशा में चला गया है लेकिन अगर मनुष्य थोड़ी सी भी समझदारी दिखाए, अगर थोड़ी सी बुद्धि से जीने लगे, थोड़ी सी विचारशीलता के साथ, थोड़ी सी अपनी आंखें खोल ले, तो सही आहार का निर्णय लेना बिलकुल कठिन नहीं होगा। यह बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। सही आहार को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली बात: मनुष्य क्या खाए और क्या न खाए? मनुष्य का शरीर रासायनिक तत्वों से बना है, शरीर की पूरी प्रक्रिया रासायनिक है। अगर मनुष्य के शरीर में शराब डाल दी जाए, तो उसका शरीर पूरी तरह उस रसायन के प्रभाव में आ जाएगा, यह नशे के प्रभाव में आ कर बेहोश हो जाएगा। कितना भी स्वस्थ, कितना भी शांत मनुष्य क्यों न हो, नशे का रसायन उसके शरीर को प्रभावित करेगा।

अंतर्मन

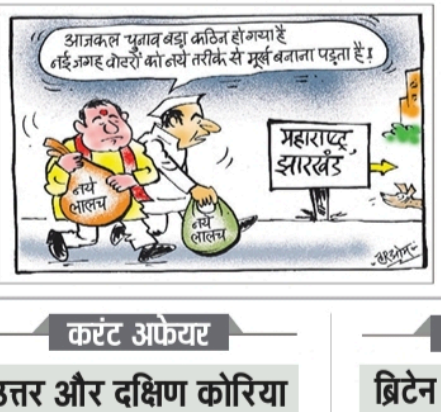

आज की पाती

स्वामी विवेकानंद जी का एकता का मंत्र

हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं। उन्होंने दुनिया को नेक राह पर चलने की शिक्षा दी है। इसके लिए दुनिया का मार्गदर्शन भी किया है। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसे आज भी याद किया जाता है और इस पर आज भी दुनिया को बहुत ज्यादा अमल करने की जरूरत है। स्वामी जी का वो भाषण वहां उपस्थित लोगों को इतना पसंद आया था कि उन लोगों ने लगभग 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाई थीं। वैसे तो स्वामी जी ने उस भाषण में बहुत सी बातें कही थी, लेकिन विश्व में एकता का जो संदेश उन्होंने दिया, उस पर आज भी विश्व को चलने की जरूरत है।

- विजय कुमार साहू

ट्रेंड

हमें मिला सौभाग्य

पाली सहित हमारी हर भाषा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनको सशक्त का माध्यम बन रही है। मुझे खुशी है कि जिस पाली भाषा ने भगवान बुद्ध की शिक्षा/विरासत को विश्व को मिली है, उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का सौभाग्य हमें मिला है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कोटि-कोटि नमन

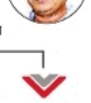

जीवनदर्शन के प्रेरक स्वतंत्रता महाव्रत के स्थापित आदिपुरी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। वाल्मीकि जी की रचना सदैव समाज में समरसता और राष्ट्रभाव के लिए प्रेरित करती रहेगी।

-अरविन्द केजरीवाल, आप प्रमुख

वैश्विक बायोटेक हब

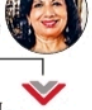

बायोटेक उद्योग में ताकी लाने वाले देश के बेंगलुरु और हैदराबाद शहरों को शीर्ष वैश्विक बायोटेक हब के रूप में देखना अच्छा लगता है।

-किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

माधुरी एक किंवदंती

किसी लावण्यमय अभिनेता को माधुरी दीक्षित जैसी सोहना दरसे काली नहीं देखा। पता था कि वह सौंदर्य की नहीं लालना के कारण दर्शकों तक स्टार बनी रहेगी, जिसके वह स्वयं दावेदार है। आज वह एक किंवदंती है

-सुभाष घई, फिल्मकार

करंट अफेयर

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ी टेंशन

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सालों से चल रहा तनाव अब और भी गहराता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल में संशोधित किए गए अपने संविधान में दक्षिण कोरिया को पहली बार 'शत्रु राष्ट्र' के रूप में परिभाषित किया है। उत्तर कोरिया ने इस बात की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया की संसद ने देश के संविधान में परिवर्तन करने के लिए पिछले सप्ताह दो दिन तक बैठक की थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने जनवरी में दक्षिण कोरिया को देश का मुख्य शत्रु घोषित करने, शांतिपूर्ण कोरियाई एकीकरण के लक्ष्य को खत्म करने और उत्तर कोरिया की संप्रभुता और क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संविधान में बदलाव का आह्वान किया था। उत्तर कोरिया ने घोषणा की कि 1.4 मिलियन से अधिक नागरिकों ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। यह घोषणा दक्षिण कोरिया द्वारा पिछले हफ्ते सीमा पार प्यौंगयांग विरोधी प्रचार पत्रों के साथ ड्रोन भेजने के जवाब में अपनी दक्षिणी सीमा पर सड़कों और रेलवे लाइनों के एक हिस्से को उड़ाने के एक दिन बाद की गई है। संविधान में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को 'शत्रु राष्ट्र' के रूप में परिभाषित किया। हाल में उत्तर कोरिया ने उन सड़कों और रेल संपर्क सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया जो अब उपयोग में नहीं हैं और जो कभी उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती थीं।

ऑफ बीट

ब्रिटेन में 400 साल पुराने समुद्री जहाज की खोज शुरू

ट्रेजर हंट गेम के बारे में आपने जरूर सुना होगा और कुछ ने तो यह गेम खेला भी होगा। इसके अलावा कई फिल्में भी ट्रेजर हंट यानि खजाने की खोज पर आधारित हैं। अब इससे जुड़ा एक असल मामला सामने आया है। दरअसल, ब्रिटेन की एक कंपनी लगभग 383 साल पहले कॉर्नवाल के तट पर डूबे अंग्रेजी के एक समुद्री जहाज को ढूंढने का प्रयास कर रही है, जिसमें 421 अरब रुपये का सोना होने की संभावना है। इस अंग्रेजी जहाज का नाम मर्वट रॉयल है, जिसे 'एल डोराडो ऑफ द सीज' के नाम से जाना जाता है और इसमें अरबों रुपये का सोना और अन्य कीमती वस्तुएं होने का अनुमान है। कई कंपनियां और लोग इसकी खोज में असफल रहे हैं, लेकिन मल्टीबीम सर्विसेज नामक कंपनी का दावा है कि वह इस जहाज को ढूंढ लेगी। इसके लिए कंपनी पानी के नीचे चलने वाले मानवरहित जहाजों और कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। कंपनी के अधिकारी निगेल हॉल ने खोज के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी खोजे गए खजाने को विरासत कलाकृति माना जाएगा। उन्होंने मेट्रो को बताया कि उनकी खोज सोने के लिए ही नहीं है, बल्कि जहाज का मलबा ही अपने आप में बेशकीमती है, जिसकी कीमत अरबों रुपये हो सकती है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

हास्य, विनम्रता और ईमानदारी निस्संदेह ये सब सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक कूटनीति में काम करती हैं। -सिंथिया पी. श्नाइडर

एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट का यह कहना बेहद चिंतनीय है कि बढ़ते जल संकट से दुनिया के आधे से अधिक खाद्य भंडारों पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में, जल संसाधनों के संरक्षण, पुनर्चक्रण और उनके उचित प्रबंधन के साथ आधुनिकतम तकनीकें व दीर्घकालीन नीतियां ही स्थायी समाधान ला सकती हैं।

जल संकट का दायरा

जल संकट को अब तक पर्यावरणीय चिंताओं का विषय माना जाता था, लेकिन ग्लोबल कमीशन ऑन द इकनॉमिक्स ऑफ वाटर की ताजा रिपोर्ट का यह कहना वाकई डराने वाला है कि यह संकट जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे दुनिया के आधे से अधिक खाद्य भंडार पर खतरा मंडराने लगा है। जाहिर है कि अब यह पर्यावरण के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह जानकारी भी देती है कि 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके कारण औसतन आठ फीसदी का, जबकि निम्न आय वाले देशों को पंद्रह फीसदी तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरी दुनिया में जल संकट का यह परिदृश्य चिंतित करने वाला है। दरअसल, बढ़ती आबादी की मांग के चलते जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है। इसके अतिरिक्त जलवायु में आ रहे बदलाव भी इस समस्या को गंभीर बना रहे हैं। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह अब सामान्य बात हो चली है, उससे जल संसाधनों की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है। जिन क्षेत्रों में पहले से जल की कमी थी, वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखला को कमजोर बना रहा है। इसकी पुष्टि उक्त रिपोर्ट से भी होती है, जिसके अनुसार, दुनिया के करीब तीन अरब लोग और आधे से अधिक खाद्य उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां जल की उपलब्धता कम है या अस्थिर है। समस्या का सबसे भयावह पक्ष यह है कि मनुष्य के लंबे इतिहास में यह पहली बार है, जब हम वैश्विक जल चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण में एक प्रमुख मूल्य जल का होता है। दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में जल प्रबंधन के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वे जल के इसी मूल्य की भूमिका की अनदेखी की वजह से नाकामयाब हो रहे हैं। जाहिर है, जल संकट पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वर्षों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे में, जल संसाधनों का संरक्षण, पुनर्चक्रण और उनका उचित प्रबंधन तो जरूरी है ही, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीतियों, सिंचाई के आधुनिकतम तकनीकी समाधानों को अपनाने के साथ किसानों को कृषि की अधिक जल-प्रभावी तकनीकों की ओर प्रेरित करना चाहिए। जल उपयोग की आदतों पर पुनर्विचार करना भी जरूरी है, क्योंकि संकट के समाधान में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उम्मीद पर दुनिया कायम है

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की इसलिए आलोचना हो रही है कि उन्होंने एससीओ के उद्घाटन भाषण में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख क्यों नहीं किया। दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जोर दिया कि आतंकवाद जैसे मुद्दों का समाधान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

एक बार विदेश में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में एक सार्क देश के वरिष्ठ विदेशी प्रतिनिधि ने मुझसे शिकायत की कि जब भी सार्क शिखर सम्मेलन होता है, तो इसे पाकिस्तान और भारत द्वारा 'हाईजैक' कर लिया जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें, खासकर मीडिया की, इन्हीं दोनों पड़ोसी देशों पर टिकी होती हैं और अन्य सार्क देशों की नजर अंदाज कर दिया जाता है!

यह बात इस बार भी सही साबित हुई, जब पहली बार यह खबर पाकिस्तान पहुंची कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। मीडिया में इस बात को लेकर काफी उत्साह था, क्योंकि करीब एक दशक बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहा था। इससे पहले दिवंगत सुषमा स्वराज 2015 में इस्लामाबाद आई थीं। मुझे याद है कि दिवंगत सुषमा स्वराज के साथ मेरी मुलाकात हमेशा सुखद होती थी, क्योंकि वह उर्दू कविताओं की बहुत अच्छी जानकार थीं और अतीत के महान उर्दू शायरों की कविताएं सुनाती थीं। वास्तव में एस. जयशंकर तब उनके विदेश सचिव थे और उनके साथ यहां आए थे। हालांकि पाकिस्तान में इस बात को लेकर थोड़ा संदेह था कि हाल ही में भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद के बाद जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं। इन सबके बावजूद उनका पाकिस्तान पहुंचना इस बात का बहुत मजबूत संदेश था कि भारत एससीओ की बैठक को कितना महत्वपूर्ण मानता है।

भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान आने से कुछ दिन पहले से ही अखबारों में लेख छपने लगे थे, जिनमें से कुछ में उन्हें संबोधित करते हुए भारत-पाकिस्तान संबंधों के भविष्य पर चर्चा की गई थी और कहा गया था कि भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होना चाहिए। यही बात प्रमुख अखबारों के संपादकीयों में भी दिखाई पड़ी, जिनमें दोनों देशों से भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा का लाभ उठाने के लिए कहा गया। लेकिन दोनों देशों ने यह साफ कर दिया कि यह द्विपक्षीय यात्रा नहीं है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। कई विशेषज्ञों ने भी जयशंकर के लिए संदेश दिए, जिनका मानना था कि कम से कम कुछ मुद्दों पर, जो इस महाद्वीप के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बातचीत होनी चाहिए। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने प्रस्ताव दिया कि पराली जलाने, धुआं और प्रदूषण, जो दोनों मुल्कों के पंजाब को एक ही मौसम में प्रभावित करते हैं, ऐसा मुद्दा है, जिस पर दोनों मुल्क तालमेल बना सकते हैं। विश्व बैंक के मुताबिक, दोनों मुल्कों के 1.5 अरब लोग अत्यधिक प्रदूषण से पीड़ित हैं।

एक अन्य प्रस्ताव यह था कि पाकिस्तान, जो अभी तक पोलियो से मुक्त नहीं हो पाया है तथा अकेले इस वर्ष वहां इसके 30 से अधिक मामले सामने आए हैं, वह भारत के अच्छे कार्यों से सीख सकता है, जिसने देश से पोलियो को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इससे भारत के प्रति पाकिस्तानियों की दिलचस्पी का पता चलता है। अन्य देशों के प्रतिनिधियों में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इसका प्रमुख कारण है कि अन्य एससीओ देशों के साथ पाकिस्तान का कोई लंबित मुद्दा नहीं है और किसी अन्य एससीओ देशों के साथ राजनयिक संबंध इतने खराब नहीं हैं। इन दोनों देशों का अभी न तो इस्लामाबाद और न ही नई दिल्ली में कोई स्थायी उच्चायुक्त है। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने कई प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य आए थे, लेकिन कैमरा और मीडिया की दिलचस्पी केवल भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर में ही थी और यह समाचारों के कवरेज में भी दिखा।

अतिथियों के साथ विभिन्न देशों से मीडिया की बड़ी टीमें आई थीं, लेकिन केवल भारतीय पत्रकारों की ही पूछ थी। इसका कारण यह था कि दोनों देशों का मीडिया अपने देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करने और उन पर बहस करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित था। एस. जयशंकर और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बैठकों के नतीजों को देखें, तो यह बहुत सकारात्मक और निश्चित रूप से अच्छा था। इस्लामाबाद में जब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित औपचारिक रात्रिभोज के लिए गए, तो लाइव कवरेज में शरीफ को गर्मजोशी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए दिखाया गया और अगली सुबह सम्मेलन के शुरू होने पर भी ऐसा ही हुआ, जब दोनों राजनेताओं ने कुछ गुफ्तगू की। सूत्रों के मुताबिक जब नेता लाउंज एरिया में मिले, तो जयशंकर ने कई पाकिस्तानी राजनेताओं से बातें भी कीं। रात्रिभोज के समय भी वह उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बगल में बैठे थे और खाते हुए एक-दूसरे से बातें कर रहे थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री को उनके आतिथ्य और सौजन्यता के लिए टवीट करके धन्यवाद देने भर से दोनों मुल्कों के बीच जारी गतिरोध में कोई बदलाव नहीं आया।

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि उन्होंने उद्घाटन भाषण में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख क्यों नहीं किया। सम्मेलन में अपने भाषण में जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत के रुख को दोहराया। उन्होंने पड़ोसियों के बीच ईमानदार बातचीत की ओर इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों का समाधान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि सम्मेलन में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था, जिसने एससीओ घोषणापत्र पर प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के समय चीन की वन बेल्ट ऐंड वन रोड परियोजना का समर्थन करने से इन्कार कर दिया था। मुझे लगता है कि यदि दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छाशक्ति है और यदि भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा को वास्तव में सकारात्मक माना जा सकता है, तो द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने का सबसे आसान तरीका दोनों उच्चायुक्तों और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों की वापसी होगी। दोनों मुल्कों के अरबों नागरिक दोनों देशों के राजनीतिक मतभेदों के बंधक नहीं रह सकते। अब समय आ गया है कि दोनों मुल्क आपस में बातचीत शुरू करें।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

फ्रैंज काफ्का

हर बार की तरह मैं आपके प्रश्न का तत्काल कोई उत्तर नहीं सोच पाया। मैं वास्तव में आपसे बहुत प्रेम करता हूं। पिता जी, आपने मुझे चलना सिखाया और बताया कि रास्ते चलने से ही बनते हैं।

पिता जी, मैं आपसे क्यों डरता हूं

एक दिन रात को मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसी क्षण मुझे पिता की याद आने लगी। कुछ वर्ष पहले मैंने एक पत्र अपने पिता को लिखा था। आदरणीय पिता जी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे क्यों डरता हूं। मैं लिखने के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं, इन शब्दों में मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं एक चिंतित बच्चा था, और फिर भी मुझे यकीन है कि आपने और मां ने मुझे भी लाड़-प्यार किया। आपने जीवन की समस्याओं में गोता लगाने और गहराई में डूबने और तैरकर निकलने की हिम्मत सिखाई, ताकि बाद में फिर से उठकर हंसते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहूं।

हर बार की तरह मैं आपके प्रश्न का तत्काल कोई उत्तर नहीं सोच पाया। मैं वास्तव में आपसे बहुत प्रेम करता हूं। पिता जी, आपने मुझे चलना सिखाया और बताया कि रास्ते चलने से बनते हैं। और तब से मैं दुनिया को बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि मैं इसका आविष्कार करता हूं। मैंने आपसे एक चीज सीखी है कि मैं आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें खुद को निगल जाने देता हूं। एक निश्चित बिंदु से आगे कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। यही वह बिंदु है, जिस तक पहुंचना ही चाहिए। किसी बाधा की तलाश में अपना समय बर्बाद नहीं करता, हो सकता है कि कोई बाधा ही न हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति केवल विपरीत दिशा में जान-बूझकर छलांग लगाकर ही हासिल कर सकता है।

आपने एक दिन कहा था कि झुको नहीं, कमजोर मत बनो और फैशन के हिसाब से अपनी आत्मा को संपादित मत करो। आपने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की। हमारे लिए आपने सबकुछ त्याग दिया, खासकर मेरे लिए, और आज उसी का परिणाम है कि मैं उच्च और सुंदर जीवन जी रहा हूं, जो कुछ भी मैं सीखना चाहता था, उस सपने को पूरा करने के लिए आपने हर तरह की आजादी दी। मैं आपसे क्यों डरता हूं, यह आपको नहीं समझा सकता। मैं किसी को भी नहीं समझा सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं खुद को भी यह नहीं समझा सकता। सारी भाषाएं कमजोर पड़ गई हैं। मैं लगातार कुछ ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो शब्दों से बताया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझ से परे है, कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं सिर्फ अपनी हड्डियों में महसूस करता हूं और जिसे सिर्फ उन हड्डियों में ही अनुभव किया जा सकता है। मैं थक गया हूं, कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं और बस मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं। बचपन की तरह आपके हाथ पकड़कर चलना चाहता हूं और हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूं। (महान लेखक और उपन्यासकार द्वारा 1919 में अपने पिता के नाम लिखे पत्र के संपादित अंश।)

खुशी तलाशने से नहीं मिलती

सूत्र

जो आपके पास है, उससे खुश रहें और जो आप चाहते हैं, उसके लिए काम करते रहें। आप अपने काम से खुश हैं, तो आप खुद को पसंद करेंगे, आपको आंतरिक शांति मिलेगी। जो लोग खुशी की तलाश नहीं कर रहे हैं, उन्हें खुशी मिलने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि जो लोग खोज रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि खुश रहने का सबसे पक्का तरीका दूसरों के लिए खुशी की तलाश करना है।

दूसरा पहलू

अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए लाखों प्रवासियों को बुलाने वाला कनाडा अब उनके लिए सख्त नीति बना रहा है।

अब प्रवासियों का स्वर्ग नहीं है कनाडा

अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से लाखों प्रवासियों को अपने यहां बुलाने वाले देश कनाडा ने अब अपनी प्रवासन नीति को सख्त बनाने का फैसला किया है, क्योंकि प्रवासियों की भीड़ से उसके यहां आवासन, स्वास्थ्य सेवा और दूसरे क्षेत्रों में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। विदेशी छात्र जो कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें यहां रहने के लिए वर्क परमिट मिलता है। अस्थायी तौर पर कनाडा में रहने वाले प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह यही होते हैं। दूसरे समूह में वे होते हैं, जिन्हें कनाडा की कंपनियां काम करने के लिए बुलाती हैं, प्रवासियों के तीसरे समूह में वे हैं, जो यहां शरण मांगने के लिए आते हैं।

दरअसल कोविड के बाद जब कनाडा श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहा था, तब उसने टेंपरेरी रेजिडेंस प्रोग्राम को गति दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी आएं। नतीजतन कनाडा में टेंपरेरी रेजिडेंस का दर्जा पाए प्रवासियों का आंकड़ा 30 लाख तक पहुंच चुका है। इनमें से 22 लाख प्रवासी तो पिछले दो साल में कनाडा आए हैं। प्रवासियों का दबाव कनाडा किस तरह झेल रहा है, इसका पता इससे चलता है कि टेंपरेरी रेजिडेंस का दर्जा पाने वाले प्रवासी अभी देश की कुल आबादी का 6.8 फीसदी हैं, जबकि 2022 में ये प्रवासी कुल आबादी का 3.5 प्रतिशत थे। वैसे भी कनाडा उन देशों में है, जो कोविड के पहले भी प्रवासियों का स्वागत करता रहा है। लेकिन प्रवासियों की बढ़ती संख्या से कनाडा के कई शहरों में आवासन संकट गहरा गया है, तो कई प्रांतों में स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था चरमरा रही है। आलोचकों का कहना है कि प्रवासियों की बढ़ती भीड़ के कारण कनाडा में यह स्थिति आई है। विगत अगस्त में हुए एक सर्वेक्षण में देश के दो तिहाई नागरिकों ने यह माना कि सरकारी नीति के कारण बहुत कम समय में भारी संख्या में प्रवासी देश में आ गए हैं, जिससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं।

मैटिना स्टेविस-गिडनेफ

आस्थायी प्रवासी अभी कनाडा की कुल आबादी का 6.8 फीसदी हैं, जबकि 2022 में ये प्रवासी कुल आबादी का 3.5 प्रतिशत थे।

कनाडा की सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही स्टूडेंट वीजा की संख्या घटा दी है। इसके अलावा कानून बना दिया है कि कंपनियां तय संख्या से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को अपने यहां काम के लिए नहीं बुला सकतीं।

तमाम चुनौतियों को देखते हुए कनाडा की सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही स्टूडेंट वीजा जारी करने की संख्या घटा दी है। इसके अलावा उसने यह भी कानून बना दिया है कि कंपनियां तय संख्या से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को यहां काम के लिए नहीं बुला सकतीं। ऐसे ही, जिन प्रवासियों का वर्क परमिट खत्म हो रहा है, उसके नवीकरण में भी सख्ती बरती जा रही है। गौर करने की बात यह है कि प्रवासियों के प्रति कनाडा जैसा रवैया अमेरिका और यूरोप में भी देखा जा रहा है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

वस्तु व्यापार

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के देशों में भारत ने वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा वस्तु व्यापार चीन और रूस के साथ किया।

चीन	10.61%
रूस	5.87%
ईरान	0.17%
पाकिस्तान	0.11%
उज्बेकिस्तान	0.04%

आंकड़े देशों के साथ वस्तु व्यापार के, प्रतिशत में | स्रोत : MoC&I

संत अप्पार ने बहन के कहने पर मधुर आवाज में भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी आवाज में सरस्वती का वास होगा।

संत अप्पार की भक्ति

अंतर्यात्रा
संकलित

संत अप्पार जब छोटे थे, तभी उनके माता-पिता का निधन हो गया। बड़ी बहन ने ही उनका पालन-पोषण किया। एक बार संत अप्पार को बहुत भयंकर पीड़ा हुई। बहन के कहने पर शिव मंदिर में जाकर मधुर आवाज में प्रार्थना की और भगवान की कृपा से उनका दर्द मिट गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी वाणी में सरस्वती बसेगी।

इसके बाद बहन के कहने पर संत अप्पार भगवान की भक्ति करने लगे। वह हर दिन अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करने लगे। एक बार की बात है, जब पल्लव नरेश उन्हें दूसरे धर्म में दीक्षित करना चाहते थे। इन्कार करने पर राजा ने संत अप्पार को कई प्रकार के कष्ट दिए। एक बार संत अप्पार की गर्दन में पत्थर बांधकर नदी में छोड़ दिया, लेकिन वह पत्थर जल पर तैरने लगा। और इस प्रकार वह अपने धर्म पर हमेशा अटल रहे। चिदंबरम के संत संबंध ने सबसे पहले उनको अप्पार (पिता) कहकर पुकारा। तभी से वह संत अप्पार के नाम से विख्यात हुए। तिरुपणलूर में संत अप्पार को हर तरह का आर्थिक प्रलोभन मिला, लेकिन उन्होंने इन चीजों के प्रति अपने हृदय में कोई स्थान नहीं रखा। वह बड़ी सरलता से जीवन जीते थे। जीवन के अंतिम दिनों में भी वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते और आतुर होकर प्रार्थना करते कि उन्हें अपने पास बुला लो। यह प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की और वह परमात्मा में लीन हो गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 18 जनवरी, 1961

सच्ची शिक्षा की कसौटी उसकी व्यावहारिकता

सच्ची शिक्षा की कसौटी उसकी व्यवहारिकता

राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बलवंत विद्यापीठ के कार्यक्रम में कहा कि सच्ची शिक्षा की कसौटी उसकी व्यावहारिकता है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार तेजी से किया जाए।

जम्मू-कश्मीर में बदलाव का सवेरा

शेख अब्दुल्ला के दबाव में नेहरू द्वारा संविधान में शामिल कराए गए अनुच्छेद 370 और 35ए ने राज्य की प्रगति के दरवाजे बंद कर दिए थे।

शिवदान सिंह | मुद्दा

अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में फारूख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) लगातार कश्मीर घाटी के निवासियों के सामने अनुच्छेद 370 का हटाना इस प्रकार दिखा रही हैं, जैसे केंद्र सरकार ने इस राज्य को गुलाम बना लिया हो। लेकिन पूरे राज्य के निवासी अनुच्छेद 370 की सच्चाई को पहचान गए हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेकर प्रदर्शित कर दिया है। इसलिए अनुच्छेद 370 की सच्चाई देश के सामने लाना आवश्यक है।

आजादी के समय संयुक्त भारत में कुल 544 रियासतें थीं। जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर बाकी रियासतों के शासकों ने अपनी रियासतों का विलय भारत या पाकिस्तान में कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने 24 अक्तूबर, 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसका मुकाबला महाराजा हरि सिंह की सेना नहीं कर सकी और पाकिस्तानी सेना 28 अक्तूबर तक बारामूला में पहुंच चुकी थी, जो श्रीनगर से केवल 60 किलोमीटर दूर है, तब महाराजा हरि सिंह ने राज्य की सुरक्षा के लिए 28 अक्तूबर की रात में 8:00 बजे बिना किसी शर्त के भारत में विलय के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में इस विवाद को रखा। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिस कारण पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया।

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के पहले से ही शेख अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर राज्य के लिए विशेष अधिकारों के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जबकि ऐसी शर्त राज्य के विलय के समय महाराजा हरि सिंह ने नहीं रखी थी। 1949 में भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था और शेख अब्दुल्ला के दबाव में पंडित नेहरू ने बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति के जम्मू-कश्मीर को सुरक्षा, विदेश, वित्त और संचार नीति के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार देने का प्रावधान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान लागू नहीं होगा। भारत में अंग्रेजी समय से लागू भारतीय अपराध संहिता (आईपीसी) और सीआरपीसी के स्थान पर रणवीर सिंह पुरा ऐक्ट लागू किया गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य में 1932 में वहां के राजा रणवीर सिंह ने लागू किया था। शेख अब्दुल्ला के ही दबाव में पंडित नेहरू ने भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 35ए का भी विशेष प्रावधान इस राज्य के लिए कर दिया था।

दिखावे के लिए 2019 से पहले यहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली थी, परंतु वास्तव में सत्ताधारी राजनीतिक शासक इन शक्तियों को राजाओं और नवाबों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। बाहरी निवेश न होने के कारण राज्य में चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई। पाकिस्तान ने राज्य की इस स्थिति का फायदा उठाया और राज्य में ड्रग्स की तस्करी व आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अनुच्छेद 370 पाकिस्तान की मदद कर रहा था। विशेष अधिकारों की वजह से केंद्र सरकार भी जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले बजट से ज्यादा धन देती थी, लेकिन यह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, जिसका विवरण पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने अपनी पुस्तक *माई फ्रोजन टर्बुलेंस* में किया है। उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग का वर्णन करते हुए लिखा है कि राज्य पुलिस में होने वाली 120 सब इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती में मंत्री अपने चहेतों के लिए पदों की मांग कर रहे थे और पदों की संख्या के लिए लड़ाई कर रहे थे। इसी प्रकार वहां की शिक्षा, यातायात और अन्य विभागों में भ्रष्टाचार के जरिये सत्ताधारियों के लोगों को पद दिए जाते थे। इन सबसे पूरे राज्य में अव्यवस्था तथा असंतोष फैल गया और इनका ही परिणाम था कि जिस प्रकार 1948 में यहूदियों को पूरे अरब देशों से निष्कासित किया गया था, उसी प्रकार राज्य की प्रगति में योगदान देने वाले चार लाख कश्मीरी पंडितों को हिंसा के जरिये आतंकियों और कट्टरपंथियों ने कश्मीर से बाहर भगा दिया।

पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर राज्य की दुर्गति पिछले काफी समय से देश की जनता देख रही थी और इन सब दुर्गति में पूरा योगदान अनुच्छेद 370 और 35ए का था। इसलिए इस राज्य में सही अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए की समीक्षा 2019 में हटवा दिया गया। अब दोबारा कश्मीर घाटी पृथ्वी का स्वर्ग बन गई है। पर्यटक आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं और लोग शांति महसूस कर रहे हैं।

सम्पादकीय

सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि नीलामी की संभावना समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही इससे साझा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के वैश्विक मानक की पुष्टि हुई है। अब कीमतों के निर्धारण का मामला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के हाथ में है। अब जबकि नीलामी की गुंजाइश नहीं है तो ट्राई को एक फॉर्मूला तैयार करना होगा कि कैसे और किस कीमत पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए। दूरसंचार नियामक को इस विवादित मुद्दे को भी हल करना होगा कि ग्रामीण और शहरी सैटेलाइट सेवा प्रदाताओं के लिए समान नियम होंगे या नहीं। ऐसे समय में जबकि 5जी और 6जी दूरसंचार सेवाएं, उनके उपयोग या उनकी कमी अहम चर्चा का विषय हैं, सैटेलाइट संचार ने उद्योग जगत को विभाजित कर दिया है। मुकेश अंबानी द्वारा प्रवर्तित रिलायंस जियो क्षेत्रीय कंपनियों के साथ समान अवसर की आवश्यकता का हवाला देते हुए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी वाले मार्ग का समर्थन कर रही है जबकि सुनील मित्तल के नेतृत्व वाला भारती समूह सैटेलाइट संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के वैधिक चलन पर जोर दे रहा है। बहरहाल मित्तल ने मंगलवार को नई दिल्ली में उद्योग जगत पर नजर रखने वालों को उस समय चकित कर दिया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंधिया और कारोबारी जगत के दिग्गजों की मौजूदगी में मंच से कहा कि जिन सैटेलाइट कंपनियों की आकांक्षा शहरी क्षेत्रों में आकर कुलीन खुदरा ग्राहकों को सेवा देने की है उन्हें भी अन्य कंपनियों की तरह ही दूरसंचार लाइसेंस लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी उन्हीं कानूनी शर्तों का पालन करना चाहिए, लाइसेंस शुल्क चुकाना चाहिए और दूरसंचार कंपनियों की तरह ही स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए। मित्तल ने शहरी और कुलीन सेवाओं की बात करते हुए किसी कंपनी का नाम नहीं लिया लेकिन ऐसा लगा मानो वह पदैदारी के साथ उन विदेशी कंपनियों का उल्लेख कर रहे हैं जो देश में सैटेलाइट संचार सेवा प्रदान करना चाहती हैं। रिलायंस जियो और वनवेब (जिसमें भारती एयरटेल प्रमुख निवेशक है), विदेशी कंपनियां जिनमें ईलॉन मस्क की स्टारलिंक और एमेजॉन का प्रोजेक्ट कुइपर शामिल हैं, वे देश के सैटेलाइट संचार क्षेत्र में प्रमुख दावेदार हैं। यहां तक कि स्टारलिंक और कुइपर को अभी भारत में सेवा देने के लिए सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। दूरसंचार नियामक ट्राई को सैटेलाइट उद्योग के लिए मानक और दिशानिर्देश तय करने में जल्दी करनी चाहिए। यह दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है। ट्राई ने कहा है कि वह सैटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम आवंटन पर अनुशंसाएं करने के पहले हर प्रकार की टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा। बहरहाल ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ दूरसंचार कंपनियों की बदलाव की मांग के बावजूद इस विषय पर गत माह जारी मशविरा पत्र से पीछे नहीं हटा जाएगा। सितंबर में जारी मशविरा पत्र में ट्राई ने सुझाव दिया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शुल्क की कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर से जोड़ दिया जाए।

जम्मू-कश्मीर में महका लोकतंत्र : सरकार से बड़ी उम्मीदें

जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का गठन अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेगा बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। बहरहाल, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार और केंद्र का दायित्व है कि घाटी के लोगों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की आकांक्षा जतायी है, उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। एक समय राज्य में मतदाता डर कर मतदान करने हेतु नहीं निकलते थे। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहता था। इस बार मतदाता निर्भीकता के साथ मतदान करने निकले।

ललित गर्ग

आखिरकार जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की धूप खिल ही गयी, पांच साल बाद केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार मिल गयी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद केन्द्र शासित प्रदेश में यह पहली चुनी हुई सरकार है, जो नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। उमर अब्दुल्ला पहले भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी यह पारी हर तरह से खास है। नई सरकार के मुखिया के तौर पर उमर अब्दुल्ला के सामने आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कठिन चुनौती भी है। जनता ने विकास और शांति की आकांक्षा के साथ दिल खोलकर मतदान किया और अपनी उम्मीदों की सरकार चुनी है। घाटी में दशकों तक अब्दुल्ला परिवार के शासन के अनुभव के मद्देनजर घाटी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया। तमाम ऊहापोह, सुरक्षा चुनौतियों तथा विदेशी दखल की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए जम्मू-कश्मीर के जनमानस ने स्पष्ट सरकार बनाने का जनादेश दिया है। इस भूमिका तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनना ऐसे ही प्रयासों की सार्थक निष्पत्ति है। नई सरकार को विकास की चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए आतंकमुक्त कश्मीर के संकल्प को मंजिल तक पहुंचाना होगा।

जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के संकल्प को सकारात्मक समर्थन दिया है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी नहीं मिल पायी थी, लेकिन जनता ने उन्हें राज्य में सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं दूसरी ओर, इस भारी मतदान व स्पष्ट बहुमत का एक निष्कर्ष यह भी है कि लोग घाटी में शांति और सुकून, अमन एवं विकास, सौहार्द एवं सद्भावना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा कि इस क्षेत्र में शांति कायम होने के साथ विकास की नई बयार चले। जिसमें आम नागरिक खुद को सुरक्षित अनुभव करते हुए राष्ट्रीय विकास की धारा के साथ-साथ कदमताल कर सके।

निश्चित ही उमर के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, आम लोगों को भी उनकी कठिनाइयों का अंदाजा है, वहीं खुद उमर ने भी व्यावहारिक नजरिया अपनाने का संकेत दिया है। चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग पर कड़ा रुख अपनाने वाले उमर ने चुनाव नतीजे आने के बाद इस मसले पर अपना रुख नरम कर लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं, जिनमें इस मुद्दे पर जोर देने का किसी को कुछ फायदा होगा। उम्मीद बढ़ाने वाली बात यह भी है कि चुनावी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए सभी पक्षों ने सहयोग का रुख अपनाने का संकेत दिया है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई सरकार के साथ मिलकर काम करने का संकेत दिया है बल्कि खुद उमर ने भी उपराज्यपाल से टकराव की बजाय आपसी समझ एवं सकारात्मकता से शासन करने की मंशा जतायी है, जो जहां जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में है वही उमर की राजनीतिक सूझबूझ, परिपक्वता एवं विवेक का परिचायक है। चाहे उपमुख्यमंत्री पद जम्मू संभाग से चुने गए विधायक सुरिंदर चौधरी को स्थान देने की बात हो या कांग्रेस के लिए कैबिनेट में स्थान खाली रखने की, उमर अब्दुल्ला यह संकेत दे रहे हैं कि वह सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस ने फिलहाल सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसका कारण राज्य का दर्जा न मिलने को बताया है। उमर को हर कदम सावधानी से उठाने होंगे ताकि कोई भी स्थिति मंत्री पदों की संख्या का या इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मतभेद एवं टकराव का न बन जाए। उमर के एक-एक फैसले पर कैबिनेट और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का मसला सामने आ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इन सबके बीच जम्मू-कश्मीर की नई सरकार उमर के नेतृत्व में कितने सधे कदमों से आगे बढ़ती है। क्योंकि सरकार को अपना दायित्व इस बात को ध्यान में रखकर निभाना होगा कि केंद्रशासित प्रदेश में उपराज्यपाल के पास व्यापक अधिकार हैं।

केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का खासा उत्साह लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूती दे रहा है। कहीं न कहीं जनता ने स्पष्ट संदेश भी दिया कि वे हिंसा, अस्थिरता, आतंकवाद व अलगाववाद से छुटकारा चाहते हैं। जाहिरा तौर पर नई सरकार के सामने व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने की चुनौती होगी। इसलिये जम्मू-कश्मीर में नई सरकार को व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए बदली हुई शासन व्यवस्था के साथ भी साम्य स्थापित करना है। इस बात का अहसास उमर अब्दुल्ला को भी है कि शासन चलाने में अब पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं होगी। विश्वास किया जाना चाहिए कि कम से कम सीमावर्ती घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केंद्रशासित प्रदेश में वैसा टकराव देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच देखने को मिलता रहा है। विश्वास करें कि नई सरकार को प्रशासनिक मामलों में नौकरशाही का पर्याप्त सहयोग मिलता रहेगा। नीति-नियंताओं को ध्यान रखना होगा कि सरकार चलाने में किसी भी तरह का अनावश्यक व्यवधान कालांतर अशांति का वाहक बनेगा। उम्मीद करें कि यथाशीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की विसंगतियां दूर की जा सकेंगी।

राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, उसमें नई उम्मीदों को पंख लगे हैं। अलगाव से बाहर निकलने का नया विश्वास जगा है। पाकिस्तानी आतंकी सोच के नुकसान को प्रांत ने झेला और महसूस किया है। गुलाम कश्मीर के लोगों की दुर्दशा को देखा जा रहा है। इसीलिये इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक सरकार बनायी है, जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान उमर की भविष्य के शासन एवं नीतियों पर टिकी है। निश्चित ही इस नई सरकार से उम्मीद जगी है कि उसके प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही नई सरकार एवं उमर के नेतृत्व की सार्थकता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई विषय सामने सुख दायक रहेंगे। तथा आप कल जानकर खुश है कि आपके परिवार के लोग सौभाग्य देंगे है, जब आपके भितरे कुछ लोगों और दूसरों तथा, आपके बीच कही से सहायता तथा प्राप्ति। तथा ना किसी सामने सहन में और जीवन मुद्दों को सुलझाने तथा सहायकता और कोई को मालूम होगे, वरिष्ठ पदाधिकारी लोगों से भी, तथा यह सहायकता हर संकट और बाधाओं में सहज प्रदान करेगा

मेष
आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा। व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। नए काम शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है, उसे आसानी से पूरी कर सकेंगे।

वृष
आपकी प्रतिष्ठा को कलंक लगने या आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। आज आपको लाभ होने की संभावना है, परंतु आपका मनोबल स्पष्ट न हो, तो मिला हुआ अवसर भी खो सकते हैं। मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मिथुन
तालगी का अनुभव कर सकेंगे। अच्छे कपड़े और आभूषण खरीदने का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकेंगे। विशेष लाभ और योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है।

कर्क
आज आप नए काम आसानी से शुरू कर सकेंगे, परंतु आपके विचारों में स्पष्टता न होने से उलझन बढ़ने की आशंका है। व्यापार में प्रतियोगी को पछाड़ना मुश्किल होगा। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे लाभ होगा। नानिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

सिंह
आपका स्वास्थ्य खराब होगा। संतान का स्वास्थ्य चिंता में डालेंगे। साहित्य में रुचि रखनेवाले बौद्धिक लोगों से मिलकर ज्ञान की चर्चा में समय व्यतीत होगा। आपके साथ काम करने वाले तथा अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा।

कन्या
पार्टनरशिप के काम से लाभ हो सकता है। जीवन साथी के साथ सम्बंध प्रगाढ़ होंगे। मान- सम्मान बढ़ेगा। व्यापार-धंधे में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से आपका दिन लाभदायक होगा। आर्थिक कामकाज अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।

तुला
पिता के साथ निकटता बढ़ेगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में मेल और शांति रहेगी। पैसे की वसूली या व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने की संभावना है।

वृश्चिक
नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल दिन नहीं है। जिद्दी स्वभाव के कारण किसी के साथ मतभेद हो सकता है। अपनी मीठी वाणी से आप किसी को भी आकर्षित कर सकेंगे। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

धनु
आज सावधानीपूर्वक आगे बढ़े और महत्वपूर्ण काम आज हाथ में न लें, तो अच्छा होगा। उग्र स्वभाव और खराब व्यवहार के कारण आप तकलीफ में आ सकते हैं। आपको समय से भोजन नहीं मिलने की आशंका बनी रहेगी।

मकर
आपको खर्च पर काबू रखना होगा। परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है। किसी उलझन के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग ना रहने पर स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
नए काम की शुरुआत आप कर पाएंगे। किसी लंबे सफर पर या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। विदेश गमन और विदेश स्थित आपके रिश्तेदार या दोस्तों से बातचीत की संभावना है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

मीन
आप किसी भी बात का एनालिसिस अच्छे से कर सकेंगे। प्रवास, मनोरंजन, मित्रों के साथ मुलाकात, स्वादिष्ट भोजन और सुखद चीजों की खरीदारी आपको आपार आनंदित करेगी। विदेश गमन होगा और वहां रहने वाले अपनों का समाचार प्राप्त कर सकेंगे।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

'समाज सेवा का जज्बा होना चाहिए फिर चाहे आप अनुकूलता में हों या प्रतिकूलता में हों- यदि जज्बा है तो सेवा का भाव सेवा से ही शुरू और सेवा पर ही समापन होगा'

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के सुपर डुपर स्टार हैं, अलवर में 5 जुलाई 1971 को साधारण परिवार में जन्मे अनुपम व अनीखे व्यक्तित्व के धनी गिरीश गुप्ता जोकि विभिन्न संगठनों के माध्यम से समाजसेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा अलवर एवं अजमेर में हुई कॉलेज शिक्षा अलवर के राजर्षि महाविधालय से प्राप्त कर बीएन कॉलेज उदयपुर से डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स किया यदपभात फर्मास्यूटिकल कम्पनी में रहते हुए कई डायरेक्टर एवं सुपर डायरेक्टर अवाड्र्स प्राप्त करते हुए कई विदेश यात्रा एवं कैश अवाड्र्स प्राप्त किये। लेकिन उनका मन समाज सेवा की तरफ ज्यादा होने के कारण 20 जून 2012 को समाजसेवी डॉ. एससी मित्तल के बारे में सुनकर एवं उनकी सेवा भाव को देखकर मित्तल हॉस्पिटल में प्रशासक के रूप में जुड़गए। फिर क्या था सेवा भाव से जुड़े और डॉ.एससी मित्तल के नेतृत्व में अलवर में विभिन्न क्षेत्रों में कई नए आयाम हांसिल किये और अपनी अगल पहचान कायम की। शूरू से ही कुछ अलग कर गुजरने की धुन के पक्के गिरीश गुप्ता अब तक 70 से अधिक बार स्वेच्छिक रक्तदान एवं 100 से अधिक बार रक्तदान शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों जिन्दगानी बचाने में अपनी बेहतरीन भूमिका निभा चुके हैं। 3988 से अधिक लोगो को अब तक रक्त सहायता दिलवा चुके है। गिरीश गुप्ता वर्तमान में मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पद पर कार्यरत है साथ ही लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233 ई 1 के रीजन 2 सांवरियाँ के रीजन चेयरपर्सन, रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांच सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन, राजस्थान स्काउट एण्ड गाइड फेलोशिप के स्टेट कोऑर्डिनेटर तथा अलवर जिला स्काउट एण्ड गाइड फेलोशिप के अभी हाल ही में सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुने गए है। करीब 27 संस्थाओ में एक्टिव मेम्बर के रूप में कार्यरत है। राजस्थान सरकार एवं जिले द्वारा स्वच्छता दुत अवार्ड से सम्मानित, नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिल्ली में ताम्र पत्र द्वारा सम्मानित, लायंस क्लब इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉ. नवल जे मालू 2018-20 द्वारा एवं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डगलस एक्स एलेग्जेंडर द्वारा 2021-22 द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय लेवल के तथा स्टेट एवं जिला लेवल पर सैंकड़ो अवाड्र्स प्राप्त कर चुके है। वर्ष-1991में नईदिल्ली में राजस्थान कॉन्टिंगजेंट कमान्डर बनकर गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान एनसीसी दल का नेतृत्व किया एवं राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा अवार्ड प्राप्त किया। वर्ष 1991 में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। हमेशा ऊर्जा से लबरेज इस युवा का क्या कहना। कभी भी किसी भी काम के लिए यदि इन्हें कहा जाए तो शायद मुझे याद नहीं कि इन्होंने मना किया हो। ऐसी खूबसुरत शख्सियत को दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम सलाम करती है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

गिरीश गुप्ता
(युवा समाजसेवी)

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

18 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जर्मनी में हैडलबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना 1386 में हुई।
- इंग्लैंड के नौसैनिक कमांडर जॉन हॉकिन्स ने 1564 में दूसरी बार अमेरिका यात्रा शुरू की।
- स्पेन की सेना ने 1572 को मास्ट्रिच पर हमला कर दिया।
- उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों में 'बोस्टन शूमेकर्स' पहला श्रम संगठन 1648 को बना।
- थॉमस एल्वा एडीसन ने 1878 में घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध करायी।
- अमेरिका में 1891 को पहली अंतरराष्ट्रीय छह दिवसीय साइकिल रेस न्यूयार्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन से शुरू हुयी।
- में शुरु किया गया।
- अमेरिका ने 1898 को स्पेन से प्यूर्टो रिको का अपने कब्जे में लिया।
- काउंट बर्नार्ड वॉन बुलो 1900 में जर्मनी के चांसलर बने।
- ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1922में हुई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी से चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता के लिये सोवियत संघ ने 1944 को लड़ाई शुरु की।
- टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने पहले ट्रांजिस्टर रेडियो की घोषणा 1954 में की।
- लॉर्ड होम को कंजरवेटिव पार्टी में 1963 को नेतृत्व के लिए चली उठापटक के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया था।
- हेंस ए बेथे को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1967 में दिया गया।
- पहले बहुद्देशीय हेलिकॉप्टर एस ए 315 का 1972 को बैंगलोर में परीक्षण।
- अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री वैसिली लिओन्टीफ को 1973 में अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- विलियम एन लिप्सकॉब जूनियर को 1976 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता एरिक होनेकर को 1989 में उनके पद से हटा दिया गया.
- पहली हिमालय कार रैली को 1980 में बम्बई (मुंबई) के ब्रेबोर्न स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- सम्पूर्ण विश्व में व्यापक विरोध के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा अश्वेत कवि बेंजामिन मोलोइस को 1985 में फाँसी।

विशेष आलेख

सत्ता तंत्र की अरुचि से कमजोर हो रहा अधिकार

प्रदीप मिश्र

किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने का मंतव्य इससे स्पष्ट होता है कि इसके लिए नीति, नियम और अधिनियम क्या बनाए जाते हैं और उनका क्रियान्वयन व निगरानी कैसे की जाती है। 12 अक्तूबर 2005 को लागू किए गए सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) के हालात बताते हैं कि कड़ी मशक्कत से तैयार जनहित के कानून को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। 18 वर्ष पहले जनसामान्य को मिले इस अभूतपूर्व मौलिक अधिकार की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर यद्यपि कोई सवाल नहीं है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर गरिमा के लिए प्रयास और जागरूकता की पहल का अभाव है। अधिनियम में किए गए संशोधनों और सतर्क समूहों के सुझावों की अनदेखी भी इस बारे में चिंताएं बढ़ाती है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के डेढ़ वर्ष बाद भी आरटीआई पोर्टल शुरू नहीं किया है। इनसे 21 अक्तूबर तक जवाब मांगा गया है। यहां यह जानना जरूरी है कि शीर्ष अदालत आरटीआई आवेदनों के लिए पोर्टल बना चुकी है। आरटीआई कानून केंद्र-राज्य सरकार को ही नहीं, इनके सभी उपक्रमों को नियमों का पालन करने के साथ नियमानुसार काम करने की नसीहत देता है। अन्य कानून जहां आम जनता के लिए बनाए जाते हैं वहीं यह कानून संसद और विधानसभाओं द्वारा मान्य संस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। माना जाता है कि गोपनीयता से अनिश्चितता को बढ़ावा मिलता है और अनिश्चितता व्यवस्था को कमजोर बनाती है। सूचना अधिकार के कानून को लागू करने में सरकारों की अरुचि रही है। यह हाल तब है, जब दुनिया में सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल भारत में होता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल लगभग 60 लाख आरटीआई डाली जाती हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि 2005-06 में उसके यहां आरटीआई आवेदनों की संख्या 24,436 थी। 2021-22 तक यह आंकड़ा 18,32,133 तक पहुंच गया। भारतीय संविधान की धारा 19 (1) (क) और धारा 21 में नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए सभी कार्यों को जानने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। यह परिकल्पना 2005 में कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में साकार हुई। पारदर्शिता के परिदृश्य में बने कानून को भ्रष्टाचार से लड़ाई का सशक्त हथियार माना गया पर सरकारी पैंचीदगियों ने इसकी पहुंच आसान नहीं रहने देने के प्रयत्न किए। यही कारण है कि सूचनाओं की शुचिता बनाए रखने के बजाय संशोधन की आड़ लेकर संकोच को सार्वजनिक किया गया। संवेदनशीलता के नाम पर सूचनाएं छिपाने का पुरजोर प्रयत्न किया जा रहा है। जन सूचना अधिकारी जानकारी देने में अनावश्यक विलंब के साथ बचने का रास्ता निकालते हैं। कई बार निर्धारित अवधि 30 दिन के भीतर सूचनाएं या तो दी नहीं जा रही हैं या फिर आधी-अधूरी देकर आवेदक को उलझाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोग ने 11 जुलाई 2024 से द्वितीय अपील और शिकायतों को अफिलाइन लेने की व्यवस्था बंद कर दी है। अब ऑनलाइन द्वितीय अपील और शिकायतें ही स्वीकार की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरटीआई विभाग के प्रवेश मुखर्जी प्रयोजक इसे विडंबना बताते हुए कहते हैं कि सरकारी कार्यालयों में दोनों ही व्यवस्थाएं लागू हैं। मध्य प्रदेश के रीवा निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट संजय सिंह 2012 से अब तक एक हजार से अधिक आरटीआई लगा चुके हैं। क्या भारत आजाद है? क्या हमारा बहुत सारा टैक्स का पैसा ब्रिटेन को जाता था? रेलवे में लंबाई और वजन के आधार पर सीट के लिए क्या नियम हैं? आदि का संतोषजनक जवाब उन्हें अब तक नहीं मिल सका है। केंद्र सरकार द्वारा कामचलाऊ जवाब देकर भी वास्तविक तथ्य बताने से बचा जाता है। छत्तीसगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले आयकर भुगतान की राशि की जानकारी मांगी गई तो बीते वर्ष का ब्योरा देकर बताया गया कि भुगतान की गई राशि का विवरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह व्यक्तिगत है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। शुक्ल की तमाम आरटीआई के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में जानकारी नहीं दी है। फंड में मिली राशि और उसके खर्च के बारे में फंड की वेबसाइट भी चुप है। भारतीय गणतंत्र के इस महत्वपूर्ण कानून पर जागरूकता का अभाव और अनदेखी इससे स्पष्ट होती है कि 12 अक्तूबर गुजर जाता है और पता नहीं चलता कि जनता को एक मौलिक अधिकार इसी तारीख में मिला था। तंत्र की इसमें दिलचस्पी नहीं है कि इस तारीख को हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, साक्षरता दिवस, योग दिवस और मजदूर दिवस की तरह सूचना या जानकारी दिवस का स्वरूप दिया जाए। दिन और दिनांक विशेष पर दलीय सीमाओं और निष्ठाओं से अलग हटकर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को अपनी उपलब्धियां ही बतानी चाहिए। सूचना मंत्री भी इस दिशा में किए जा रहे उपायों, बाधाओं और निष्कर्षों से परिचित कराएं। तथ्यों को लेकर संजीदगी बरतने के बहाने सूचनाओं का प्रवाह रोकने के लिए प्रयासरत समूचा तंत्र सूचनाओं की स्वतंत्रता को लेकर सामंतशाही की मानसिकता में है। केंद्र सरकार विस्सल ब्लोअर संरक्षण एक्ट लागू नहीं कर रही है। उदासीनता का परिणाम है कि सूचनाएं और दस्तावेज लेने में कई आरटीआई एक्टिविस्ट जान गंवा चुके हैं। धमकियां, रिपोर्ट, हमले और प्रलोभन आम बात हो गई है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हथीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहड़,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

हिन्दुस्तान 1936

नागरिकता से न्याय

सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 6ए की सांविधानिकता को बरकरार रखकर सही फैसला लिया है। वैसे पांच न्यायाधीशों की पीठ इस फैसले पर एकमत नहीं थी और अंततः फैसला चार-एक से 6ए के पक्ष में आया है। भारतीय नागरिकता देने से संबंधित इस प्रावधान का विशेष महत्व है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से बांग्लादेश से आकर भारत में बसे उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, जो जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत आए हैं। अदालत में अनुच्छेद 6ए को एकाधिक याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई थी कि नागरिकता देने की कोई समय-सीमा न रखी जाए, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि असम में प्रवेश और नागरिकता देने के लिए 25 मार्च 1971 की अंतिम तिथि सही है। भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा का बहुमत का फैसला इस बात पर सर्वसम्मत था कि साल 1985 में संसद द्वारा बनाया गया कानून एक विधायी समाधान है, जिसे संसद ने प्रभावी बनाया है। यह असम समझौता असमिया संस्कृति, विरासत, भाषायी और सामाजिक पहचान को सुरक्षित-संरक्षित करने के मकसद से किया गया था।

जिस 6ए को चुनौती दी गई थी, उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच खोजा गया एक सही सियासी समाधान था। असम में इस कानून के लिए विशेष रूप से छात्रों ने छह साल तक प्रदर्शन किया था, तब जाकर समझौता हुआ था और कानून बनाया गया था। यह कानून न बनता, तो शायद बांग्लादेश की ओर से लोगों का आना कम नहीं होता। वैसे एक पहलू यह भी है कि कानून बनने के बावजूद बांग्लादेश से लोगों का आना रुका नहीं है और इसी आधार पर एक न्यायाधीश बहुमत के फैसले से असहमत हैं। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला के मुताबिक, सांस्कृतिक-सामाजिक संरक्षण का मकसद पूरी तरह से हल नहीं हुआ है और ऐसे में, अनुच्छेद 6ए को असांविधानिक माना जा सकता है। हालांकि, यह एक बहुत गंभीर सवाल है कि साल 1971 के बाद असम या भारत में आए लोगों को भी अगर स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या होगा? ऐसी ढिलाई या उदारता अन्य लोगों को भी भारत आने के लिए उकसाएगी। अतः संस्कृति और आबादी के ढांचे को बचाने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 6ए की वैधानिकता को कायम रखा है। असमिया संस्कृति, विरासत, भाषायी व सामाजिक पहचान को संरक्षित-रखना जरूरी है।

आज लोगों का एक से दूसरे देश में अवैध पलायन और उसके बाद नागरिकता के सवाल पर भारत ही नहीं, हरेक देश का चिंतित होना स्वाभाविक है। सबको अपने हित में कानून बनाने व लागू करने का हक है। यह अच्छी बात है कि हमारी अदालतों को भी चिंता है कि भारतीय राज्य का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी संस्कृति स्थानीय बसावट को मुश्किल में डालती है। आजकल स्वयं बांग्लादेश म्यांमार से आई रोहिंग्या आबादी की वजह से बहुत परेशान है और वह अपनी परेशानी संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार उठा चुका है। ध्यान देने की बात है कि मुस्लिम राष्ट्र बांग्लादेश में भी मुस्लिम रोहिंग्या को शरण देने में समस्या हो रही है और वह अपनी अर्थव्यवस्था व सामाजिकता के बारे में सोच रहा है। भारत को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपने व्यापक सामाजिक-आर्थिक हित के आधार पर ही सोचना चाहिए और तभी किसी को नागरिकता देनी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 18 अक्टूबर, 1949

वाणी और व्यवहार

हमने पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के मुंह से अनेक बार सुना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा। जब पाकिस्तान नहीं बना था, तब पाकिस्तान आन्दोलन के सबसे बड़े नेता मि. जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ न केवल न्यायोचित, बल्कि उदार व्यवहार किया जायेगा। पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसी बीती और उन्हें किस तरह घर-द्वार और जमीन-जायदाद छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, यह एक दर्दनाक कहानी है। वह सब असाधारण परिस्थितियों में हुआ, जबकि लोगों के दिमाग गुस्से की आग से भड़क उठे थे और उन्हें भले-बुरे का कोई विवेक नहीं रह गया था। एक हद तक यह बात सही हो सकती है, किन्तु इस गुस्से को भड़काने की जिम्मेदारी भी तो पाकिस्तान के समर्थकों की ही थी। उन बातों को काफी अरसा हो गया और साधारण अवस्था पुनः कायम हो गई है। किन्तु क्या आज भी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं, सुख की नींद सो सकते हैं?

हमें खेद है कि इस प्रश्न का 'हां' में उत्तर नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां लियाकत अली खां इन दिनों पूर्वी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पिछले चौबीस घण्टों में दो बार यह कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बराबर के अधिकार और सुविधायें प्राप्त हैं, और उन्हें डरने का कोई कारण नहीं है। काश कि मियां लियाकत अली का यह कथन सच होता और अल्पसंख्यक निर्भय होकर पाकिस्तान में रहते होते और उनको मुसलमानों के बराबर ही अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होतीं। किन्तु वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत हैं। सिंध से हिन्दुओं को अब भी खदेड़ा जा रहा है। वहां उन हिन्दुओं के आवेदन-पत्रों की संख्या में पिछले दिनों तेजी से वृद्धि हुई है, जो सिंध से भारत आना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निष्क्रमणार्थी कानून का मनमाना अर्थ लगाकर अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति को ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में हस्तगत किया जा रहा है। इस प्रकार चल और अचल सम्पत्ति के छिन जाने के कारण जो हिन्दू, निराश्रित हो गये हैं, वे भारत आने के लिए बाध्य हो रहे हैं।... पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति हड़पने के तरीके काम में लाये जा रहे हैं।

खुली आंखों और संविधान वाली देवी

यहां स्कैन करें

संजय पारिख | वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

न्याय देवी की प्रतिमा जिन मूल्यों की ओर इशारा कर रही है, उन्हें हम कितना देख-समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे सुनने-समझने के नए प्रयास होने चाहिए।

आम धारणा है कि न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी यह बताती है कि कानून अंधा होता है। ऐसी समझ को लेकर साल 1983 में *अंधा कानून* नाम से एक लोकप्रिय फिल्म तक बन चुकी है। यहां तक कि न्याय की देवी के हाथों में तराजू के झुके पलड़े को अन्याय के संकेत के रूप में ही दिखाया जाता रहा है। मगर अब ये सब बातें इतिहास बन जाएंगी। न्याय की देवी की नई प्रतिमा न सिर्फ खुली आंखों वाली है, बल्कि तलवार की जगह इनके हाथ में संविधान है। तराजू के पलड़ों को भी अब बराबर कर दिया गया है। देवी का रंग भी श्वेत कर दिया गया है।

खबरों की मानें, तो ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि भारत गुलामी के सभी संकेतों से बाहर निकलना चाहता है। आंखों से पट्टी हटाकर यह बताया गया है कि कानून कभी अंधा नहीं होता। तलवार को हिंसा का संकेत समझा गया था और इसे हटाकर बताया गया है कि देश संविधान से चलता है। तराजू के बराबर पलड़े का अर्थ है, सभी के लिए न्याय के समान अवसर। श्वेत रंग संभवतः शुभ या शुचिता का संकेत देता है।

बहरहाल, न्याय की देवी के पुराने संकेतों को हम अपने तई विश्लेषण करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन न्याय का तकाजा यही है कि हम उसे उसी नजर से देखें, जिस नजर से इसे स्वीकार किया गया था। 16वीं सदी से न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधे दिखाया जाता रहा है। उस वक्त इसे निष्पक्षता का प्रतीक समझा गया था। सोच यही थी कि बंद आंखों से न्याय अपने सम्मुख आने वाले लोगों में पैसे, पावर या रुतबे के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करेगा। मगर हम इस प्रतीक को न्याय-प्रक्रिया में कितना उतार सके हैं, यह जानना जरूरी है? स्थिति यह है कि आज भी वकालतखाने में यह चर्चा अमूमन होती है कि अदालत में पेश होने वाले अभियोजन या अभियोग पक्ष के रुतबे को देखकर न्याय प्रभावित हो जाता है। शायद हम न्याय की देवी की बंधी आंखों का अर्थ न्याय-प्रक्रिया में उतारने में सफल नहीं हो पाए हैं।

इसी तरह, तराजू का एक पलड़ा झुका रहने का संकेत था कि दोनों पक्षों की बहसों को सुनने के बाद न्याय का फैसला उसके हक में दिया जाएगा, जिसके गवाह और तर्क में दम हो। अदालत में सच एक पक्ष के ही साथ खड़ा होता है, जो कि निष्पक्ष विवेचना के बाद वजनदार साबित होता है। रही बात तलवार की, तो उसका मतलब था, न्याय शीघ्रता से और अंतिम तौर पर मिले। तलवार को इस बात का प्रतीक माना गया था कि बिना किसी देरी और उलझन के सही फैसला दिया जाएगा। जाहिर है, अगर हम इन संकेतों का शाब्दिक अर्थ लगाएंगे, तो अनर्थ ही करेंगे।

यहां नए संकेतों का अर्थ समझना भी आवश्यक है। कहा गया है कि तराजू का बराबर पलड़ा समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि हाथ में संविधान का मतलब है, संचालन-प्रक्रिया का सांविधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना। आंखों से पट्टी हटने का संकेत है, सबको समान रूप से देखना। यानी, नए संकेतों के अर्थ भी करीब-करीब पुराने प्रतीकों को ही ध्वनित कर रहे हैं। इसी कारण न्याय की प्रतिमा में किए गए हालिया बदलावों को सांकेतिक ही अधिक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन सबके बजाय यदि हम न्याय की देवी द्वारा इंगित मूल्यों में संजीदगी दिखाते, तो कहीं बेहतर होता।

हमें देखना यह भी चाहिए कि आखिर भारतीय न्याय-व्यवस्था को लेकर आम धारणा इतनी कटु क्यों है? यह क्यों माना जाता है कि यहां न्याय देर से मिलता है, जबकि अदालतों में तारीखें अनवरत मिलती रहती हैं? प्रस्तावना में जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की गई है, उसे वास्तविक अर्थों में साकार करने में हम अब तक क्यों विफल रहे हैं? कानून के सम्मुख सभी के समान होने का जो निर्देश संविधान देता है, उसे हम अपनी व्यवस्था में पूरी तरह क्यों नहीं उतार सके हैं? जब तक इन सवालों के उचित जवाब हम नहीं खोज लेते हैं, तब तक न्याय की देवी के प्रतीक-चिह्नों की सार्थकता कठघरे में खड़ी की जाती रहेगी।

कुल मिलाकर, प्रतीकात्मक बदलावों का भारतीय न्याय-व्यवस्था पर सीधे शायद ही कोई असर पड़ेगा। देखना यह जरूरी था कि न्याय की देवी के प्रतीक-चिह्नों से जो मूल्य निकल रहे हैं, उसे हम कितना सुन-समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ रहे, तो उसे सुनने-समझने के प्रयास होने चाहिए थे। यह कहीं ज्यादा जरूरी कवायद होती। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि अदालतों के मौजूदा व्यवहार और व्यवस्था में जल्द बदलाव नहीं हुआ, तो यह स्थिति आगे भी बनी रह सकती है और तब न्याय की देवी बस एक निरर्थक संकेत बनकर रह जाएगी।

असल में, प्रतीक-चिह्न एक पहचान के रूप में काम करते हैं। हर संस्थान के पास अपना एक प्रतीक-चिह्न होता है, जिससे वह अपने कर्म का संदेश देता है। अन्य देशों में अलग-अलग व्यवस्था है, लेकिन साझा मत यही है कि इन प्रतीक-चिह्नों से जो प्रतीकात्मक अर्थ निकल रहा है, वह हर हाल में साकार हो। भारतीय अदालतें इस मामले में उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी हैं। लिहाजा, इन संकेतों के सार्थक होने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मसलन, अदालतों में वकील पूरी तैयारी के साथ आएं; मामले इस तरह पेश किए जाएं कि न्याय जल्दी मिल सके; मुकदमों का उचित वर्गीकरण हो; अलग-अलग जजों के एक ही मुद्दे पर अलग-अलग विचार न हों; जजों की पर्याप्त संख्या हो; अदालतों पर मुकदमों के लगातार बढ़ते बोझ कम करने के सार्थक प्रयास किए जाएं, आदि। ऐसे तमाम उपायों से ही भारतीय न्याय-व्यवस्था की लेट-लतीफी की बन चुकी आम धारणा खंडित हो सकेगी।

अभी यह सोचने का उचित अवसर है कि भारतीय कानून-व्यवस्था के 'अंधे' होने की धारणा बनी क्यों? अगर शुरुआत में ही हम न्याय की देवी के प्रतीकात्मक संकेतों को सही अर्थों में अपना चुके होते, तो आज हमें प्रतिमा में किसी भौतिक बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। मूर्ति में बदलाव की नहीं, बल्कि न्याय के सभी परिमार्पों को न्याय-प्रक्रिया में लाने की आवश्यकता है। मगर, जैसा कि कहते हैं, जब जागो, तभी सबेरा। हम आज भी न्याय की देवी के तमाम संकेतों को वास्तव में साकार कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें जरूरी गंभीरता दिखानी पड़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिजिटल अरेस्ट से लोगों को लूटने की बढ़ती साजिश

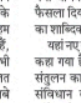

यहां स्कैन करें

शशांक द्विवेदी | संयुक्त निदेशक, एडएल्फम ग्रुप

पहले केवल पुलिस गिरफ्तार करती थी, पर अब नए दौर में साइबर अपराधी भी तकनीक की मदद से लोगों को कैदी बनाने लगे हैं, इसे 'डिजिटल अरेस्ट' कहा जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबरठग लोगों को ऑनलाइन माध्यमों से डराकर उनसे फिरौती मांगते हैं। हजारों लोग इसका शिकार बन चुके हैं। कुछ लोगों ने मामला दर्ज कराया है, तो बहुत से लोगों ने अफसोस और शर्म के मारे खामोशी ओढ़ ली है।

पिछले दिनों दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में रहने वाले 72 वर्षीय कृष्णदास गुप्ता को 12 घंटे से ज्यादा समय तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके 83 लाख रुपये एक ऐसे खाते में ट्रांसफर कराए गए, जिसके बारे में ठगों ने दावा किया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय का अकाउंट है। उनसे कहा गया था कि जांच के बाद उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

ऐसे ही साइबर ठगों ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर निरुपती का डर दिखा पीजीआई लखनऊ में डॉक्टर रुचिका टंडन को सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे 2 करोड़, 81 लाख रुपये ठग लिए। ठगों की हिम्मत देखिए, उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश के नाम का सहारा लेते हुए व फर्जी कोर्ट रूम दिखाकर वर्धमान समूह के चेयरमैन और पंजाब के प्रसिद्ध उद्योगपति एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर सात करोड़ रुपये की साइबर ठगी कर डाली। ऐसे बहुत से मामले हैं, जो चर्चा और लोगों की चिंता में आ गए हैं।

अकेले दिल्ली में हर महीने डिजिटल अरेस्ट के लगभग 200 मामले सामने आते हैं। ऐसे में, सबसे जरूरी है, लोगों का सचेत रहना।

भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में करीब 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 10 वर्ष में 65 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 4.69 लाख करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है और यह अब भी जारी है। अगस्त, 2019 से दिसंबर, 2023 तक सरकारी पोर्टल में साइबर अपराध की 31 लाख से ज्यादा शिकायतें आईं, जिनमें सिर्फ 66 हजार मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। बीती मई से जुलाई के तीन महीनों के दौरान सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट के 600 से ज्यादा मामलों की रिपोर्टिंग हुई है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, सिर्फ दिल्ली में हर महीने डिजिटल अरेस्ट के लगभग 200 मामले सामने आते हैं। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोहों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है, जो कानून में नहीं है, पर अपराधियों के इस पैटर्न पर बढ़ते अपराध की वजह से इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाने लगा है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसियां सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती हैं। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है, तो वह दो तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिये शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, आप स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को एक घंटे के भीतर सूचना देते हैं, तो ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने की संभावना रहती है। सरकार ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए संचार साथी वेबसाइट में 'चक्षु पोर्टल' को लॉन्च किया है।

बदलते दौर में सचेत रहने की जरूरत है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको वाट्सएप पर किसी अनजान ग्रुप में जोड़ता है, तो तुरंत उससे कारण पूछें और किसी भी अनजान ग्रुप से न जुड़ें। इसी तरह, फेसबुक पर कोई आपको लालच देकर किसी पेज को लाइक करने को कहे या किसी अनजान ग्रुप से जुड़ने को कहे, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। यूट्यूब पर किसी वीडियो में दिए गए नंबरों पर कॉल नहीं करना चाहिए। कई बार वीडियो लाइक करने पर पैसे दिए जाने का लालच दिया जाता है और फिर अकाउंट डिटेल्स लेकर ठगी की जाती है। पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह के ऑनलाइन शॉर्टकट तरीकों से बचना चाहिए। समय के साथ समझदार और सचेत रहने की जरूरत बढ़ती जा रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

क्रोध की आग विनाशकारी

क्रोध को अग्नि के समान क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें इंसान खुद तो धधकता ही है, उसका क्रोध आस-पास के लोगों में भी क्रोध की चिनगारी सुलगा देता है। यह सबसे पहले मनुष्य के विवेक को भस्म करता है।

एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। चलते-चलते वह एक गांव के बगीचे में पहुंचे। बुद्ध के आने की खबर आसपास के गांवों में भी पहुंच गई। उनके दर्शन और उनकी अमृतवाणी सुनने के लिए लोग बगीचे में उमड़ आए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मौन बैठे थे। जब काफी देर हो गई, तो शिष्यों को लगा कि तथागत कहीं अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया, 'तथागत! आज आप शांत क्यों हैं? आपको सुनने की प्रतीक्षा में हजारों लोग बैठे हैं। क्या हमसे कोई गलती हो गई है?' बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन रहे। सच यह था कि हर पल आनंद में स्थित बुद्ध न तो नाराज थे और न ही अस्वस्थ। वह तो सभा में आए हजारों लोगों के चित्त के चित्र को अपने ध्यानस्थ नेत्रों से देख रहे थे कि प्रत्येक दर्शनार्थी के मन में क्या चल रहा है? उसके चित्त की दशा क्या है? बुद्ध अपने तरीके से लोगों की मानसिक उलझनों को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान सुझाने के प्रयास करते थे।

इसी बीच पीछे खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? एक शिष्य बोल उठा कि उस व्यक्ति को सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध मौन से बाहर आए और बोले- नहीं! उसे सभा में आने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों के साथ वहां बैठे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति महात्मा बुद्ध द्वारा किसी को अनुमति न दिया जाना सबके लिए आश्चर्यजनक था। बुद्ध की निगाह में तो मानव मानव में कोई भेद न था।

बुद्ध ने कहा- 'इस व्यक्ति के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है। क्रोध हिंसा का प्रकट रूप है। जिस व्यक्ति में क्रोधाग्नि जल रही है, वह अहिंसक हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सभा, समूह और समाज से दूर ही रहना चाहिए।' उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह दौड़ते हुए आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बिलखने लगा। बुद्ध उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए बोले- वत्स! क्रोध उस दहकते हुए कोयले के समान है, जिसे व्यक्ति दूसरों को जलाने के लिए अपने मन में रखे रहता है और उससे हर पल वह स्वयं ही जलता है, इसलिए इससे बाहर निकलो। अपने अंदर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता के जल को भरकर इसे सदा-सदा के लिए बुझा सकते हो। इसके बुझते ही तुमको शांति मिलेगी और तुम्हें अपने अंदर से सुख की प्राप्ति होने लगेगी।

करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति महात्मा बुद्ध द्वारा किसी व्यक्ति को सभा में न आने देना सबके लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि बुद्ध की निगाह में तो मानव मानव में कोई भेद न था।

सुभाष चंद्र शर्मा

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

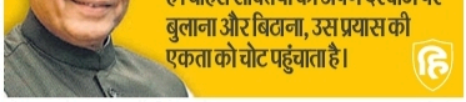

भारत की समुद्री सीमाएं जिन देशों के साथ लगती हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि समुद्री सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने दरवाजे पर बुलाना और बिठाना, उस प्रयास की एकता को चोट पहुंचाता है।

अनुलोम-विलोम

पराली-दहन

दूसरे राज्यों के किसानों का दोष नहीं

पराली जलाने के खिलाफ शीर्ष अदालत सख्त हो गई है। किसी अदालती आदेश या टिप्पणी पर मैं अपनी राय नहीं दे रहा। यह जानता हूं कि कोर्ट का आदेश है, तो उस पर अमल होना ही चाहिए, लेकिन जितनी मुस्तैदी से यह ध्यान रखा जाता है कि किसान अपने खेतों की पराली न जला सकें, उतनी ही गंभीरता उन कारकों पर भी दिखाई जाती, तो बेहतर होगा, जिनसे प्रदूषण फैलता है और दिल्ली की आबोहवा खराब होती है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि यहां जितने भी कल-कारखाने हैं, जो सालों भर वातावरण को दूषित करते हैं या दूषित पानी नदियों में बहाते हैं, उनके खिलाफ भी समय-समय पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती? क्या यह विडंबना नहीं है कि काफी प्रदूषण फैलाने वाले कल-कारखाने भी कागजों पर मानक के अनुरूप पाए जाते हैं? आप सबको याद ही होगा कि दूषित वातावरण वाली दिल्ली सिर्फ लॉकडाउन में स्वच्छ हुई थी। इसका क्या यह संकेत नहीं है कि दिल्ली का प्रदूषण पराली से जुड़ा मसला नहीं है? मेरा तो यही मानना है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाना चिंता का विषय नहीं, यह तो 10-15 दिनों की बात होगी, असल विषय तो यहां सालों भर आबोहवा को दूषित करने वाले बीमार कल-कारखाने और उनसे निकलने वाला धुआं है। समाधान यहीं से निकलेगा। वैसे, सरकारों को धन्यवाद देना चाहिए कि वे समय-समय पर मुकदमे खत्म करती रही हैं, अन्यथा तमाम किसान अब तक जेल में होते।

आशीष जयकरन नाथ वर्मा, टिप्पणीकार

यहां का प्रदूषण

पिछले दिनों की बात है। नई दिल्ली में न जाड़े की दस्तक हुई थी और न पराली का धुआं यहां पहुंचा था। फिर भी, यहां की वायु गुणवत्ता बिगड़ चली थी। कमोबेश हर रोज एक्यूआई में कुछ अंकों की वृद्धि देखने को मिल रही थी। चिंताजनक यह थी कि दिल्ली के सभी 13 हॉटस्पॉट की हवा 'खराब' या 'बहुत खराब' की श्रेणी में पहुंच गई थी। वास्तव में, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो सकता है, पर अफसोस यह कि कानून बनाने और उसका पालन करवाने का अधिकार अधिकतर उन लोगों के पास है, जो भ्रष्ट व लापरवाह हैं। उनको दूर पंजाब से जलती पराली का धुआं तो दिख जाता है, मगर हर चौराहे पर खड़े कमर्शियल तंदूर नहीं दिखते। रिश्वत लेकर प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाते पेट्रोल पंप नहीं दिखते। अगर प्रदूषण खत्म करना है, तो युद्धस्तर पर काम करना होगा। मगर अफसोस, सारी प्लानिंग वसूली तक सिमटी रह जाती है।

विवेक, टिप्पणीकार

दिल्ली वालों को बीमार करता यह धुआं

पंजाब और हरियाणा में पराली कितनी तेजी से जलाई जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां इस साल पराली जलाने की अब तक 900 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से भी धुआं-धुआं हैं, वानी यहां काफी अधिक पराली जलाई जा रही है। एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि बठिंडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले दस दिनों में 100 से 500 तक पहुंच चुका है। कुछ इसी तरह का हाल दिल्ली का भी है, जहां पराली का धुआं पहुंचने लगा है। नतीजतन, यहां की वायु गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी है। इसका नुकसान विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को होता है। सांस की बीमारी से पीड़ित लोग तो इन दिनों मानो घुटन भरी जिंदगी जीने को अभिशप्त हो जाते हैं।

पराली वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। इसको जलाने से कार्बन डाई-ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाई-ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे तमाम जहरीली तत्व व गैसें हवा में घुलती हैं। जब वे चीजें सांसों के जरिये इंसान के शरीर में जाती हैं, तो श्वसन-प्रक्रिया में रुकावट पैदा करती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी कहती है कि पराली का जो धुआं दिल्ली आता है, वह यहां के लोगों को बीमार कर रहा है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने भी सख्त रुख अपनाया है और पूछा है कि पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसा करना जरूरी है। विशेषकर दिल्ली को 'गैस चैंबर' बनने से यदि हमें रोकना है, तो पराली-निस्तारण का उपाय खोजना ही होगा।

कुछ किसानों का मानना है कि पराली जलाने से उनके खेत की उर्वरता बढ़ जाती है, जबकि असलियत में यह एक मिथक है और तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। रिपोर्ट यही बता रही है कि बार-बार पराली जलाने से खेत बंजर होने लगे हैं, जिसके कारण खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ गया है। ये रासायनिक खाद या उर्वरक हमारी जमीनों को ही नहीं, इंसानी सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर, यही समझिए कि पराली को जलाना कोई अच्छी नीति नहीं है। इसके बजाय हमारे किसानों को प्रकृति-हितैषी प्रयास करना चाहिए। उनको यह भी समझना चाहिए कि पराली जलाने से खुद उनकी और उनके बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। सरकार भी किसी किस्म की दंडात्मक कार्रवाई के बजाय जागरूकता फैलाए, तो शायद ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

किशोर कुमार, टिप्पणीकार

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024

ख़त्म हुई उलझन

नागरिकता कानून की धारा 6-A की संवैधानिकता पर गुरुवार को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक पुराने मसले के नए सिरे से उभर आने की आशंकाओं पर तो विराम लगा ही दिया, कई ऐसे पहलुओं पर भी रोशनी डाली, जिससे समाकलीन बहस को दिशा मिल सकती है। इस लिहाज से यह फैसला असम में अवैध प्रवासियों के मामले को देखने के असम समझौते में रेखांकित हुए नजरिए की पुष्टि करता है।

दो कटऑफ डेट | अदालत के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि नागरिकता के लिए दो कटऑफ डेट रखना सही है या नहीं। कोर्ट ने इसे सही बताते हुए स्पष्ट किया कि असम की खास भौगोलिक स्थिति और अवैध घुसपैठियों की समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने असम समझौते के रूप में एक राजनीतिक समाधान निकाला। धारा 6-A का जुड़ाव इसी मसले का विधायी समाधान है। कोर्ट के मुताबिक सरकार को इसका पूरा अधिकार है।

AI image

सिटिजंस एक्ट- अहम फैसला

विशिष्ट मामला | जहां तक अन्य राज्यों में ऐसा प्रावधान करने की बात है तो इसका सीधा, सहज जवाब हां में आता है। लेकिन इस बिंदु पर कोर्ट का यह कहना महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य राज्य में समस्या ने इतना गंभीर रूप लिया ही नहीं। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल के उदाहरण का फैसले में भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि असम में 40 लाख प्रवासियों की मौजूदगी पश्चिम बंगाल के 57 लाख प्रवासियों के मुकाबले ज्यादा गंभीर इसलिए मानी जाएगी क्योंकि असम में जमीन की उपलब्धता काफी कम है। जाहिर है, अदालत का फैसला बताता है कि इस मसले को सभी तथ्यों, प्रसंगों और संदर्भों के साथ देखकर ही नतीजा निकाला जाना चाहिए।

तीन अलग श्रेणियां | यह फैसला बाहर से आकर असम में रह रहे उन तमाम लोगों के लिए राहत लेकर आया, जो खुद को अनिश्चितता में फंसा महसूस कर रहे थे। फैसले ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किन लोगों की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है और किन लोगों को अवैध प्रवासी के रूप में चिह्नित कर कानूनी तौर पर वापस भेजना है।

संवेदनशीलता की जरूरत | फैसला परोक्ष रूप से यह भी बताता है कि इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मसलों से निपटते हुए खास सावधानी की जरूरत है। ताकतिलक हितों से निर्देशित राजनीति इस मामले में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। फैसला भले असम के संदर्भ में दिया गया हो, लेकिन अवैध प्रवासियों का मुद्दा कई और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। उम्मीद करें कि इस फैसले की रोशनी में अन्य क्षेत्रों में भी सभी संबंधित पक्ष विवाद को भड़काने के बजाय सुलझाने वाला नजरिया लेकर आगे बढ़ेंगे।

पिछली एक सदी में आकार लेती बहसों को इन पुरस्कारों ने नए ढंग से रेखांकित किया है

कइयों को असहज क्यों कर गए नोबेल

चंद्रभूषण

इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार जापान में एटम बमों से पीड़ित लोगों के संगठन निहोन हिदान्क्यो के लिए घोषित हुआ। जो लोग 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिरे अमेरिकी बमों के विस्फोट की सीधी जद में आए, वे तो भाप बन गए। पर ऐसे बहुत सारे लोग, जो बमों की भाप से काफी दूर थे, उन्होंने रेडियोधर्मी विकिरण का कहर झेला। देर-सबेर तमाम बीमारियां उन्हें पकड़ती रहीं। जापानी भाषा में उनके लिए एक साझा नाम है- 'हिबाकुशा'। निहोन हिदान्क्यो हिबाकुशा लोगों का ही संगठन है और इसके सदस्यों की औसत उम्र 86 साल है।

एटम बम से पीड़ित लोगों के संगठन को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

अंडरग्राउंड सचाई | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान पर दस साल के लिए अमेरिका का कब्जा था और यह कब्जा हटने के बाद भी साल्टों-साल वहां अमेरिकी रिंदु ही राज करते रहे। नतीजा यह हुआ कि हिबाकुशा लोग जापान में एक तरह की अंडरग्राउंड सचाई बनकर रह गए। निहोन हिदान्क्यो न केवल उनके दुख सार्वजनिक करने का मंच बना, बल्कि समूचे जापान में लोकतांत्रिक साहस का बीज-संगठन भी बन गया।

सुनाई खरी-खरी | इस संगठन की दमदारी का ही नतीजा है कि नोबेल मिलने के बाद इसके प्रतिनिधियों ने न तो अतिशय विनम्रता दिखाई, न ही पीठ पर आकर अच्छी-अच्छी बातें बोलीं। इसके बजाय ये खरा बोलते ही दिखे। जैसे यह कि इस बार पीस नोबेल के वाजिब हकदार फलस्तीन के वे कार्यकर्ता हैं जो अपने खून सने बच्चों को छाती से लगाए माताओं के साथ बमबारी के बीच भी खड़े हैं। स्वाभाविक था कि इसाइल ने उनकी निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऐसा बयान जारी किया कि दुनिया में युद्ध और एटमी खतरे के फैलाव को लेकर वे लगातार सजग हैं।

करलोगारत ने रचा मानस | दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को मिले साहित्य के नोबेल का रिश्ता भी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ठेठ पूरब में बने तानाशाही वाले माहौल के साथ जुड़ता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापानी फौजों के हटने के साथ ही कोरिया में गृहयुद्ध के बीज पड़ गए। 1953 में दोनों खेमों के बीच हुई संधि के तहत उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का गठन हुआ। तब से लेकर 1990 तक दक्षिण कोरिया में तीन अमेरिका संरक्षित तानाशाहों का शासन चला- सिंगमान री, पार्क चुंग ही और चुन डू ह्वान। इनमें तीसरे वाले के उभार के दौरान ग्वांग्जू शहर में हुई कत्लोगारत ने लेखिका हान कांग का बचपन रचा।

दमन की तस्वीरें | अतिशय संवेदनशील भाषा के लिए चर्चित हान कांग अपने काव्यात्मक गद्य की पैदाइश के लिए जिस घटना को जिम्मेदार बताती हैं, वह किसी आंदोलन में सीधी भागीदारी की नहीं है। वैसे भी, 1979 में ग्वांग्जू शहर में हुए छात्र उभार के समय वे वहां थीं जरूर, लेकिन उनकी उम्र तब सिर्फ आठ साल थी। यह एक संयोग ही था कि दमन की कुछ तस्वीरें उनके हाथ लग गईं, जो इतनी भयानक थीं कि कोई जानवर भी इंसान के साथ वैसा सलूक न करे। एक तस्वीर एक लड़की के चेहरे में भुंकी हुई संगीन की थी।

इसलिए हैं खास

- एटमी त्रासदी की याद दिलाते हैं
- आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का साया
- दमन से उपजे लेखन को सम्मान

बचपने में दिखे चेहरे | हान कांग कहती हैं, ये तस्वीरें अगर वे सयानी उम्र में देखतीं तो शायद इस नतीजे पर पहुंचतीं कि पुलिस-फौज इतनी ही क्रूर संस्थाएं हैं। लेकिन सज्जन्त बच्चों के हमले में मारे गए युवा आंदोलनकारियों के कटे-फटे चेहरे जितने बचपने में उन्हें दिख गए, उससे उनके दिमाग में यह धारणा बनी कि इंसान अपने से कमजोर लोगों के प्रति इतना बेरहम हो सकता है। किस्से के रूप में यह हादसा उनके दो बाद के उपन्यसों 'ह्यूमन ऐक्ट्स' और 'वी डू नॉट पार्ट' में आता है, पर उनका लेखकीय मन यहीं से बनना शुरू हुआ।

गुलामी से उपजी अमीरी | अर्थशास्त्र के लिए स्वीडन के बजाय नॉर्वे की ओर से दिया जाने वाला नोबेल स्मृति पुरस्कार इस साल जिन तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को हासिल हुआ है, उनकी छवि इस सदी की शुरुआत से ही उपनिवेशवाद पर काम करने वाले अर्थशास्त्रियों की है। डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिंसन ने अपने लंबे शोध से इस धारणा का खंडन किया है कि राष्ट्रों की समृद्धि में अंतर उनकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पैदा होता है। वे साबित करते हैं कि इस अंतर में मुख्य भूमिका औपनिवेशिक अतीत की है। यूरोपीय मुल्कों के लंबे राज का नतीजा है कि सत्रहवीं सदी तक दुनिया की सबसे अमीर समझी जाने वाली जगहें आज सबसे गरीब जगहों में गिनी जाती हैं और आगे भी उनकी नियति में कोई तब्दीली बहुत मुश्किल से ही आ पाएगी।

AI का प्रभाव | विज्ञान के तीनों नोबेल पुरस्कारों की चर्चा इस बार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जबरदस्त प्रभाव के लिए हो रही है, हालांकि AI और ANN (आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क) के नाम पर नोबेल सिर्फ भौतिकी में ही दिया गया है। रसायनशास्त्र के नोबेल का आधा हिस्सा गूगल डीपमाइंड के दो वैज्ञानिकों को मिला है, जिन्होंने AI का इस्तेमाल करते हुए 20 करोड़, यानी लगभग सारे ही ज्ञात प्रोटीनों की संरचना खोलकर रख दी है। इसका बाकी हिस्सा भी केम्ब्रिज़ोनल मॉडलिंग के जरिए ऐसे प्रोटीन तैयार करने के लिए दिया गया है, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते। इससे दवा निर्माण के अलावा मैटीरियल साइंस में भी एक नई क्रांति आ सकती है।

भविष्य का मेडिकल साइंस | मेडिकल साइंस का नोबेल माइक्रो RNA की खोज और इसके कामकाज का खाका खींचने के लिए दिया गया है। शरीर के हर हिस्से की कोशिकाएं वहां मौजूद कोई खास प्रोटीन ही क्यों बनाती है, इसकी समझ इस लंबी रिसर्च के जरिये बनी है। यूं कहें कि यह भविष्य की मेडिकल साइंस की नींव रखने जैसा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

कितना सफल होगा DNA कंप्यूटर का सपना

मुकुल व्यास

DNA के लंबे-लंबे अणुओं में पृथ्वी पर जीवन की सूचनाएं तो हैं ही, साथ ही समस्याओं को हल करने की प्रणाली भी है। DNA की इन खूबियों से प्रेरणा लेकर इंजिनियर एक ऐसा जैविक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो DNA में डेटा रेकॉर्ड कर सके। ये एक ऐसा सिंथेटिक सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ही समय में डेटा स्टोर करने के साथ-साथ दूसरे कार्यों को भी अंजाम दे सके। नई रिसर्च ने दिखाया है कि DNA से दोनों तरह के काम कराए जा सकते हैं।

कंप्यूटर मास्टर | DNA के जैविक अणुओं यानी न्यूक्लिक एसिड की शृंखला से सब तरह के कंप्यूटिंग हो सकती हैं। इन कार्यों में डेटा को स्टोर करने, पढ़ने, मिटाने, ट्रांसफर करने और फिर से लिखने के अलावा इन कार्यों को प्रोग्राम करने लायक बनाना और दोहराना शामिल है। एक पारंपरिक कंप्यूटर इसी तरह काम करता है। नॉर्थ कैरोलाइना स्टेट यूनिवर्सिटी (एनसी स्टेट) और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि उनका नया न्यूक्लिक एसिड ढांचा DNA कंप्यूटिंग की बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। इसमें अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लैक्ट जैविक मशीनें बनाने की क्षमता है।

लड़ियों में डेटा | इस अध्ययन से जुड़े जीववैज्ञानी अल्फर्ट केंग ने कहा कि पहले यह सोचा गया था कि DNA लंबे समय तक डेटा स्टोरेज के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाने वाले ऑपरेशन की पूरी शृंखला को शामिल करने वाली DNA तकनीक विकसित करना मुश्किल या असंभव होगा। हमने प्रदर्शित किया है कि ये DNA-आधारित तकनीकें व्यावहारिक हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है। DNA जीवों के लिए एक कोड बेस के रूप में काम करता है, जो जैविक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है। फिर भी सिद्धांत रूप में रासायनिक लड़ी सूचना के किसी भी सीक्वेंस की नुमाइंदगी कर सकती है। वर्षों से वैज्ञानिक DNA की मुक्त लड़ियों में सभी प्रकार के डेटा भरने का तरीका ढिवेलप करने में जुटे हुए हैं।

कॉपी-पेस्ट | नए अध्ययन में रिसर्चर अणुओं को छोटे वृक्ष जैसी संरचनाओं पर स्टोर करने में सफल रहे। इन संरचनाओं को डेंड्रिमोलीड कहा जाता है। एक खास बात यह है कि रिसर्चर DNA कोड को और भी आसानी से संपादित करने में सक्षम हो गए। इस सिस्टम की खासियत यह है कि डेंड्रिमोलीड संरचनाओं में संग्रहीत सूचनाओं में अंतर किया जा सकता है। इस वजह से यह डेटा को RNA (राइबोन्यूक्लिक एसिड) फॉर्म में कॉपी करने में सक्षम बनाता है। मूल DNA फाइल या स्टोरेज माध्यम को नुकसान पहुंचाए बगैर इस डेटा को प्रॉसेस किया जा सकता है। इससे भी बेहतर बात यह है कि पॉलिमर संरचनाओं की तुलना में डेंड्रिमोलीड संरचनाओं की शाखाएं DNA की जानकारी को संरक्षित करने में भी मदद करती हैं। एक विश्लेषण से पता चला कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर डेंड्रिमोलीड पर संग्रहीत DNA की लड़ी का जीवन 500 साल का होगा। कम तापमान पर यह अवधि लाखों साल हो सकती है।

AI image

ज्ञान-विज्ञान

विशाल स्टोरेज | DNA आधारित सिस्टम का उपयोग करके, एक हजार लैपटॉप में समा जाने वाले डेटा को एक पेंसिल इरेजर जितनी जगह में विश्वसनीय रूप से स्टोर किया जा सकता है। इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि नया सिस्टम हमें DNA डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग कार्यों की पूरी शृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाता है।

सदियों तक टिकाऊ | जैविक मशीनें शतरंज और सुडोकू की सरल प्रॉब्लम्स को हल करने में सक्षम हैं। DNA के सूक्ष्म अणुओं की यह खूबी प्रभावशाली है। जैविक कंप्यूटर भले ही इस समय शक्तिशाली या तेज न हों, लेकिन DNA स्टोरेज और कंप्यूटिंग ने बहुत छोटी जगह में विशाल मात्रा में जानकारी को एकत्र करने का करिश्मा दिखाया है। वह भी ऐसे माध्यम पर जो संभावित रूप से समस्त सभ्यताओं से अधिक समय तक चल सकता है। रिसर्चरों का मानना है कि उनका अध्ययन आणविक कंप्यूटिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

हमारे भीतर चल रहा तीन शक्तियों का अनोखा खेल

भयंक मुरारी

तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है, 'ईश्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी।' यानी यह आत्मा उसी सच्चिदानंद को निरंतर खोजती रहती है, लेकिन माया के अवरोध की वजह से उसे प्राप्त नहीं कर पाती। जब माया का आवरण हट जाता है, तो सच्चिदानंद के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। प्रकृति माया है और आत्मा हम। परमात्मा ही परम पुरुष है। प्रकृति की माया तमस है, तो आत्मा गतिमान होकर रजोगुण का धर्म अपनाती है। परमात्मा रूपी सत्व को जीवन में अपनाकर ही शिखर की यात्रा संभव है। सच्चिदानंद का सत भी परमात्मा की तरह सदैव शुद्ध रहता है। वह सभी बाहरी परिवर्तन और प्रभाव से परे स्थिर है। यह पूर्ण है और सत्य भी। वह सदैव क्रियाशील है। सत जो पूर्ण है, वह चित एक विशुद्ध चेतना में है। जो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है और जो सदैव जागरूक व अपरिवर्तनीय प्रकाश में रहता है। सत और चित का स्वरूप आनंदमय है। सभी अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना से परे विशुद्ध आनंद में रहता है। परमात्मा ही तीन गुणों में प्रकृति, शरीर, जीवन और पदार्थ में प्रकट होता है।

मनुष्य के भीतर जो भी घटता और बढ़ता है, वह भी तीन शक्तियों का खेल है। जन्म के साथ लगातार निर्माण, निर्माण में जो अनुपयोगी होता है, उसका विखंडन करना और इसके बीच का संतुलन ही तो जीवन है। अगर यह नहीं हो तो जीवन में विस्फोट हो जाए। न केवल निर्माण और न ही संहार जीवन है। हरेक अणु में सत, रजस और तमस की गति हमारे अंदर चल रही है। तमस रोकता है, रजस गति देता है और सत्व संतुलित करता है। यही तीन गुण हमारी चेतना की तीन अवस्थाओं- जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था से भी संबंधित हैं। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के-फुल्के, अधिक सजग व बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्ती, आलस्य और भ्रम के शिकार हो जाते हैं।

हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है, जिनमें तीन गुणों का वास होता है। तमोगुण का कारण पृथ्वी तत्व, रजोगुण का कारण जल तत्व और सतोगुण का कारण आकाश तत्व होता है। भोग की वृत्ति से तमो गुण, अहंकार की वृत्ति से रजो गुण और वैराग्य भाव से सतोगुण आता है। हमारे शरीर में तीन नाड़ियां होती हैं- इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा अपनी सक्रियता में हमें शांत, शीतल और अंतर्मुखी रखती है। पिंगला के कारण मनुष्य तर्क, वितर्क, श्रम और बहुमुखी प्रतिभा को प्रकट करता है। वहीं, सुषुम्ना से स्थिरता, वैराग्य और शून्यता की स्थिति आती है। संसार में तीन तत्व हैं- प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। सच्चिदानंद अपनी क्रियाशीलता में प्रकृति का स्वरूप धारण कर पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र और जीवन का कारण बनता है। इस प्रकृति को क्रियाशील रखने वाला तत्व पुरुष प्रधान है, जिसकी डोर परमात्मा से जुड़ी होती है। गति और ठहराव के बीच संतुलन जो करता है, उसे विष्णु कहा गया। उसके संतुलन से जीवन है। इसके कारण ही जीवन को आनंदमय बताया गया है।

बात बराबर की

भाषा में भेदभाव

शैलेंद्र पांडेय

प्याज महंगा है या महंगी, दाल जमता है या जमती और रोड़ बनता है या बनती? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जवाब आपका या के इधर वाला हो या उधर वाला, इससे उस चीज पर तो कोई फर्क पड़ने से रहा। प्याज का दाम आसमान चढ़ ही चुका है, तो इसके नर या मादा बन जाने से क्या असर पड़ने वाला है। इसे तो चाद देखिए बस एक उदाहरण के रूप में कि कैसे हमारी आदत बन चुकी है हर चीज को जेंडर के दायरे में बांधने की। जीवित तक तो ठीक, लेकिन गाड़ी-मोटर, मशीनें, हथियार, ओहदा-ओहदेदार, खेल-मैदान, गांव-कस्बा-शहर, व्रत-त्योहार - कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसका लिंग न निर्धारित किया हो हमने। अंतर बस यह कि किसी भाषा में यह हरकत ज्यादा है और किसी में थोड़ी कम। बच्चे को भाषा ज्ञान देते समय यह भेदभाव भी दे देते हैं हम। फिर वह हर चीज को उसके जेंडर के हिसाब से तौलने लगता है। इस लैंगिक पूर्वाग्रह की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पता भी नहीं चलता हम किसी पूर्वाग्रह के शिकार हैं। यह सामान्य आदत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो भाषाएं सैकड़ों-हजारों बरसों में विकसित हुईं, उन्हें एक झटके में तो बदला नहीं जा सकता। हां, शायद इन भाषाओं के लिए उन भाषाओं के उदाहरण कुछ काम आ सकें, जिन्हें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कहा जाता है।

जेंडर न्यूट्रल का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मर्द और औरत का भेद पूरी तरह मिटा दिया गया है इन भाषाओं में। इसका मतलब है ऐसी लचीली भाषा, जहां संवाद करते समय जेंडर पर अधिक ध्यान नहीं देना पड़ता। हमारी अपनी ऐसी सबसे जानी-पहचानी भाषा है बंगाली। कई सामान्य वाक्यों में यहां लिंग के आधार पर अंतर नहीं होता। इसी तरह पुलिस, डॉक्टर और शिक्षक जैसे कई ओहदे जेंडर में नहीं बंधे। फिलीपींस में बोली जाने वाली प्राचीन Tagalog को भी जेंडर न्यूट्रल मानते हैं। इसमें बहुत से शब्द और वाक्य संरचनाएं लिंग के आधार पर नहीं बंटतीं। महिला और पुरुष, दोनों के लिए एक ही सर्वनाम इस्तेमाल होता है, 'Sia'। जापानी, चास्क, पर्शियन और कुछ हद तक चीन की मैंडरिन को भी जेंडर न्यूट्रल माना जाता है।

किसी भी भाषा का लक्ष्य है कम्युनिकेशन, न कि कंपन्यूजन या बायस्ड बनाना। अंग्रेजी ने पांच साल पहले यह पहचाना कि दुनिया बस मर्द और औरत में नहीं बंटी। उसने They को सिंगल पर्सन के लिए सर्वनाम के रूप में अपनाया। यह केवल एक शब्द की नई पहचान नहीं थी, बल्कि इसने एक पूरी कम्युनिटी को अपनी पहचान दे दी, जो खुद को आदमी या औरत के रूप में बांटना नहीं चाहती। तो बराबर की बात करने से पहले क्यों न भाषा में थोड़ी बराबरी लाई जाए, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर जमता नहीं।

एकदा

आलोचकों की कृपा

इटली के फ्लोरेंस शहर में 1386 में जन्मे प्रसिद्ध मूर्तिकार Donatello को सेंगमरमर और कांस्य की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी। उनकी मूर्ति कला प्रारंभिक पुनर्जागरण शैली के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कांस्य प्रतिमा 'डेविड' आज भी फ्लोरेंस के बारोलो संग्रहालय में मौजूद है। जब यूरोप में कला संस्थानों की तरफ से कलाकारों के कामों पर पाबंदी लगाई गई थी, उस समय इस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने कलात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठाई थी। फ्लोरेंस में उनकी कलाकृतियों की आलोचना हुआ करती, लेकिन वह कभी इस बात की परवाह नहीं करते थे। वह अपने काम में हमेशा सुधार करने का प्रयास करते रहते। एक बार Donatello को कुछ मूर्तियां बनाने के लिए पीसा बुलाया गया। वहां जाकर उन्होंने कुछ अद्भुत मूर्तियां बनाईं। डोनाटेलो को हर तरफ से वाहवाही मिलने लगी। उनकी कला को देखते हुए उन्हें पीसा में ही कुछ और मूर्तियां बनाने का काम मिला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डोनाटेलो के एक साथी ने जब मूर्ति न बनाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मुझे डर है कि अपनी प्रशंसा सुनते-सुनते कहीं मैं इतना आत्म-संतुष्ट न हो जाऊं कि मेरे अंदर अहंकार आने लगे, और कहीं यह मेरी कला के विकास में बाधक न हो जाए।' उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, 'फ्लोरेंस में मैं अपने आलोचकों की कृपा से कभी आत्म-संतुष्ट नहीं हो पाया और दिनों-दिन मेरी कला में निखार आता चला गया।' एक मूर्तिकार के रूप में उन्होंने दुनिया को यही संदेश दिया कि प्रशंसा से मिली आत्म-संतुष्टि कला की प्रगति को रोक देती है।

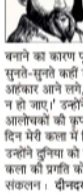
Subrata Dhar

संकलन : दीनदयाल मुरारका

MVA में सीटों के बंटवारे पर समझौता जल्द, 75% पर दलों में हो चुकी है बात

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहां सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच कटि का मुकाबला होने की उम्मीद है। इन चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी की रणनीति क्या है, उसका अजेंडा क्या है, वादे क्या होंगे? यह भी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों का कितना असर होगा महाराष्ट्र में। इन तमाम मसलों पर **नरेन्द्र नाथ** ने बात की शिवसेना ठाकरे गुट की नेता और राज्यसभा सांसद **प्रियंका चतुर्वेदी** से। पेश है बातचीत के अहम अंश :

■ **अभी हरियाणा में BJP ने सरप्राइज जीत हासिल की। उसके बाद वह कॉम्पिटेंट लग रही है। महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में जीत का कितना विश्वास है? मनोबल पर कोई असर पड़ा?**

जो हरियाणा में हुआ है वह उम्मीद से परे है, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र में उसका किसी तरह से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र के हालात से BJP हो या महायुति गठबंधन, सब वाकिफ हैं। इन्होंने परिवार की लड़ाई परिवार से कराई है, जो महाराष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, यहां जो दिल्ली से झुका है या ही दिल्ली की कमांड पर चलता है। मगर यहां पर जो भी निर्णय हो रहे हैं, दिल्ली से हो रहे हैं, जो महाराष्ट्र की जनता अच्छे से समझ रही है। इन्होंने राज्य में उन्माद फैलाने की कोशिश की। मराठा बनाम ओबीसी किया है। हिंदू-मुस्लिम किया है।

■ **सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कब तक तीनों दलों में समझौता हो जाएगा?**

तीनों दलों की लगातार बैठकें जारी हैं। करीब-करीब 75% सीटों पर बात हो चुकी है। घोषणा जल्द होगी। डिस्कशन पॉजिटिव-ये में हो रहा है।

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

■ **महाविकास आघाड़ी की ओर से चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार घोषित करने को लेकर क्या रणनीति बनी?**

हमारी पार्टी और प्रमुख उद्धव ठाकरे का यह मानना है कि हमें एक नाम घोषित करना चाहिए और उनको पूरा कैपेन लीड करना चाहिए। हो सकता है कि स्ट्रैटिजी के अनुसार गठबंधन के बाकी दो पक्षों को लगे कि यह सही नहीं रहेगा। इस मामले में अभी विचार चल रहा है।

■ **इस चुनाव में आपकी पार्टी और गठबंधन के लिए NDA सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा?**

महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों में दे दी, उसे किस तरह वापस लाया जाए। महाराष्ट्र कर्ज में डूबा है। बेरोजगारी तीसरा बड़ा मुद्दा है। चौथा बड़ा मुद्दा है- किस तरीके से मुंबई की खरी जमीन अडाणी ग्रुप को दी जा रही है। इसके अलावा महंगाई और करप्शन बड़ा मुद्दा है ही। खुलेआम महाराष्ट्र की ट्रेजरी लूटी जा रही है, असंवैधानिक तरीके से बिना टेंडर BJP से जुड़े MLA को काम दिया गया।

■ **महाराष्ट्र में BJP, शिंदे सेना और अजित पवार गुट को विश्वास है कि महिलाओं को देने वाली राशि योजना के बल पर वे लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे। पूर्व में भी इस योजना का लाभ मिला है। इसे किस तरह काउंटर करेंगे?**

लोकसभा हार के बाद राज्य सरकार ने देखा कि यह महाझूठा गठबंधन जनता को पसंद नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि पैसे देकर जनता का मूड बदल सकते हैं। पर यहां की महिलाएं बहुत सक्षम हैं। जनता जानती है कि महाराष्ट्र पर जो 90 हजार करोड़ का कर्जा बढ़ रहा है, उसकी भरपाई उनी को करनी पड़ेगी।

■ **चुनाव में सबसे अहम वादा क्या होगा?**

सबसे अहम वादा तो यही है कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। जो अभर्ष हुआ है, उस अधर्म को खत्म करना है। हमारे लिए सबसे बड़ा वादा है कि हम इंडस्ट्री वापस महाराष्ट्र में लाएंगे। रोजगार के माध्यम बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे।

■ **प्रकाश आंबेडकर और बाकी छोटे-छोटे दलों से गठबंधन नहीं हो पाने का कितना नुकसान होता है?**

वंचित बहुजन आघाड़ी और हमारा अलायंस हुआ था। लोकसभा चुनाव के वक्त वो अलायंस से बाहर आए थे। उन्होंने I.N.D.I.A. की एक रैली अटेंड करते वक्त कहा था कि एक साथ लड़ेंगे, लेकिन किसी कारणवश निर्णय लिया कि हमारे साथ नहीं लड़ेंगे। उम्मीद अभी भी है कि जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि इनको हराना है, महाराष्ट्र के हित में फैसला लेना है, वो हमारे साथ शामिल होकर भ्रष्टाचारियों को हराएंगे। आखिर में निर्णय उनका होगा।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

एकजुटता जरूरी

17 अक्टूबर का लेख 'उमर से आस' पढ़ा। पांच साल बाद जम्मू कश्मीर को एक निर्वाचित सरकार मिली है। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सुरेंद्र रैना को उपमुख्यमंत्री बनाया। गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने की बात कही है। देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर के लोगों ने नैशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत देकर उसे राज्य को विकास की डगर पर आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है उमर अब्दुल्ला इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आतंकवाद पर भी शिकंजा कसेगा। सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है।

पैथर तोमर, किशन गंज

राजनयिक बुलाना सही

यह पत्र 17 अक्टूबर के लेख 'कनाडा ने क्यों छेड़ा फिर पुराना राग' से संबंधित है। कनाडा में अगले वर्ष चुनाव होने हैं और वहां जस्टिन ट्रूडो की सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को देखते हुए उसके फिर से सत्ता में आने के आसार कम ही हैं।सब जानते हैं कि खालिस्तानियों ने भारत को कई जख्म दिए हैं। इसलिए भारत का कनाडा से राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला बिल्कुल सही है। अमेरिका को भी बिना सबूत बहकावे में आकर बयान नहीं देना चाहिए। इन देशों को समझ लेना चाहिए कि भारत बिना वजह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

साइबर सेफ्टी

2030 तक संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सस्ते दामों पर 5जी सर्विस उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 5जी से डिजिटल बदलाव में मदद मिली। डिजिटल सुविधा गांव-गांव पहुंची। 6जी का फायदा आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सबको मिलेगा। भारत में हर व्यक्ति औसतन 6-7 घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटरनेट आज के समय में कितना जरूरी है। साथ ही साइबर सेफ्टी भी जरूरी है।

माधुरी, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बिहार में जहरीली शराब पीने से 28 की मौत- एक खबर

- कहीं राज्य सरकार शराबियों को सबक सिखाने की कोई नई योजना तो नहीं ले आई।

रामीत कुमार

नभ टाइम्स, नई दिल्ली, ISSN 2321-0362 रजिस्ट्रेशन सूचना: रिजिस्ट्रार न्यूज़पेपर्स के लिए संपादक एवं प्रकाशक सूचना, भारतीय प्रेस परिषद, दिल्ली। मुद्रक: मुद्रक, प्रकाशक, संपादक: राजेश कालरा द्वारा टाइम्स हाउस, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **प्रकाशन अधिष्ठान टाइम्स हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001** और **नॉर्थ ब्लॉक** (पेज 2-4, रीडर्स ब्लॉग, इंडियाज़ टॉप, इंडियाज़ मोस्ट, रीडर्स मेल, एकदा, विचार, संपादकीय, बात बराबर की) से मुद्रित। फोन : 23322222 फैक्स: 23322227 संपादक: राजेश क

चुनावों की घोषणा

जनता की इच्छा

चुनावों की घोषणा और उनके परिणाम लोकतंत्र में जनता की इच्छा जानने का माध्यम बनते हैं। दो राज्यों में विधानसभा चुनावों तथा कुछ उप-चुनावों की घोषणा हुई है जिससे चुनाव का मौसम फिर आ गया है। 2024 में चुनावों का अंतिम दौर नवंबर में होगा। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू होगी। झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इसके साथ ही अनेक लोकसभा उप-चुनावों की घोषणा हुई है जिनमें केरल से वायनाड भी शामिल है। राहुल गांधी द्वारा सीट छोड़ने से यहां उप-चुनाव की जरूरत पड़ी है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ व विपक्षी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उनकी शक्ति परीक्षण का प्रमुख क्षेत्र बनेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी-भाजपा को 'महा विकास अघाड़ी'-एमवीए गठबंधन से भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसमें शिवसेना-यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-रांकापा और कांग्रेस शामिल हैं। एमवीए आर्थिक परेशानी तथा प्रशासनिक विफलता जैसे मुद्दों पर जनता का असंतोष भुनाने का प्रयास कर रही है और वह आंतरिक तनावों के बावजूद स्वयं को एकजुट मोर्चे के रूप में पेश कर रही है।

झारखंड में भी मुकाबला कांटे का है जहां सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा-जेएमएम व कांग्रेस का गठबंधन भाजपा की चुनौती का सामना कर रहा है। सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन का विश्वास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता तथा उनके द्वारा लागू समाज कल्याण योजनाओं पर है। भाजपा यहां मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कानून-व्यवस्था तथा आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दे उठा रही है। विधानसभा चुनावों के साथ 13 नवंबर को पंजाब की चार विधानसभा सीटों-डेरा बाबा नानक, छब्बेवाल, गिद्दरबाहा व बरनाला में उप-चुनाव होंगे। ये उप-चुनाव क्षेत्र में वर्तमान राजनीतिक भावनाओं को प्रकट करेंगे जिनसे संभवतः व्यापक चुनावी संघर्षों का आधार तैयार होगा। इसके साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उप-चुनाव एक और महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। आमतौर से अनुमान लगाया जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी। इससे कांग्रेस की प्रचार रणनीति में व्यापक परिवर्तन आएगा। भारत में चुनावों का समय न केवल राजनीतिक दलों की गतिविधियां बहुत तेज करने वाला होता है, बल्कि यह निर्वाचन आयोग तथा सरकारी मशीनरी की कड़ी परीक्षा भी लेता है। देश में चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रकार शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भी बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनाव तथा उप-चुनाव भारत में विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य की तस्वीर सामने रखेंगे। दोनों राज्यों में 'कांटे की टक्कर' वाले इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आ सकते हैं। ये राजनीतिक परिदृश्य विभिन्न पार्टियों की चुनावी रणनीति, क्षेत्रीय मुद्दों तथा विभिन्न नेताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों से प्रभावित होंगे। इन राज्यों के चुनावी परिणाम देश में भावी राजनीति की भी दिशा देंगे। राजनीतिक विश्लेषक अभी से इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों के बारे में अनुमान लगाने लगे हैं, लेकिन मतदाताओं के मन की थाह पाना आसान नहीं है। इन चुनावों में मतदाता राजनीतिक पार्टियों की किस्मत तय करेंगे और उनके द्वारा पेश एजेंडे पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाएंगे।

हरियाणा में कांग्रेस की पराजय

हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने न केवल पार्टी के उभार का विमर्श ठंडा कर दिया है, बल्कि इसने गठबंधन राजनीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता भी उजागर की है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने न केवल पार्टी के उभार का विमर्श ठंडा कर दिया है, बल्कि इसने गठबंधन राजनीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता भी उजागर की है। हरियाणा में पराजय के कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 'इंडिया' गठबंधन में सहयोगियों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने हालिया हरियाणा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके कारण दस साल सत्ता में रहने के कारण पैदा 'सत्ता-विरोधी भावनाओं' के बावजूद भाजपा को तीसरी बार विजय प्राप्त कर सरकार बनाने का अवसर दे दिया है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अधिकांश एक्जिट पोलों ने कांग्रेस की स्पष्ट विजय का अनुमान लगाया था, पर इसके बावजूद भाजपा विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 48 जीतने में सफल हुई। भाजपा की इस भारी विजय का अनुमान संभवतः पार्टी नेताओं को भी नहीं था। यदि हरियाणा में कांग्रेस एक्जिट पोल अनुमानों के अनुसार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल होती तो इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं में उत्साह पैदा होता तथा देश भर में उसकी छवि में और व्यापक सुधार होता। लेकिन इसके एकदम विपरीत कांग्रेस हाल में अपने आंतरिक टकरावों के कारण पांचवां विधानसभा चुनाव हार गई है। इसके पहले वह पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देख चुकी है।

कांग्रेस की हरियाणा में इस पराजय से अब यह निश्चित नहीं है कि 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी भविष्य में भाजपा के खिलाफ मुकाबले के लिए एकजुट होंगे। ऐसे में बहस हो रही है कि यदि कांग्रेस का हरियाणा में आम आदमी पार्टी-आप से गठबंधन होता तो क्या वह चुनाव जीतने में सफल होती। इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति तथा 'इंडिया' के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, हरियाणा में कांग्रेस की पराजय का प्रभाव महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। हरियाणा चुनाव परिणाम का तत्काल प्रभाव आगामी दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में सीट-साझा समझौतों पर पड़ सकता है। इन चुनाव परिणामों के बाद आप ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा ही कर दी है।

तीसरा, यह अनिश्चित है कि क्या कांग्रेस और आप का भविष्य में कोई गठबंधन होगा क्योंकि आप ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अपने लचीलेपन तथा सुलह-समझौते की नीति के कारण 'इंडिया' ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारना था ताकि भाजपा-विरोधी वोटों में विभाजन को रोका जा सके। गठबंधन ने विवादास्पद मुद्दों को पीछे छोड़ कर अपने कामकाज में अच्छा प्रबंधन किया था। 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों ने मोदीतंत्र से भाजपा को हराने का लक्ष्य सामने रखा था और वे एक सीमा तक सफल भी हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहुमत घटा और वह जदयू व टीडीपी की सहायता से ही सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने गठबंधन के भीतर स्थिति एकदम बदल दी है। इस पराजय के कारण अब 'इंडिया' में गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस पर बढ़त मिल गई है। गठबंधन सहयोगी अब संभवतः ज्यादा कठोर दृष्टिकोण अपनायेंगे जिससे कांग्रेस को झुकने पर मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि, अब तक किसी ने यह नहीं कहा है कि 'इंडिया' गठबंधन समाप्त हो गया है।

इसके उलट परिणाम आने के अगले दिन समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने अपने बयान से संकेत दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश ने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया समूह बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा।' लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी-आप ने कहा है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, जबकि उसने तीन महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

'इंडिया' समूह में अन्य गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वह अति-विश्वास से भरी थी तथा उसने सीट-साझा के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दुगनी कर ली थी और वह उत्साह से भरी थी, लेकिन हरियाणा में पराजय के बाद वह कमजोर हुई है और उसे भारी झटका लगा है। अधिकांश एक्जिट पोलों ने हरियाणा में कांग्रेस की शानदार विजय की भविष्यवाणी की थी क्योंकि भाजपा दस साल की सत्ता-विरोधी लहर का सामना कर रही थी और जनता का एक हिस्सा उसके कामकाज से निराश था। लेकिन भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से न केवल हरियाणा में लगातार तीसरी बार विजय पाई, बल्कि उसका यह प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। किसी पार्टी ने अब तक इस ग्रामीण-प्रभुत्व वाले राज्य में लगातार तीसरी बार विजय पाई है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना-उद्धव तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-रांकापा के बीच सीट-साझे पर बातचीत जारी है। हरियाणा में पराजय के बाद कांग्रेस को सीट-साझा फार्मूले के प्रति ज्यादा विनम्रता दिखानी चाहिए तथा उसे चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित करने की शिवसेना की मांग पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। जहां तक हरियाणा विधानसभा चुनाव का सवाल है, आप को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली और उसे लगभग केवल 1.78 प्रतिशत वोट ही मिले। लेकिन यदि कांग्रेस ने आप से गठबंधन किया होता तो ये वोट निश्चित रूप से 'इंडिया' को मिलते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस ने छोटी पार्टियों तथा उनके द्वारा किए जा रहे गठबंधन प्रयासों को अनदेखा किया।

तृणमूल कांग्रेस, आप, शिवसेना-उद्धव, नेशनल कान्फ्रेंस, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा अन्य ने कांग्रेस की आलोचना की है कि वह अपनी गलतियों के कारण हरियाणा में पराजित हुई। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' ने अपने संपादकीय में बुधवार को कहा, 'किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा में भाजपा सरकार फिर आ जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अति-आत्मविश्वास तथा स्थानीय कांग्रेस नेताओं का घमंड पार्टी की पराजय का कारण बना।' ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में सीट-साझा के लिए लोकसभा चुनाव का फार्मूला दुहराना जरूरी हो गया है। अब अधिकांश सहयोगियों के साथ सीट-साझे में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहेगा। 'इंडिया' गठबंधन में व्याप्त वर्तमान सोच से कांग्रेस के अपने सहयोगियों के साथ संबंध प्रभावित होंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व पराजय से स्पष्ट है कि अब विपक्ष हालिया विधानसभा चुनावों में पराजय के और झटके झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को मुख्यतः उन 286 सीटों पर ही ध्यान देना चाहिए जहां वह भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ 'स्ट्राइक रेट' 29 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जबकि यह 2019 में केवल 8 प्रतिशत था। इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 2024 में कांग्रेस ने केवल 286 सीटों पर भाजपा से मुकाबला किया, जबकि इन सीटों की संख्या 2014 में 370 थी।

कांग्रेस को 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने साझीदारों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण ही विजय मिली थी। वर्तमान समय में गठबंधन को व्यापक बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। उसे यह अवश्य समझना चाहिए कि कोई साझीदार चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके लिए जरूरी है। कांग्रेस ने अतीत में अनेक 'चिंतन शिविर' आयोजित किए हैं, पंचमढ़ी और शिमला इनके अच्छे उदाहरण हैं। वर्तमान समय की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित व अभूतपूर्व पराजय के बाद कांग्रेस ऐसा ही एक और चिंतन शिविर आयोजित करे।

तीव्र प्रगति के बीच स्वस्थ भविष्य का निर्माण

अश्वजीत सिंह
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

शहरीकरण, आर्थिक समृद्धि और संसाधनों का इंजन है, आधुनिकता के केंद्र में है और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक, 10 में से 7 लोग शहरों में रहेंगे, और युवा संभवतः सबसे ज्यादा आबादी वाले होंगे। भविष्य का निर्माण लगातार बढ़ते वैश्विक युवाओं द्वारा किया जाएगा, जो मजबूत, समृद्ध, टिकाऊ और जीवंत समाज बनाने और बनाने में एक गतिशील और क्रांतिकारी भूमिका निभाने के लिए अधिमन अंग हैं। हाल के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युवाओं की सार्थक भागीदारी पर जोर दिया है, क्योंकि विकास वैश्विक स्तर पर जारी रहने के दौरान स्वस्थ की दिशा में प्रगति को तेज करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण इस वर्ष के विश्व पर्यावास दिवस के संदेश से भी मेल खाता है, जो बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करने पर केंद्रित है। हालांकि, जब हम भागीदारी प्रक्रियाओं और स्थानीय नेतृत्व के अवसरों के माध्यम से नई पीढ़ी को उनके शहरी वर्तमान और भविष्य की योजना बनाने में शामिल करने की दिशा में काम करते हैं, तो उनकी स्वस्थ आजीविका सुनिश्चित करना अनिवार्य है। शहरीकरण के सकारात्मक गुण इसके भीतर मौजूद असमानताओं को भी छिपाते हैं। सभी शहरी निवासी इन लाभों का समान रूप से अनुभव नहीं कर पाते या उन तक पहुँच नहीं पाते। उदाहरण के लिए, 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत आबादी शहरी सेटअप में निवास करेगी, जिसमें 24 प्रतिशत युवा (15-29) होंगे, जो इसे अपेक्षाकृत युवा देश बनाता है।

हालांकि तेज शहरीकरण भारत की औसत घरेलू सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बाल स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना जारी रखेगा, लेकिन यह शहरी युवाओं के स्वास्थ्य को असमान रूप से प्रभावित करने की उम्मीद है, जो स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की संभावना रखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना शहरीकरण के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्वास्थ्य असमानताएँ होती हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण के साथ जेंट्रीफिकेशन बढ़ता है, युवाओं का एक बड़ा हिस्सा

शहरी झुग्गियों और कम आय वाले क्षेत्रों में रहने की संभावना है। ये क्षेत्र अलग-अलग स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझते हैं जो गरीबी, शिक्षा और रोजगार जैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों से प्रभावित होते हैं। निम्न आय वाले परिवारों और क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करने की अधिक संभावना है, जो बदले में नौकरी के अवसरों को सीमित करता है और खराब स्वास्थ्य परिणामों के चक्र को जारी रखता है। ये अनौपचारिक बस्तियाँ किसी समृद्ध पड़ोस के बगल में स्थित हो सकती हैं। फिर भी, वहाँ रहने वाले लोगों के पास सुरक्षित पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे तक पहुँच नहीं है, जो बाढ़, खुले सीवर और भीड़भाड़ के कारण जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियों के लिए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। ऐसी खराब स्वच्छता के साथ, बच्चों और युवा वयस्कों में कुपोषण की बढ़ती दर बीमारियों के बोझ को और बढ़ा देती है। संक्रामक रोगों के अलावा, निम्न आय वाले क्षेत्रों में शहरी युवा मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों के संपर्क में तेजी से आ रहे हैं, जो अक्सर खराब आहार, तनाव और शुरुआती निदान या नियमित स्वास्थ्य जांच तक पहुँच की कमी के कारण बढ़ जाती हैं। शहरी युवाओं के रहने और स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करने वाली ये पर्याप्त क्षेत्रीय असमानताएँ क्लीनिकों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के असमान वितरण के कारण भी होती हैं, जो देखभाल के विकल्पों को सीमित करती हैं। एनएफएचएस-3 के अनुसार, शहरी गरीब बच्चों में से केवल 39.9 प्रतिशत को ही पूर्ण टीकाकरण मिल पाता है, जबकि शहरी गैर-गरीब बच्चों में यह प्रतिशत 65.4 है। कम टीकाकरण दर और चल रहे स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता की कमी स्कूल में उपस्थिति और संज्ञानात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

2013 में शुरू किया गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शहरी क्षेत्रों के लिए विनियामक, सुधारात्मक और विकासात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पूरा करने में सहायक रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, एनयूएचएम ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है, जिससे शहरी गरीबों को महंगी निजी सेवाओं के बजाय सार्वजनिक सेवाओं को चुनने की अनुमति मिली है। शहरी युवा स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की अन्य पहलों में, राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) 2021 संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी के साथ संरेखित करते हुए, 2030 तक युवा विकास के लिए 10-वर्षीय दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। एनवाईपी शहरी युवाओं के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घटकों को संबोधित करके और मानसिक स्वास्थ्य को स्वीकार करके भारत के समग्र विकास और प्रगति के लिए युवा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा, सभी को लाभ पहुंचाने वाले और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले समावेशी स्वास्थ्य के निर्माण की दिशा में भारत के अग्रणी कदम को हाल ही में 2023 में जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में भी प्रमुखता मिली।

रिपोर्ट में भूख और कुपोषण को खत्म करने और अधिक स्वास्थ्य सहयोग के साथ आगे बढ़ने के तरीके शामिल हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य का सामना करते समय। जबकि ह्लऊ और ह्लक्क जैसी नीतियों ने शहरी युवा स्वास्थ्य को संबोधित करने में प्रगति की है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए और अधिक करने और लागू करने की आवश्यकता है।

कई शहरी स्वास्थ्य सेवा केंद्र अभी भी कम कर्मचारियों, संसाधनों की कमी और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले युवाओं के लिए पहुंच संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के शहरी युवा फलते-फूलते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना और निर्णय लेने में युवाओं को शामिल करना जारी रखना महत्वपूर्ण है।

आप की बात

मोदी की उपलब्धियां

गुजरात के सीएम और बाद में देश के पीएमके रूप में नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक सेवा में 23 वर्ष इसी 7 अक्टूबर को पूरे कर लिए। उनके शासनकाल में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्य हुए, जिसके चलते आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बहुत ऊंचा हो गया है। इन सालों में विपक्ष के साथ-साथ मोदी को अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के भी कटाक्ष सुनने पड़े। विपक्ष ने उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद से भी हटाने के भरपूर प्रयास किये थे। केंद्र में आने के बाद समूचा विपक्ष साम, दाम, दण्ड, भेद किसी भी प्रकार उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए छटपटा रहा है। विपक्ष ने आरएसएस से उनके संबंधों में खटास की बात भी खूब उछाली। मगर हरियाणा चुनाव परिणाम ने मोदी को पुनः सर्वशक्तिमान बना दिया और विपक्ष ठगा सा खड़ा देखता रहा। केजरीवाल की पार्टी की तो एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मोदी ने अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया है कि वह पूरे जोश के साथ काम करते रहेंगे। नरेन्द्र मोदी निन्दा और प्रशंसा की चिन्ता किए बिना न्याय के पथ पर चलते रहते हैं। इसी कारण उन्होंने इन 23 वर्षों में एक दिन छुट्टी ली और न कभी अपने काम से विरत हुए। मोदी की उपलब्धियों का लाभ देश के सबसे गरीब तबके को सीधे-सीधे मिल रहा है।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

उमर अब्दुल्ला से उम्मीद

जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई महक से गठित नेशनल कान्फ्रेंस सरकार से लोगों को भरोसा है कि वह केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्द्र सरकार के पूरे सहयोग का वादा किया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को कई नई चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा। हिंसा और आतंक में गुजरे कई दशकों के बाद राज्य में संवैधानिक रूप से लोगों ने अपनी पसंद की सरकार चुनकर उससे उम्मीद लगाई है। लोगों ने साहस दिखाकर कई दशक बाद भारी मतदान से यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य अब आतंक नहीं विकास की डगर चाहता है। राज्य सरकार को युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता को पुरा करना होगा ताकि वे असंवैधानिक गतिविधियों से दूर रहें। इसके अलावा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्राथमिकता देकर नेशनल कांफ्रेंस सरकार को केंद्र से दोस्ताना संबंध बनाने होंगे तभी वह राज्य के लिए जरूरी योजनाओं और उनके लिए आवंटित धनराशि प्राप्त कर सकेगी। उमर अब्दुल्ला अपने कैरियर के ऐसे मोड़ पर हैं, जब प्रदेश और देश के साथ ही सारी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हैं। वे जम्मू कश्मीर को भारत का स्विटजरलैंड बना सकते हैं।

- अमृतलाल मारू, इंदौर

रेलों की सुरक्षा

पिछले हादसों के बाद रेल प्रशासन व्यवस्था मजबूत करने व रखरखाव पर कठोरता से ध्यान दे रहा है। पिछली कुछ दुर्घटनाओं में मानवीय भूल, रखरखाव की शिथिल व्यवस्थाए, असामाजिक तत्वों द्वारा रेल पटरियों पर खतरनाक वस्तुएं व अवरोध रखने तथा पटरियों को नुकसान पहुंचाने जैसे कारण सामने आए हैं। नई व बेहतर रेलों के संचालन के साथ ही रेलवे प्रशासन को पटरियों, बोगियों, सिग्नल व्यवस्था आदि के रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। तकनीकी स्टाफ के साथ ही सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी है जिनमें आरपीएफव जीआरपी शामिल हैं। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए पुरानी पटरियों व बोगियों को बदलना या उनमें सुधार करना जरूरी हो गया है। यात्रियों को नई ट्रेनों के साथ अन्य सुविधाएं देना तथा यात्रा को बेहद सुरक्षित बनाए रखना भी जरूरी है। विदेशों में अनेक स्थानों पर रेल पटरियां दोनों ओर दीवालों से घिरी रहती हैं, जबकि भारत में इसका ठीक उल्टा है। ऐसे में यथासंभव रेल पटरियों के दोनों ओर दीवाल उठाने की दूरगामी योजना पर ध्यान देना चाहिए। राजमार्गों को सुरक्षित करने के लिए ऐसी पहल नितिन गडकरी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। रेलवे को उनका अनुसरण करना चाहिए।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

फाइव आईज़ गठजोड़

फाइव आइज़ गठजोड़ के प्रति भारत को सतर्कता बरतनी जरूरी है क्योंकि यह कनाडा का समर्थन करता है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए सिखों का समर्थन पाने हेतु भारत के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना, झूठे, मनगढ़ंत और हास्यापद आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। बिना प्रमाण के लगाए इन आरोपों का भारत ने कठोर जवाब दिया तो कनाडा सरकार तिलमिला गई है। सिखों का समर्थन पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान-समर्थकों को शह देकर बेलगाम बना रहे हैं। इस काम में अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, अर्थात इन पांच देशों का फाइव आइज नामक कथित संगठन ट्रूडो की सहायता कर रहा है। इससे वे खालिस्तानियों को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनके दल के ही लोग इस नीति का खुला विरोध कर सरकार गिराने की चुनौती दे रहे हैं। भारत को राजनयिक स्तर पर अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन से भी बात करनी चाहिए।

-बी.एल. शर्मा, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
आत्मविश्वास में पर्वतों को भी हिलाने की क्षमता होती है

असम समझौते पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6ए को वैधानिक करार देकर 1985 में राजीव गांधी सरकार और अखिल असम छात्र संघ के बीच हुए समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस समझौते के तहत नागरिकता कानून में धारा 6ए जोड़कर यह व्यवस्था की गई थी कि 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले यह तिथि 1 जनवरी 1966 थी। नागरिकता कानून की इस धारा की संवैधानिकता को दी गई चुनौती खारिज होने के बाद बांग्लादेश से असम आए वे लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो 25 मार्च 1971 के पहले आए थे, लेकिन उनकी पहचान करके वापस भेजा जाएगा, जो इसके बाद आए। यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है और उनकी पहचान करना भले आसान हो, लेकिन उन्हें वापस भेजना मुश्किल है। ऐसे लोगों को तभी वापस भेजा जा सकता है, जब बांग्लादेश उन्हें लेने को तैयार हो। यह स्पष्ट तो है कि इनमें से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध आदि तो वापस जाने के लिए तैयार होने वाले नहीं। उनके वहां लौटने का मतलब है उनकी जान पर बन आना। अब तो इसकी आशंका और भी बढ़ गई है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां इस्लामी कट्टरता काफी अधिक बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। सौभाग्य से इन्हें नागरिकता कानून में किए गए उस संशोधन का सहारा मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।

असम में कुछ लोग 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में इसलिए नहीं, क्योंकि इससे राज्य का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इस खतरे को निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असम एक छोटा राज्य है और वहां पाकिस्तान बनने के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से लोग अवैध तरीके से आने लगे थे। कुछ शरणार्थी के रूप में आए और कुछ घुसपैठिए के रूप में। बांग्लादेश से एक बड़ी संख्या में लोग असम के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ बंगाल में भी आ बसे हैं। इनमें से अनेक ने अवैध तरीके से भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिए हैं और मतदाता बन गए हैं। इनमें से जो घुसपैठिए के रूप में हैं, उन्हें वापस भेजा ही जाना चाहिए, क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति को बदलने का काम कर रहे हैं और सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के साथ देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं। यह कहना कठिन है कि बांग्लादेशियों के साथ-साथ म्यांमार के रोहिंग्याओं और कुकी लोगों का भारत आना पूरी तरह थम गया है। यह थमना ही चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी सख्ती दिखानी होगी।

वित्तीय अनुशासन जरूरी

विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर सरकारी राशि की लूट अब नई बात नहीं रही। नया मामला झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम और पर्यटन विभाग से जुड़ा है। यहां सरकारी कर्मचारियों ने पहले फर्जी खाते खुलवाए और फिर करोड़ों रुपये डकार गए। इन घोटाले के पीछे का एक कारण यह भी है कि सरकारी विभागों में आज भी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया है। इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम लोगों से टैक्स मद में जमा रुपये घोटालेबाजों की जेब में जा रहे हैं। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम और पर्यटन विभाग के 107 करोड़ से अधिक की राशि खाते में ट्रांसफर किए जाने के मामले में सरकारीकर्मियों और बैंककर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। बहरहाल, सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पिछले दिनों इस मामले को सीआइडी को स्थानांतरित कर दिया है। जांच में अभी तक लगभग 300 फर्जी खातों की जानकारी मिली है, जिनमें सबसे अधिक अकाउंट निजी बैंकों में खोले जाने की बात सामने आई है। अब तक के अनुसंधान में लगभग 39.70 करोड़ रुपये विभिन्न खातों में प्रेषित कराए गए हैं। ऐसी गड़बड़ी सिर्फ एक विभाग में नहीं हुई है। फर्जीवाड़े में शामिल ऐसे विभागों की लंबी सूची है, जहां करोड़ों के वारे-न्यारे हुए हैं। सरकार को ऐसे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आवश्यक यह भी कि शासन-प्रशासन विभागों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मानकों पर स्थापित तकनीकों का भी सहारा ले। अन्यथा घोटाले होते रहेंगे। विकास के लिए उमा राशि बिचौलियों और घोटालेबाजों की जेब में जाते रहेंगे।

> विभागों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मानकों पर स्थापित तकनीकों का भी सहारा लेना आवश्यक है

संपदा के सर्जकों को मिले सम्मान

विकास सारस्वत

देश को रतन टाटा जैसे अनेक भविष्यद्रष्टा उद्यमी चाहिए, क्योंकि सुनहरा भविष्य खोखले समाजवाद और कोरे नारों से नहीं, बल्कि व्यापार और उद्यम से बनेगा

प्रवेश तलाछा

उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर समूचे राष्ट्र ने शोक मनाया। उद्योग जगत एवं शीर्ष नेताओं के अलावा जिस तरह गैरेगांव के गरबा पंडाल से लेकर काशी की गंगा आरती तक आमजन ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, वह टाटा घराने और स्वयं रतन टाटा के प्रति देशवासियों स्नेह और कृतज्ञता के भाव को प्रकट करता है। टाटा समूह ने उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े-बड़े कीर्तिमान एवं आयाम स्थापित किए और यह उद्योग क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांडों में से एक बनकर उभरा। इस सुनहरे एवं समृद्ध विरासत को रतन टाटा ने बखूबी आगे बढ़ाया। बतौर चेयरमैन अपने 21 वर्ष के कार्यकाल में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 46 गुना बढ़कर 4.75 लाख करोड़ और मुनाफा 50 गुना बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा। रतन टाटा ने करीब 50 देशों और विदेशी स्टार्टअप्स में निवेश किया। इनमें पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक, लेंसकार्ट और ब्लू स्टोन जैसे स्टार्टअप्स आज बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने में रतन टाटा का बड़ा योगदान रहा है।

रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह का उत्तराधिकार उस समय ग्रहण किया, जब देश उदारीकरण की नीति पर चल निकला था। यह दशकों तक घरेलू संरक्षण में पले-बढ़े भारतीय उद्योग और व्यापारों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, जहां उन्हें एकाएक बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी थी। संरक्षण के चलते टाटा समूह की कंपनियों की पेशेवर क्षमताएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान शिथिल और निष्क्रिय हो चली थीं। इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने टाटा ग्रुप के मूल मंत्रों से इतर अपने मनमाने कार्यपद्धति से न सिर्फ कंपनियों की कार्यकुशलता को कमजोर किया, बल्कि टाटा समूह को भी विघटन के कगार पर ला खड़ा किया। रतन टाटा ने एक समूह कार्यकारी कार्यालय की स्थापना कर इसके सदस्यों को टाटा कंपनियों के बोर्ड में स्थान दिया। साथ ही सभी कंपनियों में टाटा सेस की 26 प्रतिशत भागीदारी तय कर उनका अधिग्रहण यानी होस्टाइल टेकओवर से बचाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस दौरान इंडियन होटल्स, टिस्को और टेल्को (वर्तमान में टाटा मोटर्स) से बड़ी संख्या में छंटनी की गई, प्लांट एवं मशीनरी का नवीनीकरण हुआ और बहुत सी युवा प्रतिभाओं की भर्ती हुई। जहां रतन टाटा नए सुझाव, नई तकनीक और नई प्रबंध नीतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे वहीं कई मामलों में उनके निर्णय भावनात्मक, निज विवेक और दृढ़ निश्चय पर आधारित होते थे।

हेलेन टेरेस्की और एलिजाबेथ क्रिस्टीफ ने अपनी पुस्तक में रतन टाटा के शेयक संस्मरणों का उल्लेख किया है। संपूर्ण आटोमोटिव सेक्टर से मिलकर एक पूर्णतः भारतीय कार बनाने के आग्रह पर एक उद्योग कार्यकारी से रतन टाटा को जवाब मिला, 'भारतीय कार की बात करने से पहले मिस्टर टाटा कैसी भी खामखाह कार बनकर क्यों नहीं दिखते।' इसके तुरंत बाद पूरी तरह भारत में निर्मित टाटा इंडिका पर काम शुरू हुआ, जो शुरूआत में सामने आई खामियों के बावजूद न सिर्फ भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी, बल्कि आटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता तय करने वाला मील का पत्थर भी बनी। इंडिका का प्रक्षेपण टाटा समूह की उस चार सूत्रीय व्यवसायिक नीति पर आधारित था, जिसमें किसी भी परियोजना को बड़े बजट पर छोटी शुरूआत के साथ उतारा जाए, ताकि संभावित खामियों में सुधार के लिए पर्याप्त पूंजी बची रहे और उत्पाद को उत्तरोत्तर सुधारा जा सके। इसी तरह अमेरिकी सलाहकार फर्म मैकेंजी द्वारा टिस्को का पूरी तरह बिनिवेश करने यानी हिस्सेदारी बेचने की सलाह को भी टाटा ने नहीं माना, बल्कि उसे और संगठित किया। टिस्को ही टाटा स्टील का पूर्ववर्ती संस्करण थी। बिनिवेश जैसी सलाहों को दरकिनार करते हुए टाटा स्टील ने इस्पात क्षेत्र की भौमकाय आंग्ल-डच कंपनी कोरस को खरीद कर इस्पात उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया।

पारंपरिक रूप से परोपकार और टाटा समूह एक दूसरे के पर्याय रहे। टाटा समूह की इस परंपरा को रतन टाटा ने और आगे बढ़ाया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से लेकर आवारा पशुओं को सहारा देने में टाटा ने करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। कोविड काल में टाटा ट्रस्ट ने 1,500 करोड़ का दान दिया। भारत के सबसे बड़े धनाढ्यों में से एक होने के बावजूद रतन टाटा का निजी जीवन बहुत सरल और सहज था। वह टाटा समूह के आफिस में आमी कर्मियों के साथ कतार में लगकर प्रवेश करते दिख जाते थे और कभी-कभार अपनी गाड़ी भी स्वयं चला लेते थे। कभी-कभार वह मुंबई में चलने वाली सामान्य काली पीली टैक्सी में भी सफर हो जाते थे। वह संपदा सृजन को भी सेवा का उपकरण मानते थे।

एक उद्यमी के रूप में रतन टाटा की विरासत इस प्रकार स्मरण रखे जाएगी कि उन्होंने न सिर्फ बदलाव के समय में अपने समूह को सेक्रमणकाल से सफलतापूर्वक बाहर निकाला, बल्कि उसे वैश्विक विस्तार भी दिया। जिस फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड ने 1998 में इंडिका का सौदा करने गए टाटा को अपमानित कर वापस भेजा था, उन्होंने 2008 में मुश्किल के दौर से गुजर रहे अपने दो बड़े ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह द्वारा खरीदने पर कठिन समय में उन पर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया। रतन टाटा ने दशकों तक पेशेवर समाजवादी कटुता के बावजूद राजनेताओं और राजनीति से अभिभूत भारतीय समाज में पूंजी, उद्यम और धन सृजन को भारतीय मानस में सम्मान दिलाने का काम किया है। यदि हमें एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है तो यह आवश्यक है कि टाटा जैसे और बहुत से भविष्यद्रष्टा उद्यमी भारत को मिलें। यह आवश्यक है कि समाज में धन सृजन करने वाले ऐसे उद्यमियों को यथोचित सम्मान भी मिले, क्योंकि भारत का सुनहरा भविष्य खोखले समाजवाद और राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि व्यापार और उद्यम से तय होगा। यह ठीक नहीं कि कुछ नेता संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कारोबारियों को खलनायक ठहराने पर तुले हैं।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कानूनों से नहीं रुकेगा पराली का जलना

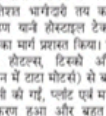

पंकज चतुर्वेदी

यह बात किसानों तक पहुंचाना जरूरी है कि खेतों में जलने वाला फसल अवशेष उन्हेंही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पराली यानी फसलों के अवशेष जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सख्त कार्रवाई में कोताही बरतने पर हरियाणा और पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई। पराली का मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंचा, क्योंकि दिल्ली और इसके आसपास वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। इसके लिए वाहनों, फैक्ट्रियों एवं पराली का धुआं, धूल इत्यादि कारण अधिक जिम्मेदार हैं। आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जैसे-जैसे पराली जलाने की घटनाएं बढ़ेंगी वैसे-वैसे प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। सरकारें पराली जलने से रोकने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं। बीते एक दशक से राज्य सरकारें कभी कानून तो कभी जन-प्रचार के माध्यमों से किसानों को बताती रही हैं कि खेतों में अवशेष अर्थात पराली जलाने के कितने नुकसान हैं, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। इस बार भी खेतों से लपटें और हवा में धूएं के बादल उठते दिख रहे हैं। अब तो कुछ उन राज्यों में भी पराली जलने लगी है, जहां पहले नहीं जलती थी।

किसान वैसे तो समाज को जीवन देने के लिए अन्न उगाता है, लेकिन अनजाने में ही फसलों के अवशेष जलाने से सांस लेने से जुड़ी गंभीर तकलीफों और कैंसर तक का वाहक बन रहा है। इससे उनका अपना परिवार भी नहीं बचता। इसे देखते हुए अब पराली की समस्या का निदान कानून या तकनीक की जगह सामाजिक तरीके से करना बेहतर होगा। यह बात किसानों तक पहुंचानी जरूरी है कि खेतों में लगी आग से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। पराली का सलीके से निपटान कर किसान अपने खेतों की उर्वरता बढ़ा सकते हैं और अपनी तकदीर बदल सकते हैं। देश में हर साल करीब 31 करोड़ टन फसल अवशेष जलाए जाते हैं, जिससे हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा 33 से 290 गुणा तक बढ़ जाती है। हर साल अकेले पंजाब और हरियाणा में करीब तीन करोड़ 50 लाख टन पराली जलाई जाती है।

एक टन पराली जलाने पर दो किलो सल्फर डाईआक्साइड, तीन किलो ठोस कण, 60 किलो कार्बन मोनोआक्साइड, 1,460 किलो कार्बन डाईआक्साइड और 199 किलो राख निकलती हैं। ऐसे में जब करोड़ों टन अवशेष जलते हैं तो वायुमंडल की कितनी दुर्गति होती होगी। इन दिनों संभावित एवं बड़े किसान खरीफ फसलों खासतौर पर धान काटने के लिए हार्वेस्टर जैसी मशीनों का सहारा ले रहे हैं। इससे कटाई से फसल के तने का अधिकांश हिस्सा खेतों में ही रह जाता है। जहां गेहूं, गन्ने की हरी पत्तियां, आलू, मूली की पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती हैं तो कपास, सनई और अरहर आदि के तने, गन्ने की सूखी पत्तियां, धान की पुआल आदि को जला दिया जाता है। फसलों के बचे अंश का इस्तेमाल मिट्टी जीवंतता पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

आज पूरी खेती ऐसे रसायनों द्वारा हो रही है, जो कृषि-मित्र सूक्ष्म जीवाणुओं को ही चट कर जाते हैं। ऐसे में खेत की जैव-विविधता का संरक्षण बेहद जरूरी है। फसलों के अवशेष इसमें किसानों की मदद कर सकते हैं। किसान चाहें तो फसलों के अवशेषों से कंपोस्ट या जैविक खाद तैयार कर अपने रासायनिक खाद के खर्चे से बच सकते हैं। पुआल को खेत में ढेर बनाकर खुला छोड़ने के बजाय गड्ढों में कंपोस्ट खाद बनकर उपयोग कर सकते हैं। आलू और मूंगफली जैसी फसलों को खोदाई कर बचे अवशेषों को धूप में जोत कर मिला सकते हैं। मूंग एवं उड़द की फसल में पलियां तोड़कर खेत में मिला सकते हैं। केले की फसल के बचे अवशेषों से तैयार कंपोस्ट खाद में 1.87 प्रतिशत नाइट्रोजन, 3.43 प्रतिशत फास्फोरस तथा 0.45 प्रतिशत पोटाश होता है। वैसे आधुनिक मशीन रोटावेटर भी फसल अवशेषों को उपयोगी बनाने में बेहद कारगर है। इस मशीन से जुताई करने पर फसल अवशेष मशीन से बारीक होकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जिन इलाकों में जमीन की नमी कम हो रही है और भूजल और गहराई में जा रहा है, वहां रासायनिक खाद के बजाय कंपोस्ट ज्यादा कारगर है और पराली जैसे अवशेष बगैर किसी व्यय के आसानी से कंपोस्ट खाद में बदले जा सकते हैं। यदि मिट्टी में नमी कम हो जाए तो जमीन के बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। फसल अवशेष को जलाने से खेत की छह इंच परत आग में भस्म हो जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लाभदायक सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, नील हरित काई, मित्र कीट के अंडे आदि होते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी जर्जर हो जाती है।

किसानों का कहना है कि पराली को मशीन से निपटाने पर प्रति एकड़ कम से कम पांच हजार रुपये का खर्च आता है। फिर अगली फसल के लिए इतना समय होता नहीं कि गीली पराली को खेत में पड़े रहने दें। पंजाब में किसानों का एक बड़ा वर्ग सरकार की सब्सिडी योजना से भी नाखुश है। उसका कहना है कि पराली को नष्ट करने की मशीन बाजार में 75 हजार से एक लाख रुपये में उपलब्ध है। यदि सरकार से सब्सिडी ले तो वह मशीन डेढ़ से दो लाख रुपये की पड़ती है। जाहिर है सब्सिडी उनके लिए बेमानी है। उसके बाद भी मजदूरों की जरूरत होती ही है। किसानों को पराली के हर पक्ष को समझने के अलावा समुदायिक स्तर पर मजदूरों की मदद से सरकार खुद इस काम को कुछ साल करे तो शायद उनके मन में व्याप्त शंका का निवारण हो जाए और वे आगे से खुद पराली नहीं जलाएं।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

अमृतसर में खेतों में जलाई जाती पराली। प्रेट्र

ऊर्जा

परिवेश की महत्ता

वह सब कुछ जो हमारे शरीर एवं मन को घेरे हुए है, परिवेश के अंतर्गत आता है। इसका प्रभाव हमारे क्रियाकलापों, हमारी पहचान, हमारे कर्म एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि हमारे चारों ओर आध्यात्मिक परिवेश है तो हमारा स्वभाव एवं प्रकृति अध्यात्म की ओर झुकने लगेगी। यदि हम चारों ओर से दैहिक परिवेश द्वारा घिरे हुए हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर का परिवेश बुराइयों से घिरा हुआ है तो वे बुराइयां उस परिवेश के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाएंगी। कुल मिलाकर परिवेश में मौजूद तत्व एवं विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती हैं एवं हमारा व्यक्तित्व उसी अनुरूप ढल जाता है।

यदि हम जीवन में सफलता एवं प्रगति का अर्जन करना चाहते हैं तो हमें ऐसे परिवेश में रहने का प्रयास करना चाहिए, जो सकारात्मकता से परिपूर्ण हो। नकारात्मक भावनाओं, विचारों एवं प्रकृतियों से परिपूर्ण परिवेश हमें सदैव अवनति की ओर ही ले जाएगा। यहां पर एक अन्य बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि परिवेश का निर्माण करने वाले भी स्वयं हम ही होते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वैसा ही परिवेश हम अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए निर्मित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिवेश के निर्माण में सहायक होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए परिवेश का निर्माण करता है। बच्चे पर परिवेश का प्रभाव तुरंत ही पड़ना आरंभ हो जाता है और यह प्रभाव ही उसके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एक-दूसरे को एक अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण परिवेश प्रदान करने में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि नकारात्मकता हम सभी से कोसों दूर रहे एवं हम सभी अपने-अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ने में सफल हो सकें।

प्रेरणा अवस्थी

स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण की जरूरत

सोनम लववंशी

यदि समय रहते बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित नहीं किया गया, तो उनका मानसिक और सामाजिक विकास बाधित होगा

वर्तमान युग डिजिटल क्रांति का युग है। डिजिटल उपकरणों के बढ़ते चलन ने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक तो बनाया ही, साथ ही इसके अंधाधुंध उपयोग ने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है। आज सबसे बड़ी चिंता 'वर्चुअल आटिज्म' है, जो छोटे बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ है। इससे उनका सामाजिक और मानसिक विकास बाधित हो रहा है। स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर आदि डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण करीब एक से तीन साल के बच्चों में आंखों का संपर्क न बनना, दूसरों के साथ संवाद करने में असमर्थता और व्यवहारिक असंगतियां जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। बच्चों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वे डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बचें और वास्तविक दुनिया के अनुभवों में शामिल हों।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन एक घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन औसतन बच्चों का स्क्रीन टाइम दो-तीन घंटे है। भारत में शहरी क्षेत्रों के बच्चे पांच घंटे प्रतिदिन स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जो कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम तीन घंटे प्रतिदिन पाया गया है। अमेरिकन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दो साल से कम उम्र के बच्चे औसतन 1.5 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जबकि इस आयु वर्ग के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी अनुशंसित नहीं है। आंकड़ों के अनुसार करीब 90 प्रतिशत अमेरिकी बच्चे दो साल की उम्र तक किसी न किसी डिजिटल स्क्रीन का उपयोग शुरू कर देते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में सुझाव गया है कि सरकार और संस्थानों को स्क्रीन टाइम से संबंधित नीतियां बनाने की आवश्यकता है। इसमें बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियमित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की अनुशंसा की गई। माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम को मानिटर करने और उन्हें शारीरिक गतिविधियों, रचनात्मक खेलों और समाज के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी गई है।

यदि समय रहते बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित नहीं किया गया, तो उनका मानसिक और सामाजिक विकास बाधित होगा। अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें। बच्चों को शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। सामाजिक जागरूकता से ही वर्चुअल आटिज्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अधिकार बनाम दुरुपयोग

'वैवाहिक दुष्कर्म कानून के खतरे' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में दीपिका नारायण भारद्वाज ने वैवाहिक दुष्कर्म कानून के संभावित दुरुपयोग और इसके संतुलित एवं निष्पक्ष क्रियान्वयन की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला है, जो वर्तमान सामाजिक स्थिति को उपयुक्त मांग भी है। वैवाहिक दुष्कर्म कानून को लेकर बहस आज एक नाजुक मोड़ पर है। यह विषय जितना संवेदनशील है, उतना ही जटिल भी। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से इस कानून की आवश्यकता निःसंदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके संभावित दुरुपयोग की आशंका की नजरअंदाज करना भी गलत होगा। सवाल यह है कि क्या यह कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा का माध्यम बनेगा या झूठे आरोपों के जरिये निर्दोष पुरुषों के लिए खतरा? विवाह, जिसे समाज में एक पवित्र और परस्पर विश्वास का बंधन माना जाता है, उसके भीतर दुष्कर्म की परिभाषा और इससे जुड़ी धाराओं को समझने की जरूरत है। वैवाहिक दुष्कर्म कानून के लागू होने से जहां महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद है, वहीं इसका यह पहलू भी देखने योग्य है कि ऐसे आरोपों की जांच और सत्यापन किस तरह किया जाएगा। एकतरफा कानून बनाने से समस्या और उलझ सकती है, जिससे पुरुषों पर झूठे आरोप लगाने के मामले बढ़ सकते हैं। कानून न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि पुरुषों के अधिकारों की भी रक्षा हो। किसी भी वैवाहिक रिश्ते में संवाद की कमी अक्सर ऐसी समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए कानून बनाने के साथ-साथ वैवाहिक संबंधों में संवाद और सहमति की अहमियत को भी बढ़ावा देना चाहिए। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जो हर मामले की सावधानीपूर्वक जांच करे। न्याय का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब कानून दोनों पक्षों को समान रूप से सुने और दोषियों को सजा दे, मगर निर्दोषों को बचाए भी।

awanish30@gmail.com

बिहार में जहरीली शराब का कहर

बिहार में जहरीली शराब का कहर फिर से देखने को मिला है। शराब पीने से बिहार के 16 से अधिक गांवों में 15 अक्टूबर से अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिले सिवान और सारण हैं। 40 से अधिक व्यक्ति शराब पीने के कारण गंभीर अवस्था में हैं। बिहार के अंदर हर कुछ महीने छोड़कर शराब का प्रकोप दिखाई देता है। यहां शराब बनने और वितरण के ऊपर प्रशासन एवं सरकार की रोक असफल साबित हो रही है। बिहार में बार-बार शराब से होने वाली जनहानि को तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक प्रशासन की गतिशीलता दिखाई न दे। प्रशासन की मिलीभगत के कारण भी शराब का कारोबार बिहार में तेजी से फैलता जा रहा है। यह सभी के संज्ञान में है कि बिहार में जहरीली शराब बन भी रही है और उसका वितरण भी हो रहा है। इसको रोकने में विफलता प्रशासन की असफलता ही मानी जाएगी।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

जीवनसाथी की सहमति आवश्यक

वैवाहिक दुष्कर्म जीवनसाथी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने का कार्य है। सहमति की कमी एक अनिवार्य तत्व है। वैवाहिक दुष्कर्म को घरेलू हिंसा और यौन शोषण का एक रूप माना जाता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से, विवाह के भीतर यौन संबंध बनाना पति-पत्नी का अधिकार माना जाता था, लेकिन अब दुनिया भर के कई समाजों में पति-पत्नी की सहमति के बिना इस कृत्य को दुष्कर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसे अपराध माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध श्रेणी में रखा गया तो इससे समाज को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे झूठे आरोपों को बढ़ावा मिलेगा और संभावित रूप से परिवार नष्ट हो जाएंगे। हालांकि, वे यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि इस कानूनी अपवाद की वजह से कितनी ही महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हिंसाओं के खतरे की दर तेजी से बढ़ रही है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संपादक-एस. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-एस.एन.गोयल, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रबंध संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेश ओसवाल द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63, नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43566300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समाचार विश्लेषण/विचार के अधीन रहते हैं। कार्य हेतु मूल्य ₹-2 अतिरिक्त।

एरिया : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। लेख/लेख शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

11 मीटर है मध्यम रक्षित एम्क्यू-9 बी प्रीडेटर ड्रोन की लंबाई, जो 4,763 किलोग्राम अधिकतम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में एक बार में 1,700 किलोग्राम ईंधन भर जा सकता है।

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

नोबेल पुरस्कार

एआइ को सशक्त बनाने के संकेत

इस साल भौतिकी और रसायन, दोनों क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों का जुड़ाव उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) से है, जिसे मानव भविष्य के लिए घातक बताया जा रहा है और जिसके क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ने एवं इसके ग्लोबल हब बनने के प्रयास में हैं। इन सबके इतर एआइ के अनुप्रयोगों के मानव हित में कई सकारात्मक पहलू भी हैं, जिसे इन नोबेल खोजों ने साबित किया है। इसे एआइ को सशक्त बनाए जाने के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है

जिन दो विज्ञानियों को भौतिक विज्ञान का नोबेल प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है, उनमें से एक विज्ञानी जान जे. हापफील्ड को 'आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क' विकसित करने के लिए तो दूसरे केन्यूटर विज्ञानी जैफ्री हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों के लिए सम्मानित किया जाएगा। हापफील्ड और हिंटन, दोनों के कार्य क्षेत्र का जुड़ाव सांख्यिकीय भौतिकी, न्यूरोबायोलाजी और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सहित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से है। पर अंततः उनका मुख्य सिरा एआइ से ही जुड़ता है।

दूसरी तरफ रसायन विज्ञान के लिए जिन दो विज्ञानियों को पुरस्कार मिला है, उनकी खोजें प्रोटीन से संबंधित हैं। प्रोटीन के बिना जीवन असंभव है। डेविड बेकर को 'कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए' नोबेल मिला है। डेविड बेकर के कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन से पहले ही ध्वनित होता है कि यह कंप्यूटर और गणना या फिर गणित से संबंधित है। निस्संदेह इसमें एआइ की महती भूमिका है। इसके अलावा, डेमिस हसबिस और जान जंपर को 'अल्फाफोल्ड 2 माडल को विकसित करने के लिए नोबेल दिया गया है, जिसकी सहायता से लाखों प्रोटीन संरचनाओं को जाना जा सकता है। इस माडल के आने से पहले हम महज 1.70 लाख प्रोटीन संरचनाओं को ही जानते थे। यह भी एआइ आधारित एक माडल है, तो रसायन क्षेत्र में भी दोनों नोबेल पुरस्कार मूलतः भौतिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते एआइ से ही संबंधित हैं।

नोबेल कमेटी ने कहा है कि इन विज्ञानियों ने नूतनता की नए तरीके से कंप्यूटर का उपयोग सिखाया, पर ताजा नोबेल पुरस्कार बताते हैं कि समूचा संसार बड़ी तेजी से एआइ की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल यह बाजार का औजार है और हम इसके शिकार हैं। जिस तरह इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, वह दिन दूर नहीं कि आज जो घर-घर में एक जान-पहचान शब्द बन चुका है, वह एआइ आगे सर्वव्यापी होगा और विश्व के हर मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप में किसी न किसी अंश में शामिल होगा। फिलहाल फौरी तौर पर हम इसे देखने से इसे समर्थित डीप फेक के नए दौर में नकली ही नया असली होगा, सच झूठ का भेद मिट जाएगा। दूसरामी आशंका है कि मनुष्यों की जगह मशीनें ले लेंगी, मानव अनुपयुक्त, नकारा और मशीनों का गुलाम होगा।

नकारात्मक असर की आशंका : नोबेल पुरस्कारों की घोषणाओं की गहमागहमी के बीच एआइ की आगत आशंकाओं को परे रखकर हम यह नहीं भूल सकते कि उन्नत एआइ की आधारशिला रखने वाले, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हापफील्ड ने पिछले साल गूगल की नौकरी इस विरोध के साथ छोड़ी थी कि वह एआइ के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। जैफ्री ने अपने को एआइ की खोज का अपराधी मानते हुए दुख जताया और एक साक्षात्कार में कहा, 'यह बड़े पैमाने पर बेरोजगारी लाएगा। समाज में ऐसी अफवाहें तेजी से फैलेंगी जिन्हें जल्दी रोकना असंभव होगा।'

हालांकि आगत की आशंकाओं की अहद से इतना हलकान न होते हुए सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही श्रेयस्कर होगा। एआइ के नुकसान हैं, तो लाभ भी कम नहीं और भविष्य में इस बुराई से लड़ने के लिए भी इसकी ही अच्छाई काम आने वाली है। फिलहाल जिन खोजों पर नोबेल की घोषणा की गई है, उनमें कोई चार तो कोई 21 वर्ष पुराना है, तो कोई 44 साल। सौ अब तक इनके अनुप्रयोगों से यह तय हो चुका है कि मानवता के लिए ये बड़े काम के हैं। उन पर आधारित तकनीक को पर्याप्त कार्यक्षम माना जा चुका है और उनसे उल्लेखनीय संभावनाओं को जन्मते देखा जा रहा है। हापफील्ड के कृत्रिम तंत्रिका तंत्र ने ऐसा मशीनी स्मृति तंत्र विकसित किया जो मानव मस्तिष्क की तरह आंकड़ों, सूचनाओं को ग्रहण, संग्रहीत व याद रखकर उसके पुनर्निर्माण व आवश्यकता पड़ने पर फिर से याद दिलाने में सफल हुआ तो हिंटन ने बोल्ट्जमैन मशीन विकसित करके हापफील्ड के काम को गति दी, उनका आविष्कार न्यूरल नेटवर्क को उद्घटनों का विश्लेषण करके सीखने में इस कदर सक्षम बना देता है, जिससे यह पैटर्न को पहचान आंकड़े को खोजने में सक्षम होने के साथ चित्रों में अंतर कर सके।

अल्फाफोल्ड 2 माडल शोर में भूमिकाएं निभाने वाले, शरीर के उतकों एवं अंगों की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक लाखों प्रोटीनों की संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है, जिससे हम जान पाते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार कार्य करता है। यह समझ जाने के बाद इस बारे में नई परिकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं कि किसी प्रोटीन के कामकाज को कैसे प्रभावित, निर्बलित या बदल दिया जाए। इसे रैबोटिक्स से जोड़कर इंटरेक्टिव होम हिब्राइस बनने, ब्रायोमेट्रिक्स के क्षेत्र में सटीक सर्वेक्षण करवाने, तकनीकी क्षेत्र में मानवीय दखल और गलतियां न्यून करने के लिए, बेहतर मानव-कंप्यूटर इंटरेक्शन आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काम चल रहा है।

समाचार पत्रों की सुर्खियों से परे, वैज्ञानिक शोधों के लिए दशकों से चली आ रही कम फंडिंग, अकुशल प्रशासन, संसाधनों की कमी और नौकरशाही की गैरजरूरी प्रक्रियाओं के साथ प्रयोगशालाओं को नव्यतम जरूरतों की किल्लत वाली असुविधाओं से समंजस्य बिठाते हुए किए जाने वाले अपर्याप्त प्रयासों के चलते एआइ के क्षेत्र में हम उस स्तर से आगे नहीं निकल पाए हैं, जितनी हमारी क्षमता है। संभव है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मिलने वाले ये नोबेल हमारे अनुसंधान, अभियान को कुछ गति प्रदान करें। (ईआरसी)

प्रीडेटर ड्रोन से मजबूत होगी भारतीय सेना

व. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विषय

भारत ने अमेरिका के साथ ड्रोन खरीद के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में देश के रक्षा और रणनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच समरिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। इसके तहत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी 'जनरल एटामिक्स' से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस खरीद की लागत लगभग चार अरब डालर होगी। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य चीन सेमा पर भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति ने एमक्यू-9बी हंटर किलर ड्रोन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी।

प्रीडेटर ड्रोन को खरीद से भारत के शत्रु देश हमें आंख दिखाने से डरेंगे। इन ड्रोन की शक्ति से भारत दुश्मनों के नापाक इरादों को तहस-नहस करने में आसानी से सफल होगा, क्योंकि यह समुद्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और जमीनी सीमा के उस पार लक्ष्य साधने सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत विशेष रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है। ये ड्रोन हवा से जमीन पर सटीक मार करने में अत्यंत सक्षम हैं। समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे तथा भारतीय वायु सेना व थल सेना को आठ-आठ स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले ये ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं। ये चार हेलफायर मिसाइलें व 450 किलोग्राम बम ले जाने की क्षमता रखते हैं।

मानवरहित एमक्यू-9 बी प्रीडेटर ड्रोन की लंबाई लगभग 26 फुट है। एमक्यू-9 बी ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलें से लैस है। यह चार मिसाइलों को एक साथ दागने में सक्षम है। इसकी खासियत यह भी है कि यह एक बार उड़ान भरने के बाद आसमी के साथ 1900 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है। चीन ने हिंद महासागर के अलावा कई समुद्री इलाकों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है। चीन अपने जासूसी जहाजों के साथ-साथ उपग्रहों, रकेटों व बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनात करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत को इन ड्रोन की विशेष आवश्यकता थी। अब भारत की ताकत पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगी और समय रहते बड़े अभियान को अंजाम दिया जा सकेगा।

वर्तमान में भारत एक खुफिया एकत्रीकरण अभियान के हिस्से के रूप में एमक्यू-9 बी ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि इसे मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज तथा बचाव एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी उपयोग में लाया जा सकता है। एमक्यू-9 बी सी गार्डियन ड्रोन में एक इन-बिल्ट वाइड-एरिया समुद्री राडार, एक स्वचालित पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रानिक समर्थन उपाय और एक स्व-निहित एंटी सबमरीन वारफेयर किट लगी है। शत्रु क्षेत्र के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने वाला यह ड्रोन इंटर-किलर सूएबे के नाम से प्रसिद्ध है। पानी की सतह के ऊपर और भीतर दोनों ही प्रकार की जगहों की निगरानी व छानबीन के लिए इसमें 80 से ज्यादा जी-सइज के सेनेबाय लगाए गए हैं। वस्तुतः सोनेबाय वह डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के माध्यम से पानी के भीतर हो रही आवाजों को पहचान करता है। इनकी मदद से प्रीडेटर ड्रोन गहरे पानी में छिपी हुई शत्रु की पनडुब्बियों को आसानी से खोज लेता है और उसके बाद मिसाइलों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देता है। इन खूबियों वाले ड्रोन से भारतीय सेनाएं काफी ताकतवर हो जाएंगी।

खरी-खरी

हम विकास करेंगे!

सुन सत्ता

चुनाव का मौसम था। नेताओं की आवाजाही बढ़ गई थी। जिस किसी चुनाव प्रत्याशी से पूछो कि चुनाव जीत गए तो क्या करोगे भाई? सभी का एक ही उत्तर होता विकास करेंगे। मैं पूछता, विकास क्या होता है? तो वे दाएं-बाएं झांकने लगते। मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, यदि आप विकास का मतलब नहीं जानते, लेकिन यह तो जानते होंगे कि विकास करेंगे कैसे? इस पर वे मुझे अज्ञानी समझ कर हंसते और कहते कि यह भी कोई पूछने की बात है, आजादी के बाद से जैसे विकास हो रहा है, वैसे ही करेंगे।

मैं कहता हूं कि आजादी के बाद वाले विकास में तो घोटाले होते रहे हैं, तो वे कहते हैं, उनकी जांच करवाएंगे। दोषियों को दंडित करेंगे, लेकिन हम विकास का काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और विकास हो भी क्यों नहीं, देश को इसकी आवश्यकता है, इसलिए अपने बेटे विकास को ही चुनाव में उतार दिया है। देखता हूं, विकास कैसे नहीं होता है?

मैंने नेताजी से कहा भी था कि यह तो वंशवाद है और वंशवाद को तो अब नकारा जा रहा है। नेताजी ने कहा कि यह वंशवाद नहीं है, यह विकास से है। विकास ऐसे ही होता है। विकास एक अबाध परंपरा है, जिसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। इसी कड़ी की लड़ी से विकास साकार होगा तथा आकार लेगा।

मैंने नेताजी से कहा कि मैं आपका आशय समझ नहीं सका। इस पर नेताजी बोले, 'तुम यह मसला समझो ही नहीं तो मेरे हित में है। मैंने आपको समझाया कि हम विकास करेंगे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे तो क्या करूं?'

मैंने कहा, 'हम विकास करेंगे- इसका मतलब सारे नेता मिलकर अपना घर भरेंगे, कहीं यह तो नहीं है।' मेरी इस बात पर वे खिल खिलाकर हंसे और बोले, 'बात तो समझते हो, लेकिन बात का मर्म तुम्हें बहुत देर से समझ में आता है। मेरा मतलब पांच वर्ष बाद समझे तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने साफ-साफ कहा है कि हम चुनाव के बाद विकास करेंगे और आप देख लेना।'

यह कहकर नेताजी चले गए और मैं खड़ा-खड़ा घंटों सोचता रहा। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि उनकी बात का मर्म समझने में वाकई में पांच साल की देरी हो गई।

X पोस्ट

बेंगलुरु टेस्ट में भारत का प्रदर्शन एडिलेड-आस्ट्रेलिया में 36 रनों पर आलआउट होने से भी बदतर है। एडिलेड में वह स्कोर एक तो विदेशी पिच पर बना व और दूसरे, टेस्ट भी गुलाबी गेंद से खेला गया था।
आदित्य साहा@Adityaksaha

भारतीय टीम में जितने बल्लेबाज इस समय खेल रहे हैं, उनमें से किसी की भी तुलना में केएल राहुल ने नई गेंद का उसी ज्यादा सामना किया है। अपने टेस्ट करियर की करीब 75 पारियों में उन्होंने ओपनिंग की है। उन्हें छठे नंबर पर उतारा गया।
हर्षा भोगले@bhogleharsha

बहराइच में रामगोपाल मिश्र की हत्या पर जिनके मुंह में बढ़ी जम गया था, उन्हीं को देखिए कि आज हत्या के आरोपितों के पैर में गोली लगने पर कैसे पापकार्न की तरह उछल रहे और छाती पीट रहे।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

ट्रूडो ने भारत-कनाडा रिश्ते बर्बाद कर दिए। उन्हें यह नहीं दिख रहा कि कनाडाई विश्वविद्यालों में आवेदनों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। कनाडा में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों में आधे भारतीय होते हैं। संभव है भारतीय छात्र अध्ययन के लिए कोई और देश चुनें।
अद्वैता काला@AdvaitaKala

जागरण जनमत

दल का दिखावा

क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से दोनों देशों के संबंध में सुधार की उम्मीद है?

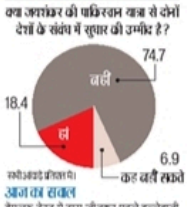

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
बेंगलुरु टेस्ट में टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का रोहित शर्मा का फैसला भारी पड़ा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पटरी खोली आंख से निहारा दिखे स्वरूप,
त्याग दिया अहंका किया मंथारी सा रूप।
मंथारी सा रूप नया देवी करो धारे,
सकुशल देवो और न्याय की बात विचारे।
अब्बाहे तोमून लोगे कह करे टिठौली,
चंद्रचूड़ जी धन्य आपने पटरी खोली!
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

पक्ष-विपक्ष दोनों लगा रहे जोर

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। पहली बार राज्य में दो चरणों में ही चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पिछला विधानसभा चुनाव पांच चरणों में संपन्न हुआ था। चुनाव की उलटी गिनती आरंभ होने के पहले से यहां सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन और भाजपा व उसके सहयोगी दलों में राजनीतिक रस्साकशी आरंभ हो गई थी। देखा जाए तो इस वर्ष के आरंभ से ही राज्य चुनावी मोड में चला गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि हालिया लोकसभा चुनाव के परिणाम से दोनों खेमा उत्साहित है। सत्तारूढ़ गठबंधन को इस मायने में परिणाम अपने पक्ष में लग रहा है कि उसने सभी आदिवासी सुरक्षित सीटों पर काबिज होने में सफलता पाई।

जबकि भाजपानीत राजग गठबंधन नौ सीटों पर कब्जा जमाकर संतुष्ट है। लोकसभा चुनाव को आधार बनाया जाए तो 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर राजग को बढ़त मिली है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव के अनुरूप विधानसभा चुनाव के परिणाम का आकलन करना जल्दबाजी होगी। इसकी वजह भी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सहयोगी आजसू पार्टी के साथ मिलकर 14 में से 12 सीटों पर कब्जा किया था। उक्त चुनाव में 65 से अधिक विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो स्थिति बदल गई। भारतीय जनता पार्टी केवल 25 सीटों पर सिमट गई और झामुमो ने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर आसनी से बहुमत हासिल कर लिया।

पिछले विधानसभा चुनाव से अलग इस बार भाजपा ने यहां आजसू पार्टी के साथ-साथ जनता दल यूनाइटेड और लोजपा (रामविलास) से भी तालमेल की घोषणा की है। यह रणनीति वोट प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में कारगर हो सकती है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी भी पिछले विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस, राजद और वामदलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। ऐसे में लगभग सभी 81 विधानसभा सीटों पर सीधे मुकाबले की संभावना है। हेमंत सोरेन की चुनौती फिर से सत्ता में वापसी की होगी। भाजपा ने भी समय से पहले चुनावी तैयारी आरंभ कर कड़ी चुनौती दी है। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में करने में माहिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य भाजपा ने चुनाव की कमान सौंपी है तो यह स्पष्ट है कि पार्टी चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने को आतुर है। दो बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोड शो और जनसभा हो चुकी है। इसमें और तेजी आएगी। भाजपा ने किसी प्रतीय नेता का चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं किया। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा।

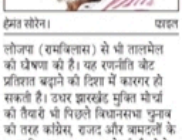

हेमंत सोरेन। फाइल

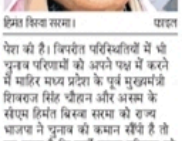

हेमंत बिस्वा सरमा। फाइल

राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमोनीत गठबंधन ने इन सुरक्षित सीटों में से 26 सीटों पर कब्जा कर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की थी। भाजपा केवल दो आदिवासी सुरक्षित सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा के लिए अभी भी आदिवासी सुरक्षित सीटों पर बढ़त बनाने की चुनौती है, क्योंकि इसके बगैर सत्ता के करीब पहुंचना आसन नहीं होगा। पांच प्रमंडलों में बंटे झारखंड में कोल्हान और संताल परगना प्रमंडल में भाजपा के समक्ष बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। समय रहते भाजपा ने इसे मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है। झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन इस मोर्चे पर लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों पर भाजपा खाता तक नहीं खोल पाई थी। संताल परगना की 18 में से 14 सीटों पर पार्टी पिछड़ गई थी। इस बार आदिवासी वोटों को रिझाने के लिए भाजपा ने घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव का नारा उछाला है। झामुमो के लिए राहत की बात यह है कि चम्पाई सोरेन सरीखे कद्दावर नेता के दल छोड़ने के बावजूद दल का कोई विधायक उनके साथ नहीं गया। समय रहते मोर्चा ने कोल्हान और संताल परगना प्रमंडलों में सेंगल को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास किए हैं।

चुनाव में फ्री स्कीम के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें भी चरम पर है। हेमंत सोरेन ने लगभग तीन माह पहले महिलाओं के लिए एक हजार रुपये महीना वाली मंईयां सम्मान राशि की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने की स्वीकृति दे गई है। इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी की गोगो दीदी योजना है, जिसके तहत पार्टी ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 2100 रुपये हर माह देने का वादा किया है। अधिकाधिक लुभावने वादे कर जो गठबंधन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगा, वही सत्ता पर भी काबिज होगा।

मंथन

अनुशासित और सशक्त समाज

बीती कुछ सदियों से भारतीय समाज को विभाजित करने के कुत्सित प्रयास हो रहे हैं। लिहाजा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय भावना को बलवती करने हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे

आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी
कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

स्मार्टफोन के व्यापक उपयोग से कहीं एक पुरानी की मानसिकता दुष्प्रभावित हो रही है। प्रतीकात्मक

समावेशी भारतीय संस्कृति संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करती है। किंतु इस कल्याणकारी संस्कृति को ग्रहण सा लग रहा है। ऐसे में यह चिंतन-मनन का विषय है कि इस संस्कृति को पुनः कैसे सर्वहितकारी मार्ग पर लाकर वैश्विक पटल पर सार्थक बनाए। वस्तुतः जातिगत विद्वेष ने भारतीय समाज को कई जातियों-उपजातियों में विभाजित कर दिया है। विदेशी आक्रमणों के सामने भारत की पराजय का एक बड़ा कारण यहां की जातिगत समस्याएं रही हैं। हमें जातिगत भेदभाव और सामाजिक असामानताओं को समाप्त करने होंगे। हमें स्वीकारना होगा कि एक सभ्य एवं संगठित समाज को व्यक्ति, जाति, समुदाय या आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। हमारा निर्मित एक सुसंगठित, अनुशासित और सशक्त समाज निर्माण होना चाहिए। ऐसा समाज जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय अस्मिता के संदर्भ में भी सशक्त हो।

हमें युवाओं को ऐसी पीढ़ी तैयार करने चाहिए जो नैतिक एवं सामाजिक रूप से जागरूक हों, अपने सामाजिक-राष्ट्रीय दायित्वों को निभा सकें एवं समाज को सुसंगठित करने एवं राष्ट्रीय हित के विषयों पर सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम हो। शेष नैतृत्व क्या करता है, सामान्य व्यक्ति उससे अधिक प्रभावित नहीं होता है। पड़ोस के लोगों का आचरण एवं व्यवहार कैसा है, इस पर वह अधिक ध्यान देता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म-नैतिक बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें एक व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। कहना न होगा कि भारत देश कभी भी हमारे लिए केवल कागज पर बना मानचित्र मात्र नहीं रहा है। हमने इसे भूमि का एक टुकड़ा न मानकर सदैव एक जाग्रत देवता के रूप में पूजा है।

सामाजिक एकजुटता : इस तथ्य को विवादित नहीं बनाना चाहिए कि प्राचीन काल से यहां जो निवास करते आए हैं, उन्हें 'हिंदू' नाम से जाना गया एवं उनके निवास स्थान को 'भारत भूमि' कहा गया। विष्णु पुराण में वर्णित है कि हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग भारत एवं इसके निवासी भारतीय कहलाए। हिमालय, हिंद महासागर, ईरान व इंडोनेशिया के मध्य के पूरे भू-भाग को आर्यावर्त अथवा भारतवर्ष व हिंदुस्तान कहा गया। स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने भारत एवं भारतवासियों के लिए ही कहा है- जो सिंधु नदी के उद्गम स्थान से कन्याकुमारी के समुद्र तक के विस्तृत भूभाग को भारत भूमि, पितृ भूमि, मातृ भूमि एवं पुण्य भूमि मानते हैं, उन्हें 'हिंदू' कहते हैं। आशय है कि इस राष्ट्र की उन्नति के साथ ही अवनति का हेतु भी हिंदू समाज ही है। अतः हिंदुओं की एकजुटता और सजगता अति आवश्यक है। इसका आशय कतई नहीं कि हम अन्य मतावलंबियों के विरोधी हैं। अपितु हमें सभी समुदायों एवं वर्गों को संगठित करना है, ताकि एक सशक्त-समृद्ध भारत का निर्माण हो सके।

राष्ट्रहित सर्वोपरि : इस हेतु राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत लोगों की संख्या बढ़ाने होगी। इसमें बाधाएं आएंगी, क्योंकि बाधा खड़ी करने वाले बिघ्नसंतोषी भी इसी समाज में हैं। राष्ट्रहित में इन बाधाओं को पार करना ही पड़ेगा। आज जो हमारे विचारों के विरोधी हैं, कल हमें उनें अपना बना लेना है। उनके साथ भी मिलकर राष्ट्रोत्थान में लग जाना है। ऐसा करते समय धर्म अर्थात नीति-नियम और पवित्र मन से दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। इस उद्देश्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में उन सुधारों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय और संस्कृतिक जीवन मूल्यों को सुदृढ़ कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनका समुचित प्रविधान है। यथा सर्वभौमिक जीवन मूल्यों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावीजन, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, परिणाम आधारित एवं चरित्र निर्माण युक्त समग्र शिक्षा, अनुभवजनित एवं कौशलयुक्त शिक्षा और समाजोपयोगी शिक्षा एवं शोध आदि। भविष्य में इस क्षेत्र में अधिक सघनता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

सशक्त युवा से सशक्त देश : कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से कुछ सेगठनों ने घर-घर जाकर परिवारों एवं उनके बच्चों में संस्कार के बीज बोने का बीड़ा उठाया है। वर्तमान में बच्चे एवं युवा मोबाइल, इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, जंक फूड सहित पाश्चात्य जीवन शैली एवं औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित हो गए हैं। वे पाश्चात्य जीवन शैली को ही सर्वोत्तम मान बैठे हैं। उन्हें इस बोध से बाहर निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अपने संस्कृतिक इतिहास एवं सच्चे राष्ट्रनायकों से अनभिज्ञ इस पीढ़ी के संज्ञान में इस विषय को लाने हेतु हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से युवाओं को सशक्त बनाना होगा। उनमें स्व का भाव जगाना होगा, जिससे वह अपनी सर्वभौमिक-सार्वभौगलिक सांस्कृतिक विरासत पर गौरवान्वित हो सकें।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • शुक्रवार • 18 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

किसी स्त्री के लिए एक पुरातत्वविद ही सबसे अच्छा पति हो सकता है। जितनी उसकी उम्र बढ़ेगी उतनी उसके पति की उसमें जिज्ञासा
-अगाथा क्रिस्टी

आगे की चुनौतियां

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक बनावट में काफी बदलाव आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश की यह पहली निर्वाचित सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री की शक्तियां और अधिकतर देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम हैं। इसी वर्ष जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति और अधिकार देने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 को संशोधित किया। इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल के पास पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा।

शायद इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फारुक अब्दुल्ला ने अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को कांटों का ताज कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए जम्मू संभाग से सुरेंद्र चौधरी को उपमुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि हमें लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जनादेश मिला है और हम पहले दिन से ही यह करना चाहते हैं। सीमित शक्तियों के साथ जनता की आकांक्षाओं को कितना पूरा कर पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। नेशनल कांफ्रेंस की मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से दो विशेष मांगें हैं। जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना और अनुच्छेद 370 की वापसी। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने चुनाव में प्रमुख रूप से इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर जनता से वोट मांगा है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वैधानिक मांग है। लेकिन अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया है अगर नेशनल कांफ्रेंस इसे बहाल करने की बात करती है तो केंद्र के साथ टकराव बढ़ेगा यह स्थिति उमर के प्रतिकूल जाएगी। राज्य के विकास योजनाओं को लेकर उमर को उपराज्यपाल के साथ समन्वय बनाकर चलना होगा। उमर अब्दुल्ला पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियों काफी बदल गई हैं। इन बदली भी परिस्थितियों के साथ उमर अपने आप को कितना ढाल पाते हैं यह आने वाला समय बताएगा।

जरूरी है सख्ती

एयरपोर्ट व विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां बढ़ती ही जा रही हैं। यह वाकई सरकार के लिए चुनौती बन गई हैं। तीन दिन के भीतर अलग-अलग विमान कंपनियों की बारह फ्लाइट्स को ऐसी धमकियां मिलीं। गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय व ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के साथ फर्जी बम कॉल पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक साथ सात फ्लाइट्स में बम होने की धमकी के कारण आनन-फानन उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर नये संवेदनशील मार्गों पर एअर मार्शलों के नये बैच तैनात किए जाएंगे। स्काई मार्शल सादे कपड़ों में सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी होते हैं, जो यात्री विमानों पर यात्रा करते हैं। जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स से धमकी दी गई, वे ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों में भी सक्रिय हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसियों को पत्र देने के बाद फौरन एक्स ने ये अकाउंट निलंबित कर दिये। मगर इस हड़कंप के चलते सुरक्षा-व्यवस्था, पुलिस, एअरपोर्टों, उड्डयन अधिकारियों, चालक दल, सरकारी महकमे समेत यात्रियों में दहशत फैल जाती है। फर्जी धमकियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि दोषी को अगले पांच वर्षों तक किसी भी विमान में उड़ान न भरने दी जाए यानी नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनचाही व हॉक्स कॉल्स को रोकने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। फर्जी कॉल्स द्वारा ब्लैकमेलिंग या धमकी देने वालों पर लगाम लगाने के सारे प्रयास बेमानी होते जा रहे हैं। बम या विस्फोटकों की धमकी देने वालों का मकसद अकसर ध्यान भटकाना, व्यवधान खड़ा करना या परेशान कर सामान्य संचालन को बाधित कर दहशत पैदा करना होता है। कभी-कभी कुछ सिरफिरे चर्चा में आने या बचकानेपन में भी इस तरह की हरकतें करते पाए जा चुके हैं, परंतु इस आशंका में फर्जी या छद्म कॉल्स की अनदेखी करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का फैसला उचित है। साथ ही यह व्यवस्था भी जरूरी है कि इस तरह की झूठी धमकी देने वालों के भीतर इतना भय पैदा हो सके कि वे घटना का मंसूबा बनाते हुए भी सिहर जाएं।

सैन्य बल/डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव

ताकत देंगे प्रीडेटर ड्रोन

भारत ने 15 अक्टूबर अमेरिका के साथ ड्रोन खरीद के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजधानी दिल्ली में भारत के शीर्ष रक्षा और रणनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य चीन के साथ विवादित सीमाओं पर भारतीय सेनाओं की यौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की केन्द्रीय समिति (सीसीएस) ने एमक्यू-9बी स्टेटर किलर ड्रोन की खरीद को मंजूरी प्रदान की थी।

प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से भारत के शत्रु देश भारत को आंख दिखाने से डरेंगे। ये समुद्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और जमीनी सीमा के उस पार लक्ष्य साधने सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत विशेष रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है। ये ड्रोन हवा से जमीन पर सटीक मार करने में अत्यंत सक्षम हैं। समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे तथा भारतीय वायु सेना व थल सेना को आठ-आठ स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से जिस मानवरहित प्रीडेटर ड्रोन एमक्यू-9 वी का समझौता हुआ वह संसार का सबसे उन्नत श्रेणी का ड्रोन है। इस मानवरहित प्रीडेटर ड्रोन एमक्यू-9 वी के दो वर्जन हैं। पहला स्काई गार्डियन और दूसरी सी गार्डियन। एमक्यू-9 वी, सी गार्डियन ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं। प्रीडेटर ड्रोन एमक्यू-9 वी सी गार्डियन का इस्तेमाल क्वाड समूह के सदस्य चारों देश करते हैं। कर्तमान में भारत एक खुफिया एकत्रीकरण अभियान के हिस्से के रुप में एमक्यू-9 वी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि इसे मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज तथा बचाव एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी उपयोग में लाया जा सकता है। दुश्मन क्षेत्र के ठिकानों पर एकदम सटीक निशाना लगाने वाला यह ड्रोन इंटर-किलर यूएवी के नाम से प्रसिद्ध है। पानी की सतह के उपर और अंदर दोनों ही प्रकार की जगहों की निगरानी व छानबीन के लिए इसमें 80 से ज्यादा जी-साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वह डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के माध्यम से पानी के भीतर हो रही आवाजों की पहचान करता है। इन खूबियों वाले ड्रोन से भारतीय सेनाएं काफी ताकतवर हो जाएंगी।

बंदरगाहों से घटेगी निर्यात लागत

अर्थव्यवस्था

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

इस समय पश्चिम एशिया संकट के कारण देश से घटते हुए निर्यात, बढ़ते विदेश व्यापार घाटे, लाल सागर में बढ़ते संकट और कंटेनरों की किल्लत की चिंताओं के बीच देश से वस्तुओं के निर्यात की लागत घटाने के लिए हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत शिपिंग कॉरपोरेशन बड़े कंटेनर जहाज चलाएगी। बंदरगाह शुल्क में कटौती की जाएगी तथा निर्यात की खेपों को जल्दी भेजने के लिए प्रक्रिया में तेजी के उपाय शामिल हैं।

विगत 16 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर नए तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए अपने संदेश में कहा कि यह टर्मिनल भारत के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सितारा है। इस नये टर्मिनल से वीओ चिदंबरनार पोर्ट के सामर्थ्य में भी विस्तार होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक बंदरगाह से निर्यात बढ़ाने के नये फैसलों से देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्यात भी बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि इस समय देश के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ उन्हें समुद्री व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति के साथ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। विगत 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वधावन देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाए।

उन्होंने कहा कि वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत कम होगी। यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। गौरतलब है कि भारत की 7517 किमी लंबी समुद्री तटरेखा है, जो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करती है। देश के विशाल समुद्र तटों पर, 13 प्रमुख बड़े और 212 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों में पूर्वी तट पर हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराज, चेन्नई, तूतीकोरीन और पोर्ट ब्लेयर हैं। पश्चिमी तट पर कोचीन, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव, जवाहरलाल नेहरू, कांडला और मुंबई बंदरगाह है। भारतीय बंदरगाह अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक व्यापार के लिए

शताब्दियों से महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं और बंदरगाहों से विदेश व्यापार लगातार बढ़ता गया है। इस समय भारत का मात्रा के हिसाब से 95 फीसद और मूल्य के हिसाब से 70 फीसद व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता है।

निसंदेह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होने के कारण भारतीय बंदरगाहों ने समुद्री (तटीय) राज्यों को देश में औद्योगिक विकास के मद्देनजर पसंदीदा स्थल बना दिया है। परिवहन संबंधी न्यूनतम बाधाओं के साथ-साथ लॉजिस्टिक लागत में कमी बंदरगाहों के निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ाने वाला प्रमुख कारण है। निश्चित रूप से पिछले एक दशक में भारत अपने बंदरगाहों को समुद्री व्यापार की धुरी बनाने के लिए लगातार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। निजी बंदरगाहों को प्रोत्साहन दिया गया है। भारत कार्गो और जहाजों को संभालने में अपनी दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से अपने बंदरगाहों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। वर्ष 2015 में सागरमाला कार्यक्रम के लॉन्च होने के बाद से बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। मार्च 2022 तक सागरमाला कार्यक्रम के लिए 5.40 लाख करोड़ रुपए की निर्धारित लागत वाली कुल 802 परियोजनाओं में से 1.12 लाख करोड़ रुपए की 221 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4.28 लाख करोड़ रुपए की 581 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति प्रदान की जा रही है। पीएम गति-शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन पर केंद्रित है जिसमें बंदरगाह भी शामिल हैं।

ज्ञातव्य है निजी भागीदारी बंदरगाह आधारित विकास की मुख्य रणनीति है। इस संबंध में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की सभी परियोजनाएं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत सूचीबद्ध है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि जो समुद्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (एनएलपी) जनवरी, 2023 में शुरू हुआ है, वह एक ऐसा वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों को आईटी के माध्यम से जोड़ता है। जिसका उद्देश्य लागत और समय की देरी को कम करते हुए दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। सरकार ने बंदरगाह और बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी हुई है। इसके अलावा, 11.8 अरब डॉलर के योजनाबद्ध आउटले के साथ समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम भी अत्यधिक लाभप्रद है। अब मेरीटाइम इंडिया मिशन 2030 के तहत बंदरगाहों के विकास और लॉजिस्टिक लागत घटाकर समुद्री अर्थव्यवस्था से देश को लाभांवित करने का नया अध्याय आगे बढ़ रहा है। इन सबके साथ-साथ वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान तय किए गए व्यापक रोडमैप के साथ समुद्री अमृतकाल विजन 2047 भारत के समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है।

उम्मीद करें कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बंदरगाहों से निर्यात बढ़ाने के लिए जो अहम फैसले लिए हैं, उनके कारगर क्रियान्वयन पर शुरू से ही ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करें कि वधावन देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में भारत के समुद्री व्यापार की नई धुरी बनेगा। साथ ही गतिशक्ति योजना, नई लॉजिस्टिक नीति और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का सफल क्रियान्वयन रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय और 2047 तक विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

> उम्मीद करें कि वधावन देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में भारत के समुद्री व्यापार की नई धुरी बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, नई लॉजिस्टिक नीति और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का सफल क्रियान्वयन रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय और 2047 तक विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगा

कायरोप्रैक्टिक

यानी झटके से इलाज के नाम पर जोखिम में जान

- कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झटके से गर्दन का दर्द दूर करने या फिर कमर की जकड़न सही करने का दावा किया जाता है। इस तरह के विज्ञान को कायरोप्रैक्टिक यानी झटके से उपचार कहा जाता है
- विदेश में इस उपचार के लिए बाकायदा प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं, लेकिन अपने यहां इसके प्रशिक्षण की फिलहाल कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उपचार का दावा करने वाले 'नीम हकीम' ही कहे जाएंगे जो उपचार के नाम पर लोगों की जान जोखिम में डालते हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

सोनम वांगचुक और उनके सहयोगी न केवल हमें हिमालय क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत की याद दिला रहे हैं, बल्कि यह भी पुख्ता कर रहे हैं कि हिमालय को लेकर कोई ठोस नीति होना हमारे लिए कितना जरूरी है।

योगेन्द्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
@_YogendraYadav

ईश विश्वास

श्रीराम शर्मा आचार्य

चोट

खाया हुआ सांप आक्रमणकारी पर ऐसी फूफकार मारकर दौड़ता है कि उसके होश छूट जाते हैं, बचाव के लिए भागना ही पड़ता है। सांसारिक व्यथाओं से विक्षुब्ध मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति होती है। जब मनुष्य को पीड़ाएं चारों ओर से घेर लेती हैं और कोई सहारा नहीं सूझता तो वह निष्ठापूर्वक अपने परमेश्वर को पुकारता है। हार खाये हुए मनुष्य की कातर पुकार से परमात्मा का आसन हिल जाता है और उन्हें सारी व्यवस्था छोड़कर भक्त की सेवा के लिए भागना पड़ता है। मनुष्य ने बुलाया हो और उसकी शुभेच्छा न आई हो, मनुष्य ने सहायता मांगी हो और परमात्मा ने मनोरथ पूर्ण न किया हो, मनुष्य की प्रार्थना पर परमात्मा दौड़ कर न चला आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे बुलाइये, वह आपके अंतःकरण में दिव्य प्रकाश बनकर उतरेगा, मधुर संगीत बनकर हृदय में गूंजन करेगा। पर उसे सच्चे हृदय से बुलाइये, निष्कपट और निश्चल होकर पुकारिये। ऐसा समय आता है जब मनुष्य संसार को भूलकर कुछ क्षण के लिए ऐसे दिव्य लोक में पहुंचता है, जहां उसे असीम सहानुभूति और शाश्वत शांति मिलती है। परमात्मा के निकट पहुंच कर आत्मा जब भक्ति भावना से अपनी संवेदनाएं प्रस्तुत करती है, तो अनिर्वचनीय आनंद मिलता है। अंतःकरण की समस्त वासनाएं विलीन हो जाती हैं, इंद्रियों की चेष्टाएं शांत हो जाती हैं। हिरण्यकश्यपु की हठधर्मिता से दुखी बालक प्रह्लाद ने उसे बार-बार पुकारा, उसका नारायण बार-बार उसकी मदद के लिए दौड़ा। विष पिया उसके भगवान ने समुद्र के गर्त में पांथेय बना प्रह्लाद का भगवान। इससे भी काम न चला तो नृसिंह बनकर प्रह्लाद का भगवान खंभा चीरकर दौड़ा आया। जिसने मनुष्य को पैदा किया उसके हृदय में अपनी संतान के लिए मोह न हो? ममता न हो यह कैसे हो सकता है? मनुष्य बुलावे और वह न आए ऐसा कभी हुआ नहीं। द्रौपदी जान गई थी कि सभा में उसे बचाने वाला कोई नहीं है। दुःशासन चीर खींचता है। लाज न चली जाए, इस भय से निर्बल नारी दीनानाथ को पुकारती है। भगवान श्रीकृष्ण आते हैं और उसका चीर को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। दुःशासन थककर चूर हो गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। परमात्मा की लीला अपरंपार है।

रीडर्स मेल

सख्त कानून बने

आजकल सोशल नेटवर्क साइट्स के जरिए विमान में बम रखे जाने की अफवाह देकर लोगों को भयभीत करने का काम किया जा रहा है। विगत तीन दिनों में लगभग बीस विमानों में बम रखे जाने की झूठी खबर देकर विमान कंपनियों, यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने संकट उत्पन्न किया जा रहा है। उनमें में कई विमान अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर थे। किसी भी तरह की सूचना मिलने के पश्चात विमान को निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उतार कर उसकी सघन जांच की जाती है। इस प्रक्रिया से यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में विलंब होता है एवं यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। साइबर अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए एवं पुलिस को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

हिमांशु शेखर, गया

अतिआत्मविश्वास ने डुबोई लुटिया

भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिस प्रकार से 46 रन पर मात्र 31.2 ओवर खेलकर भारतीय दिग्गज धराशायी हुए, उससे लगता है कि अति आत्मविश्वास ने भारत के शेरों की लुटिया डुबो दी। क्रिकेट खिलाड़ियों की दिग्गज टीम अति अविश्वसनीय पारी ने सिद्ध कर दिया कि विश्वस्तरीय टीम इतना निकृष्ट एवं अकल्पनीय प्रदर्शन भी कर सकती है।

डॉ. सुधाकर आशावादी, मेरठ

वैश्विक मंच पर आवाज उठाए भारत

कनाडा का पक्षधर क्यों बन रहा है अमेरिका? दूसरा पकिस्तान बनने की राह पर कई वर्षों से भारतीय लोगों के प्रति दुराचार के भाव रख रहा है। विश्व शांति के अग्रदूत भारत के खिलाफ विदेश से जो साजिश चल रही है वह बहुत ही दुखद है। वहीं अमेरिका भी दुश्मन देशों की बोली बोल रहा है। वहीं भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने पकिस्तान जा पहुंचा है वहीं भारत कनाडा तनाव पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर भारत को इस विवाद के लिए गलत ठहराया रहा है। अमेरिका जैसा विश्व चौधरी देश भारत की ताकत के आगे बौना साबित हो रहा है, तभी वह इस तरह की बात कर रहा है। कुल मिलाकर विदेशी धरती से लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। इन नाकारात्मक ताकतों के खिलाफ भारत को मजबूती के साथ विश्व पटल पर आवाज उठानी ही होगी।

हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

कौन बनेगा सरताज

झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दोनों राज्यों में भाजपा का बहुत कुछ दांव पर है। हालांकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी हालत में सत्ता में दोबारा आने की कोशिश में है, मगर उसके लिए लड़ाई वाकई कठिन है। देखना होगा भाजपा इन दोनों राज्यों में हरियाणा की तरह आश्चर्यजनक जीत हासिल कर पाएगी? क्या महाराष्ट्र के तनावपूर्ण गठबंधनों से जनता की राय प्रभावित होगी, खासकर मराठा आरक्षण को लेकर जारी बहस के मद्देनजर? झारखंड में आदिवासी और गैर-आदिवासी वोटों पर क्या असर पड़ेगा? 2024 में होने वाले निर्णायक राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी में, ये चुनाव कथानक को नया रूप दे सकते हैं।

अंशु भारती, बेगूसराय
letter.editorsahara@gmail.com

बुद्ध धम्म शिक्षा में पाली की भूमिका

चिंतन

बैशाली सरकार

पाली बुद्ध के समय, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जन भाषा (लिंगुआ फ्रैंका) थी। कई अन्य साहित्यिक भाषाओं की तरह, यह विभिन्न बोलियों के मिश्रण से विकसित हुई है, जो भाषाई प्रभावों की एक समृद्ध विविधता को दर्शाती है, जिसमें अर्धमागधी प्रमुख थी। इसे मुख्य रूप से प्रारंभिक बौद्ध परंपरा के भीतर उपयोग किया गया है। पाली भाषा ने अपनी अनूठी विकास प्रक्रिया के कारण बुद्ध धम्म के प्रसार में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

थेरवाद बौद्ध परंपरा में पाली भाषा का विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह बुद्ध के उपदेशों का मूल माध्यम है। यह विशेष रूप से तिपिटक में स्पष्ट होता है, जो बुद्ध को समर्पित उपदेशों का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह है। त्रिपिटक तीन 'पिटकों' (टोकरी) में विभाजित है: विनय पिटक, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी आचार संहिता को निर्धारित करता है; सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उन उपदेशों को संग्रहित किया गया है जो उन्होंने पैंतालीस वर्षों की महान यात्रा के दौरान दिए, जिसमें उपयुक्त उदाहरण, रूपक और उपमाएं शामिल हैं; और अभिधम्म पिटक, जो शिक्षाओं का दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण प्रदान करता है, जिससे मन, मानसिक कारक, भौतिक तत्वों और पदार्थ की गुणवत्ता के बीच के अंतरसंबंध और इनसे परे जाने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जाता है।

यह मनोविज्ञान और नैतिकता का सच्चे अर्थों में संयोजन है। बौद्ध धर्म के इन तीन विभागों का आपस में गहरा संबंध है और ये बुद्ध की शिक्षाओं के अभिन्न और परस्पर पूरक भंडार हैं। ये क्रमशः सदाचार (शील), ध्यान (समाधि) और प्रज्ञा (पन्ना) के मार्गों को स्पष्ट करते हैं, जो साधकों के लिए मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक समग्र मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। पाली दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों, जैसे भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया आदि में पारंपरिक बौद्ध मठवासी शिक्षा प्रणालियों के भीतर एक जीवित भाषा के रूप में आज भी फल-फूल रही है। इन क्षेत्रों में पाली का अध्ययन मठवासी प्रशिक्षण का एक आधारभूत

हिस्सा है, जहां भिक्षु और भिक्षुणियां पाली ग्रंथों में महारत हासिल करने के लिए लंबे समय तक अध्ययन करते हैं।

जैसे-जैसे बौद्ध धर्म वैश्विक रूप से फैलता और विकसित होता जा रहा है, पाली का ज्ञान पारंपरिक बौद्ध देशों के बाहर के विद्वानों, साधकों और शिक्षकों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। यह सतत अध्ययन आधुनिक दर्शकों के लिए बुद्ध के उपदेशों को अनुकूलित और व्याख्यायित करने में मदद करता है, जबकि उनके मूल संदर्भ के प्रति निष्ठा बनाए रखता है। भारत सरकार द्वारा पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसके पुनर्जीवन और पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करना उन देशों की सांस्कृतिक धरोहर के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में पाली की स्थिति को रेखांकित करता है, जहां बुद्ध धम्म फला-फूला है।

अधिकांश बौद्ध देशों के संघों के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सदस्य होने के साथ, जो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, शास्त्रीय भाषाओं जैसे पाली के ज्ञान का सक्रिय रूप से उत्सव मनाते हैं; पाली भाषा के पुनरुत्थान की दिशा में काम करते हुए, हम केवल एक प्राचीन भाषा को पुनर्जीवित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुद्ध धम्म के सार को उसकी वास्तविक रूप में समझने के द्वार खोल रहे हैं। युवा विद्वानों और साधकों को पाली अध्ययन में शामिल करके, IBC उन्हें उन शिक्षाओं की खोज और व्याख्या के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन्हें लंबे समय तक भाषाई बाधाओं के कारण गलत समझा या गलत व्याख्यायित किया गया था। भाषा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को समझने में भूमिका को मान्यता देते हुए, IBC विशेष रूप से उन असफलताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अनुवाद की त्रुटियों ने धुंधला कर दिया था। यह मान्यता सरकार को पाली को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से लक्षित पहलों को लागू करने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पाली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रासंगिक बनी रहे। शैक्षिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक पहल और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पाली अपने स्थान को फिर से हासिल कर सकती है, जो उन समाजों की आध्यात्मिक और बौद्धिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है, जो इसे संजोते हैं।

(लेखिका बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं)

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, गौता-परियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहगुंज, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा पाटलीपुत्र टावर, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी ।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6453
आर.एन.आई. नं. बीआईएचआरबीएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्रियों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 209

हड़ताल का अंत

एक स्वागतयोग्य घटनाक्रम में कर्मचारियों, कंपनी प्रबंधन और तमिलनाडु सरकार के बीच सफल बातचीत के बाद श्रीपेरंबुदूर स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण संयंत्र में चल रही 37 दिन पुरानी श्रमिकों की हड़ताल इस सप्ताह समाप्त हो गयी। इस हड़ताल की शुरुआत तब हुई जब कर्मचारियों ने काम के बोझ और कम वेतन भत्तों, कड़े ओवरटाइम लक्ष्यों और सैमसंग की उनके संगठन को मान्यता न देने की नीति को लेकर आपत्ति प्रकट करनी शुरू की। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) से संबद्ध सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन (एसआईडब्ल्यूयू) की मान्यता की मांग हड़ताली कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच तनाव का प्रमुख मुद्दा थी और अब यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष है। दोनों पक्षों को अब संगठन की मान्यता के मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

इस बीच एक सकारात्मक बात यह हुई कि कंपनी प्रबंधन ने काम के हालात और वेतन भत्तों से संबंधित मांग को स्वीकार कर लिया। यह उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया और कर्मचारी संगठन का मामला अदालत में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में दोनों पक्ष अदालती निर्णय का सम्मान करेंगे। बहरहाल व्यापक स्तर पर देखें तो यह जोखिम हमेशा रहता है कि औद्योगिक विवाद बढ़ जाए। हम अतीत में ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं जहां ऐसी घटनाओं से विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की छवि पर बुरा असर पड़ता है। बीते दशकों में देश को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण केंद्र बना पाने में हमारी निरंतर नाकामी की एक वजह देश में श्रम संगठनों की प्रवृत्ति और देश के श्रम कानूनों की प्रकृति भी है। इसके परिणामस्वरूप कंपनियां पूरी कोशिश करती हैं कि वे ऐसे विवाद में न पड़ें। इसके लिए या तो वे अपना आकार छोटा रखती हैं या फिर उत्पादन को विभिन्न संयंत्रों के बीच बांट देती हैं।

अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन तथा अन्य के हालिया शोध ने दिखाया है कि विनिर्माण कंपनियां किसी एक कारखाने का आकार बढ़ाने के बजाय अपने कर्मचारियों को एक ही राज्य की अलग-अलग फैक्टरियों में भेज देती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का विनिर्माण न केवल बड़े पैमाने पर काम करने से होने वाला असर उत्पन्न करने में नाकाम रहा बल्कि हम प्रतिस्पर्धा और निर्यात के मोर्चे पर भी पीछे छूट गए। इसके अलावा विनिर्माण संयंत्रों में अनुबंधित श्रम तेजी से बढ़ा है और ऐसे श्रमिकों के पास मोलतोल की पर्याप्त क्षमता नहीं होती और न ही वे संगठित हो पाते हैं और न हड़ताल में शामिल हो पाते हैं। ऐसे में कुछ कर्मचारियों वाले कई संयंत्र स्थापित करना और अनुबंधित श्रमिकों से काम करना कंपनियों को आर्थिक या राजनीतिक झटकों से निपटने में मदद करता है। इस मामले की बात करें तो श्रीपेरंबुदूर संयंत्र के कुल 5,000 श्रमिकों में अनुबंधित श्रमिकों की तादाद अच्छी खासी है और वे हड़ताल में शामिल नहीं हुए।

यह बात अच्छी तरह ज्ञात है कि औद्योगिक विवाद संभावित निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौजूदा चरण में जबकि देश बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन प्लस वन की रणनीति का लाभ उठाना चाहता है, तब यह खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में यह अहम है कि कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच के मतभेदों को सौहार्दपूर्ण माहौल में हल किया जाए। संबंधित राज्य और केंद्र सरकार को भी यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभानी होगी कि कर्मचारियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए। इस संदर्भ में देश के श्रम कानूनों में सुधार जरूरी है। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार संहिताओं में समेटकर अच्छा कदम उठाया हालांकि अभी भी उनका क्रियान्वयन होना बाकी है। इस काम को राज्यों के साथ सहमति कायम करके आगे ले जाया जाना चाहिए। एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले संयंत्र कायम करने होंगे। इसकी कामयाबी में श्रमिकों के साथ रिश्तों के प्रबंधन के तौर तरीकों की अहम भूमिका होगी।

विकसित भारत के लिए तय करें प्राथमिकताएं

वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल करना सरल नहीं है। किंतु ऐसे अनेक अवसर हैं जिनकी मदद से हम यह लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। बता रहे हैं लवीश भंडारी

क्या 2047 तक देश को विकसित बनाना संभव है? वर्ष 2022 में 2,390 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ हम निम्न आय वाले देशों की सूची में नीचे की ओर थे। इस सूची में शामिल देशों में प्रति व्यक्ति आय 1,136 से 13,846 डॉलर तक थी। जाहिर है कि फासला काफी अधिक है और भारत को उच्च आय वाले देशों की सूची तक पहुंचने में समय लगेगा। हाल-फिलहाल ज्यादातर अनुमानों में भारत की दीर्घकालिक वृद्धि दर 6 से 7 फीसदी के बीच रहने की बात कही गई है, जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए काफी नहीं है। ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने में बाधा बनेंगी मगर तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण ऐसी मौके भी मिलेंगे, जो ऊंची वृद्धि में मददगार बनेंगे।

ऐसे लक्ष्य का क्या फायदा, जो महत्त्वाकांक्षी न हो? और ऐसी महत्त्वाकांक्षा का क्या फायदा, जिसे हासिल न किया जा सके? इसलिए वृद्धि के वर्तमान स्तर के साथ तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल होता नहीं दिखता मगर दाई दशक बहुत लंबा समय होता है। समय के साथ हमारे पास बेहतर मानव संसाधन होगा, बेहतर तकनीक उपलब्ध होगी, अधिक ज्ञान होगा। इसलिए लक्ष्य को कम करने के बजाय हमें भविष्य में उच्च वृद्धि के लिए तैयार होना चाहिए और उन बिंदुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनमें देर नहीं की जा सकती।

आदर्श तौर पर भारत को बहुत कुछ हासिल करना है और हम जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा है। उनमें राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, बेहतर मानू पूंजी, भूमि, श्रम एवं पूंजी बाजार से जुड़े सुधार शामिल हैं। ये सभी तथा कुछ अन्य फालतू आइम हैं मगर मेरा सवाल है कि अब सरकार को ऐसा क्या करना है, जिसमें एक साल भी देर नहीं की जा सकती? जाहिर है वे बदलाव, जिन्हें लागू करने में नकल लगता है। सोच-विचारकर मुद्दे इस समय दो परिवर्तन सबसे जरूरी लगते हैं।

मेरी सूची में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा है। 2047 में एक औसत श्रमिक की श्रम उत्पादकता आज की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पर एक रुपया ज्यादा खर्च करने का ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि राज्य और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर कई कमियां हैं। यह मान्यता पूरी तरह गलत नहीं है लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर निवेश रोक देना एकदम गलत है। हमें सोचना है कि शिक्षा बेहतर ढंग से कैसे दी जाए मगर हमें शिक्षकों, कक्षाओं, सुविधाओं, शिक्षक प्रशिक्षण आदि पर तत्काल अधिक धन खर्च करने की भी जरूरत है। हमें प्राथमिक शिक्षा में कला, क्राफ्ट, संगीत और दूसरी पठनेतर गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा। इसके लिए खेल-खेल में शिक्षा देने के तरीके अपनाने होंगे क्योंकि कल का उच्च उत्पादकता वाला कामगर रचनात्मक भी होना चाहिए। डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से शिक्षक और विद्यार्थियों की निगरानी, सतत प्रशिक्षण, सुधार, हर बच्चे की प्रगति पर नजर रखना संभव है। प्राथमिक शिक्षा के लिए मिशन की तरह काम करना होगा, जो संभव ही नहीं है, बहुत जरूरी भी है। आज प्राथमिक स्कूलों को सुधारना आईआईटी और विश्वविद्यालय बनाने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे को प्राथमिक स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिली है तो कौशल प्रदान करने जैसी वर्तमान प्राथमिकताएं भी बेहतर ढंग से अमल में लाई जा सकती हैं। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं है तो कौशल प्रदान करने के लिए कितना भी धन खर्च कर लें, वांछित नतीजा नहीं मिलेगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि भारत विकसित देश बन जाता है मगर श्रम उत्पादकता में जरूरी सुधार नहीं होता है। तब कैसी अर्थव्यवस्था बनेगी? आज दुनिया में कई देश हैं, जहां असमानता बहुत अधिक है और जो प्रगति को व्यापक स्तर तक नहीं पहुंचा सके। खराब शिक्षा वाला भारत भी वैसा ही होगा। इसलिए भारत के पास प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां हल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसे यह अभी करना होगा।

दूसरी प्राथमिकता है कृषि भंडारण और ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स। पूरे दक्षिण एशिया में मौसम की अतिरंजना के कारण वृहद आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अगले वाले समय में इसमें इजाफा होगा। भारत में भी खाद्य मुद्रास्फीति को संभालना आसान नहीं है। चीन ने भारत के मुकाबले बहुत तेज दर से वृद्धि की है मगर भारत में खाद्य मुद्रास्फीति वहां की तुलना में अधिक रही है। दोनों देशों में सरकारें कृषि में हस्तक्षेप करती हैं किंतु अन्य अंतरों के बीच बड़ा अंतर यह है कि चीन अपने यहां खाद्य का प्रबंधन करने में अधिक माहिर है। भारत भी अपनी कृषि उपज को अच्छे ढंग से संभाल सकता है मगर इसके लिए कृषि भंडारण के लिए वेयरहाउस का बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, जिसमें शीत भंडारगृह यानी कोल्ड स्टोरेज भी शामिल हों। हम इसमें ढुलाई की बेहतर प्रणाली भी जोड़ सकते हैं मगर भंडारण की व्यापक सुविधा सबसे जरूरी है।

कृषि बाजारों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का विरोध दुर्भाग्य से सफल रहा मगर इसे कृषि में सभी तरह की प्रगति रोक देने वाली यथास्थिति नहीं मान लेना चाहिए। किसान आढ़तियों पर निर्भर हों या न हों, भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होने से उन्हें लाभ जरूर होगा। इससे आढ़तियों पर निर्भरता कम होगी, किसान सशक्त होंगे और खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव भी घटेगा। किसान जितने अधिक प्रगतिशील होंगे, वे भंडारण का व्यापक नेटवर्क होने पर उच्च मूल्य वाले किंतु जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों की ओर उतना ही अधिक बढ़ सकेंगे। इसलिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और उनकी मदद से किसान खाद्यान्न की खेती से दूर जा सकेंगे।

सवाल यह है कि वेयरहाउसिंग और कृषि लॉजिस्टिक्स में अभी निवेश क्यों? हम 10 साल और इंतजार क्यों नहीं कर सकते? पहली बात देश में जिस तरह की खेती हो रही है, उसमें नई तकनीक, उत्पादन और प्रक्रिया के प्रसार में बहुत समय लग जाता है। दूसरी बात जलवायु परिवर्तन का आसन्न संकट है, जिसके कारण हमें मौसम की अतिरंजना से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी बात, हम खेती की प्रगति में बाधा डाल रही यथास्थिति को खत्म करने के लिए कानून में बदलाव नहीं कर पाए, इसलिए उस काम के लिए तकनीक तथा बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने का समय आ गया है।

हमने पहले ही कहा है कि कई चुनौतियां आएंगी तो कई अवसर भी आएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा तथा भंडारण तकनीक में सुधार के साथ ऊर्जा परिवर्तन सस्ता होता जाएगा और डिजिटल क्रांति कई क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रभावशीलता बढ़ा देगी। भविष्य में आने वाले इन अवसरों की सूची बहुत लंबी है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े बदलाव भी अपने साथ कई लाभ लाएंगे। उदाहरण के लिए भारत अभी जीवाश्म ईंधन के शुद्ध आयात पर 100 से 150 अरब डॉलर (तेल की ऊपर-नीचे आती कीमतों के हिसाब से) खर्च करता है और यह खर्च निकट भविष्य में बढ़ता जाएगा। लेकिन अगले दशक के मध्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही इसमें कमी आने लगेगी। इससे होने वाले लाभ का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है मगर वह बहुत अधिक हो सकता है।

कुल मिलाकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भले ही अभी पहुंच से बाहर लग रहा है किंतु भविष्य में अनेक अवसर हैं, जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा करने के साथ ही हमें सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिक शिक्षा और कृषि भंडारण तथा लॉजिस्टिक्स को तत्काल प्राथमिकता मानकर काम किया जाए। इसमें अधिक प्रयास किए गए तो और भी अच्छा होगा।

(लेखक सीएसईपी रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख हैं। लेख में निजी विचार हैं)

सरकारी उपक्रम और भुगतान चूक के मामले

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उस समय राहत की सांस साफ सुनी गई, जब बैंकरों को पता चला कि सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को संकट से उबारने की सोच रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों (पीएसयू) को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। दूरसंचार और इस्पात मंत्रालय इनके लिए राहत पैकेज पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहे हैं।

व्यय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग तथा दूरसंचार विभाग के सचिवों की एक समिति एमटीएनएल के ऋण पर अंतिम फैसला लेगी। 25 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक ने एमटीएनएल को दिया अपना कर्ज गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की श्रेणी में डाल दिया क्योंकि 30 जून से ही कंपनी ने किस्त और ब्याज नहीं चुकाए थे। इससे पहले सितंबर के मध्य में ही पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने भी दूसरे बैंकों की तरह कंपनी के खाते को डाउनग्रेड कर दिया था।

स्टेट बैंक ने 1 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंजों के पास एक पत्र भेजा। पत्र के मुताबिक एमटीएनएल के ऋण खाते में 30 सितंबर तक बैंक के कुल 325.52 करोड़ रुपये बकाया थे। एमटीएनएल ने 13 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उस पर पीएनबी के कुल 441 करोड़ रुपये बकाया हैं और इनमें से 46 करोड़ रुपये वह समय से नहीं चुका पाई है। इससे पहले एमटीएनएल ने यह भी बताया था कि जून और अगस्त 2024 के बीच उसे कई सरकारी बैंकों के 519 करोड़ रुपये चुकाने थे, जो वह नहीं चुका पाई है।

एमटीएनएल सूचीबद्ध कंपनी है, जिसमें भारत सरकार की 56.25 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम की 13.12 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मार्च 2024 में इसकी नेटवर्थ (हैसियत) 23,663 करोड़ रुपये घट गई थी क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में 2,915.1 करोड़ रुपये का घाटा झेलने के बाद वित्त वर्ष 2024 में भी इसे 3,302 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। उस पर कुल 35,600 करोड़ रुपये के करीब का कर्ज है, जिसमें 27,700 करोड़ रुपये के केंद्र की गारंटी वाले बॉन्ड हैं। इन बॉन्डों की अब भी 'एएए (सीई)' रेटिंग ही चल रही है। सीई का मतलब है कि सरकार की गारंटी मिलने पर कर्ज बढ़ाया गया है। बाकी 7,900 करोड़ रुपये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पीएनबी, पंजाब ऐंड सिंध बैंक और यूको बैंक से सावधि ऋण और पूंजीगत ऋण के तौर पर मिले हैं।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

आरआईएनएल को विजाग स्टील भी कहा जाता है और उसमें सरकार की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसे वित्त वर्ष 2023 में (नवीनतम ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक) 2,858 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और मार्च 2023 में इसकी नेटवर्थ 391 करोड़ रुपये थी। लेकिन वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में यह नेटवर्थ भी खत्म हो गई क्योंकि कंपनी को 2,058 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।

आरआईएनएल पर कुल 20,413 करोड़ रुपये का ऋण है। इसमें 10,812 करोड़ रुपये के सावधि ऋण और 9,601 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी है। एमटीएनएल की तरह ही जून में यह कंपनी भी किस्त और ब्याज चुकाने में नाकाम हो गई, जो सिलसिला अब तक चल रहा है। लगता है कि सभी बैंकों ने सितंबर तिमाही में आरआईएनएल और एमटीएनएल के खातों को फंसे ऋण की श्रेणी में डाल दिया है। सरकार हरकत में नहीं आई तो सभी को बड़े खाते में डालना पड़ सकता है।

सरकार ने एमटीएनएल को जुलाई 1997 और आरआईएनएल को नवंबर 2010 में नवरत्न का दर्जा दिया। नवरत्न कंपनियां केंद्रीय पीएसयू होती हैं और देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। आम तौर पर इन्हें पूंजीगत व्यय, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश तथा मानव संसाधन प्रबंधन जैसे मामलों में स्वायत्तता हासिल होती है।

एमटीएनएल की स्थापना 1 अप्रैल 1982 में की गई थी। इसका मकसद देश के प्रमुख महानगरों दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ाने, नई सेवाएं शुरू करने और दूरसंचार विकास की जरूरतों के लिए राजस्व हासिल करना था। भारत का पहला टेलीफोन एक्सचेंज 1882 में मुंबई में ही लगाया गया था। एमटीएनएल की वेबसाइट आखिरी बार फरवरी 2018 में अपडेट की गई थी और 2012 के बाद से ही उसने अपनी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करना बंद कर दिया है। पहले हासिल की गई जिन उपलब्धियों का जिक्र है, उनमें 1992 में वॉयसमेल की शुरुआत, 2000 में मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड और 2003 में महानगर टेलीफोन मॉरिशस लिमिटेड जैसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनियों की स्थापना तथा 2008 में 3जी मोबाइल सेवा की शुरुआत शामिल हैं।

सरकार ने बैंकिंग उद्योग को हाल ही में आश्वासन दिया है कि एमटीएनएल बॉन्ड धारकों के पैसे चुकाने में नहीं चूकेगी और इसे चलाने का काम मिनीरत्न कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को दे दिया जाएगा। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बैंकों का बकाया चुकाने के लिए इसकी संपत्तियों से कमाई करने का प्रयास भी चल रहा है। दूरसंचार कंपनी ने पहले बैंकों के सामने प्रस्ताव रखा था कि उसका 60 प्रतिशत कर्ज माफ कर दिया जाए तो वह बाकी 40 प्रतिशत कर्ज चुका देगी। मगर बैंकों को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया।

आम तौर पर पीएसयू को ऋण सुरक्षित माना जाता है। मगर इनमें भुगतान न होने के कई मामले सामने आए हैं और कर्ज निपटाने के फेर में बैंकों को काफी रकम से हाथ भी धोना पड़ा है। निजी बातचीत में बैंकर पीएसयू को कर्ज देने के अपने अनुभव बताने भी लगे हैं। मिनीरत्न पीएसयू स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एसटीसीएल लिमिटेड (पुराना नाम स्पाइस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड) को बंद करने की याचिका एक दशक से भी ज्यादा समय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में लटकी है। मार्च 2023 में एसटीसीएल पर अठत सरकारी और निजी बैंकों के 4,559 करोड़ रुपये बकाया थे। उन्हें वसूलने के मुकदमे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और ऋण वसूली अपील पंचाट (डीआरएटी) के पास पड़े हुए हैं।

केंद्र की मिनीरत्न पीएसयू हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में बैंकों को 65 प्रतिशत बकाये से हाथ धोना पड़ा। यह समझौता ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी के जरिये हुआ, मंत्रालय स्तर की वैसी बातों के जरिये नहीं, जैसी एमटीएनएल और आरआईएनएल के लिए हो रही है।

आरआईएनएल और एमटीएनएल के ऋण निपटान का फैसला बैंकों का समूह नहीं बल्कि सचिवों की समिति ले रही है। आईबीसी कानून है और सही कीमत आंकने के लिए बाजार है। इनकी जगह निजी बातचीत में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बात करने वाले का पलड़ा कितना भारी है। अब अगर सरकार ही बातचीत करेगी तो क्या सरकारी बैंक जमकर मोलभाव कर पाएंगे?

आपका पक्ष

आत्मविश्वास में लौट रही है भारतीय जनता पार्टी

इस बार के लोक सभा चुनावों में अप्रत्याशित नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी दिखने लगी थी। पिछली बार यानी साल 2019 के लोक सभा चुनावों में 303 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और 240 सीटों पर सिमटकर रह गई। हालांकि, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों ने केंद्र में सरकार बनाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद इसी कारण राजनीतिक विश्लेषकों को लगने लगा था कि अब लोगों पर मोदी मैजिक कम होने लगा है और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की आत्मविश्वास में कमी आने लगी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने तो यहां तक कहा था कि लोक सभा चुनावों के नतीजों में भाजपा की कम हुई सीटों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। मगर हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधान सभा के चुनावों में 90 में से 48 सीटें जीतकर भाजपा ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि लोगों में अभी भी पार्टी के प्रति विश्वास और भरोसा बरकरार है। लोक सभा चुनाव के बाद आए एक्जिट पोल में जहां भाजपा को प्रचंड जीत का दावा किया जा रहा था और नतीजा उसके उलट निकला, ठीक वही स्थिति हरियाणा के विधान सभा चुनावों में भी हुई। आखिरी चरण के चुनाव के बाद आए एक्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी और यहां तक की मतगणना के शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस बाजी मारती दिख रही थी, लेकिन दोपहर बाद तक हो गया था कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं।

हरविंदर सिंह, चंडीगढ़

दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुरुवार को पंचकूला के दशहरा मैदान में लोगों का अभिभावदन स्वीकार करते नायब सिंह सैनी

विकसित भारत के लिए संकट व चुनौतियां

समाचार पत्र में प्रकाशित सारगर्भित एवं धरातल पर सत्यता पर आधारित लेख 'भारत के लिए दो बड़े जोखिम एवं दो बड़ी चुनौतियां' वैश्विक दुर्द्धी एवं अशांति के मध्य देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव का सम्यक विश्लेषण करता है। पश्चिम एशिया में कई दशकों से पाकिस्तान, ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और इन देशों द्वारा समर्थित और पोषित कट्टरपंथी एवं संगठनों हमास, हूती, हिजबुल्ला, लश्कर-ए-तैयबा, जैश जैसे दो सौ से अधिक संगठन हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया में शांति की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? दूसरा पक्ष यह है कि यह देश अपने संसाधनों को आतंकवाद को पोषित करने में लगा देते हैं इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो रही हैं, इन देशों में अस्थिरता, युद्धोन्माद, आतंकवाद और विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के लिए हिंसात्मक संघर्ष हो रहे हैं। अमेरिका भले ही अपनी नीतियों से आक्रामकता दिखाता हो परंतु वह बहुत दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में काम करता है। चीन के भले ही कितने मित्र देश हों परंतु चीन किसी का मित्र नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियों में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के तीन दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मॉरिटेनिया के न्वाकशॉट में आयोजित एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की।